प्रभात

इस अंक में .....

★ भाकपा (माओवादी) के गठन पर प्रेस वक्तव्य ... 3
★ 'रेड सन' संपादक का साक्षात्कार ... 5
★ बजट 2004-05 का विश्लेषण ... 7
★ सुलगता मणिपुर ... 16
★ आंध्र सरकार के साथ 'शांति वार्ता' पर ... 20
★ इराकी जनता का बहादुराना प्रतिरोध... 24
★ अबू ग़रेब जेल में अमेरिकियों के अमानवीय कृत्य... 30
★ विलियम हिन्टन को श्रद्धांजलि ... 32
★ उत्तर बस्तर में एम्बुश ... 37

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) दण्डकारण्य स्पेशल ज़ोनल कमेटी का तिमाही मुख-पत्र

वर्ष - 17 | अंक - 3 | जुलाई-सितम्बर 2004 | सहयोग राशि - 10 रुपए

सीपीआई (एम-एल) [पीडब्ल्यू] और एमसीसीआई का विलय सम्पन्न

देशवासियों से नव गठित भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का आह्वान

सशस्त्र कृषि क्रान्तिकारी गुरिल्ला युद्ध को भारत के कोने-कोने में फैला दें !

उदारीकरण, निजीकरण व भूमण्डलीकरण के खिलाफ उठ खड़े हों !!

प्रिय देशवासियो !

आज हमें आप सबको यह सूचित करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि गत 21 सितम्बर 2004 को भारतवर्ष की दो माओवादी कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टियां – सीपीआई (एम-एल)[पीडब्ल्यू] और एमसीसीआई एक ही पार्टी में विलय कर गई हैं। और अखिल भारतीय पैमाने पर एक एकताबद्ध क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी – **भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) [Communist Party of India (Maoist)]** का गठन हुआ है। सचमुच ही यह खबर न सिर्फ देश और दुनिया के तमाम कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी ताकतों के लिए बल्कि भारतवर्ष के मजदूरों, किसानों, छात्र-युवाओं, मध्यमवर्गियों सहित समस्त मेहनतकश शोषित-पीड़ित अवाम और समूचे देश के लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जिसका कि वे लम्बे समय से दिल थामकर इंतजार कर रहे थे।

सचमुच ही भारत के करीब 80 वर्षों के कम्युनिस्ट आन्दोलन के इतिहास के दौरान भारत के सर्वहारा वर्ग और भारतीय जनता को मिलने वाली यह एक बेहद शानदार उपलब्धि है, जो न सिर्फ भारतवर्ष, बल्कि समूचे एशिया और पूरी दुनिया के अगले भविष्य पर एक वजनदार व दूरगामी प्रभाव डालेगी।

यह एकता रातों-रात हासिल नहीं हो गई। 1981 से ही दोनों संगठनों के बीच जारी सौहार्दमूलक व बिरादराना सम्बन्धों का विकास विभिन्न उतारों-चढ़ावों के दौर से जारी था। बीच के कुछ वर्षों में रिश्ते कुछ तनावपूर्ण हुए थे और आपस में झड़पें भी हुई थीं। इस काल को दोनों ने एक "काला अध्याय" ठहराया है और हार्दिक व खुली आत्म-आलोचना करते हुए अपनी-अपनी कमजोरियों को चिन्हित करते हुए उन्हें सुधारने की शपथ ली है। पिछले डेढ़-दो वर्षों के दौरान कई द्वैपाक्षिक बैठकों के जरिए दोनों संगठनों ने अपने राजनीतिक मतभेदों को हल कर लिया और दोनों की बुनियादी लाइनों का, जो मूलतः सही थीं और उनके द्वारा लम्बे समय से लोकयुद्ध के विकास-विस्तार करते जाने के दौरान हासिल समृद्ध अनुभवों का मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद के आलोक में सटीक संश्लेषण किया गया और इस तरह सामने आए पांच बुनियादी दस्तावेज जिनके आधार पर एकताबद्ध पार्टी भारतीय क्रान्ति का मार्गदर्शन करेगी। इस तरह यह एकता एक उसूली एकता है। भारतीय क्रान्ति के दो महान नेता – नक्सलबाड़ी के निर्माता

सूचना

जब हम इस अंक को पूरा करने जा रहे थे, तभी हमें खबर मिली थी कि 21 सितम्बर को भाकपा (मा-ले) [पीपुल्सवार] और एमसीसीआई का विलय सम्पन्न हो चुका है और नई एकीकृत पार्टी **भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)** का गठन हो चुका है। इस मौके पर एकीकृत केन्द्रीय कमेटी की ओर से जारी पर्चा व अखबारी बयान हम इस अंक में पेश कर रहे हैं। पाठकगण ध्यान दें, अब से 'प्रभात' **भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के मुखपत्र** के रूप में छपती रहेगी।

– सम्पादकमण्डल

नई पार्टी – भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के गठन के उपलक्ष्य में 7 से 13 नवम्बर तक व्यापक प्रचार मुहिम को सफल बनाएं !

कॉमरेड चारु मजूमदार और कॉमरेड कनाई चटर्जी समेत अन्यान्य नेताओं ने 70 के दशक से ही संशोधनवाद व संसदीय मार्ग के साथ सुस्पष्ट विभाजन-रेखा खींच दी थी। इस तरह सशस्त्र कृषि क्रान्ति और दीर्घकालीन लोकयुद्ध के मार्ग से साम्राज्यवाद, सामंतवाद और दलाल नौकरशाह पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने तथा इस लड़ाई को विजय तक नेतृत्व देने की पहली गारन्टी के रूप में एकताबद्ध पार्टी के निर्माण का उन्होंने तथा भारतीय क्रान्ति के अनगिनत शहीदों और व्यापक भारतीय अवाम ने जो सपना देखा था उसे इन सबके उत्तराधिकारियों ने पूरा किया है।

सर्वविदित है कि 1967 में ऐतिहासिक नक्सलबाड़ी के महान किसान-उभार के समय अखिर भारतीय पार्टी बनने की सबसे बेहतरीन परिस्थिति पैदा हुई थी, पर पार्टी बनाने की प्रक्रिया व पद्धति के सवाल पर उसी समय कुछ मतभेदों के हल न हो पाने के कारण 1969 में गठित सीपीआई (एम-एल) में कुछ कम्युनिस्ट क्रान्तिकारियों को एकताबद्ध नहीं किया जा सका। स्वभावतः 20 अक्टूबर 1969 को ही गठित हुआ – माओवादी कम्युनिस्ट केन्द्र (एमसीसी)। तभी से भारत के कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी आन्दोलन की ये दोनों धाराएं सशस्त्र कृषि क्रान्ति और दीर्घकालीन लोकयुद्ध की राह पर विभिन्न उतार-चढ़ावों के दौर से गुजरते हुए अलग-अलग बहती और बढ़ती-फैलती रहीं। आज इन दोनों का यह मिलन और एक महाधारा का उद्भव भारत के कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी आन्दोलन के इतिहास में एक ऐसी महान उपलब्धि है जो स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगी।

इतना ही नहीं, इन दोनों पार्टियों के पास एक सुसंगठित छापामार सेना भी है जिसने दुश्मन की नींद हराम कर दी है। उड़ीसा के कोरापुट और झारखण्ड के सारंडा जैसी हमलावर छापामार कार्रवाइयों के लाल आतंक ने दुश्मन को अभी भी थर्राए रखा है। आज वे बहादुर सेनाएं पीजीए (जन छापामार सेना) और पीएलजीए (जनमुक्ति छापामार सेना) भी एक नई एकताबद्ध छापामार फौज – पीएलजीए के रूप में एक ही कमान के अन्दर पुनर्गठित हो गई हैं।

साथ ही दोनों पार्टियों के पास आन्ध्र, झारखण्ड, बिहार, दण्डकारण्य, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में फैले विस्तृत छापामार क्षेत्र भी अब एकाकार होकर कई लाख वर्ग किलोमीटर तक फैल गए हैं जिनमें दसियों करोड़ की आबादी संघर्षरत है। इन क्षेत्रों की जनता ने इलाके के आधार पर सत्ता दखल के मार्ग पर बढ़ते हुए "क्रान्तिकारी किसान कमेटी" और "क्रान्तिकारी जन कमेटी" के रूप में अपनी सत्ता व शासन-व्यवस्था के संगठनों का निर्माण किया है। इस तरह साम्राज्यवाद और उनके पालतू दलाल वर्गों की प्रतिक्रियावादी सत्ता के खिलाफ जनता की यह क्रान्तिकारी सत्ता, जो एक नए जनवादी भारत के भ्रूण है, उभरती व फैलती जा रही है। साथ ही दोनों पार्टियों के नेतृत्व में गोलबन्ध लाखों जनता भी अब एकाकार हो गई है और साम्राज्यवाद-सामन्तवाद-दलाल नौकरशाह पूंजीवाद के खिलाफ जन संघर्षों का एक देशव्यापी उभार लाने को कमर कस रही है।

अतः हम कह सकते हैं कि भारत के क्रान्तिकारी संघर्षों के लम्बे इतिहास में आज हमारी आत्मगत तैयारियों की स्थिति अपेक्षाकृत रूप से कुछ ज्यादा अनुकूल हुई है। पर हमारे समक्ष चुनौतियां भी जोरदार व प्रबल हैं।

पहली बात तो यह है कि कुछ सच्चे कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी ग्रुप और व्यक्ति अभी भी इस नव गठित पार्टी के बाहर रह गए हैं। हमें उनसे एक अत्यन्त सकारात्मक रुख रखकर एकता-वार्ता चलाने और एकताबद्ध होने का भरपूर प्रयास करना होगा और हम करेंगे भी।

आज जब हम देश और दुनिया की परिस्थितियों पर निगाह डालते हैं, तो हमें अपने सामने की चुनौतियों का जबर्दस्त अहसास होता है। आज विश्व साम्राज्यवाद और उसका सरगना अमेरिका आफगानिस्तान और इराक पर नंगा हमला करके उसे अपना उपनिवेश बना चुका है। उसके इस हमलावर तेवर के खिलाफ पूरी दुनिया की उत्पीड़ित जनता सीना तानकर उठ खड़ी हुई है और हो रही है। पूरे यूरोप और अमेरिका में उसके बढ़ते शोषण-उत्पीड़न, हमलों व युद्धनीति के खिलाफ लाखों-लाख जनता, खासकर छात्र-युवा और मजदूर वर्ग जबर्दस्त प्रतिवाद व प्रतिरोध-संघर्षों में उतर पड़े हैं। एशिया, अफ्रीका व लातिनी अमेरिका में भी साम्राज्यवाद और उनके पालतू गुर्गों के खिलाफ उत्पीड़ित जनता का संघर्ष विकराल रूप लेता जा रहा है। उसी रफ्तार से बढ़ते जा रहे हैं उनके बीच के अन्तरविरोध। इसी बीच एशिया साम्राज्यवाद और उनके दलाल वर्गों के खिलाफ क्रान्तिकारी संघर्षों का तूफानी केन्द्र बन गया है जिसकी अगली कतार में खड़े होकर पूरी दुनिया को मुक्ति की रोशनी दिखा रहे हैं नेपाल, फिलिप्पीन्स व भारत के लोकयुद्ध। देश व दुनिया के पैमाने पर माओवादी ताकतें संगठित होती जा रही हैं।

भारतवर्ष को देखें तो यहां एक तरफ विशाल ग्रामीण जनता अभी भी अर्ध सामंती भूमि-सम्बन्धों व साम्राज्यवादी-सामंतवादी शोषण-उत्पीड़न के चलते लगातार भूखमरी का शिकार है। स्थाई बाढ़, सूखा व अकाल का देश बन गया है भारतवर्ष और उसका विस्तीर्ण देहाती क्षेत्र। दूसरी तरफ, साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरण की नीतियों ने पूरे भारत की जनता की दुख-दुर्दशा को चरम पर पहुंचा दिया है। लाखों कल-कारखाने बन्द होते जा रहे हैं, उधर कृषि भी ऊंची लागतों व उपज की अन्यायपूर्ण कीमतों के चलते निरंतर चौपट होती जा रही है और व्यापार-धंधे भी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लगातार विध्वंसक हमलों से तबाह होते जा रहे हैं। बेरोजगारी-महंगाई बेतहाशा बढ़ती जा रही है। इस तरह साम्राज्यवादी-सामंती शोषण-उत्पीड़न ने करोड़ों-करोड़ जनता की जीवन-जीविका को पूरी तरह तबाह कर डाला है और जब भी वे हक व न्यायोचित मांगों के लिए किसी भी आन्दोलन या संघर्षों में उतर रहे हैं तो उनके खिलाफ क्रूरतम व वीभत्स दमन बरपाया जा रहा है। इस मामले में एनडीए की सरकार हो यूपीए की सरकार, चेहरों व तरीकों तथा बोलियों के कुछ मामूली हेर-फेर के सिवाए उपरोक्त जन हत्यारी नीतियों को लागू करने के मामले में उनमें कोई फर्क नहीं आने वाला।

पर इस बढ़ते शोषण-उत्पीड़न ने तबाह जनता के सभी वर्ग व तबके तमाम दमन का सामना करते हुए संघर्ष की राह पर भारी तादाद में उतरते जा रहे हैं। मजदूर, किसान, छात्र-युवा, अन्यान्य मेहनतकश

जनता, महिलाएं, दलित, धार्मिक व राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों से लेकर तमाम शोषित-उत्पीड़ित जनता अपने अब तक के संघर्ष के अनुभवों से अच्छी तरह समझती जा रही है कि वोट-वाट से कुछ होने वाला नहीं है और हथियार उठाकर लड़े बिना उन्हें मामूली से मामूली अधिकार व न्याय भी नहीं मिलेंगे। साथ ही, विभिन्न उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं के संघर्ष भी क्रूरतम फौजी दमन का मुकाबला करते हुए अपने न्यायोचित अधिकारों को हासिल करने की राह पर आगे बढ़ते जा रहे हैं।

इन संघर्षों से घबराकर साम्राज्यवाद और उसके दलाल भारतीय शासक वर्ग भी एक पर एक नई नीतियों व षड़यंत्रों का सहारा ले रहे हैं। कभी गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के पूरे तंत्र का इस्तेमाल कर तरह-तरह के राहत व सुधार-कार्यों के जरिए, तो कभी अन्यान्य सरकारी सुधार-नीतियों के सहारे वे जनता की लड़ाकू मानसिकता को कुंद कर देने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने हिन्दू फासीवादी ताकतों को भी उभारा है और धर्म, सम्प्रदाय, प्रांतीयता व जात-पात आदि के नाम पर भी वे जनता की एकता को तोड़ने की जी-जान से कोशिश कर रहे हैं।

राजनीतिक रूप से आज के युग का प्रधान खतरा है - संशोधनवाद। हमारे देश में सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई (एम-एल) लिबरेशन से लेकर अन्यान्य संशोधनवादी व आधुनिक संशोधनवादी दलों को भी उन्होंने क्रान्तिकारी संघर्षों को गुमराह करने के लिए जोर-शोर से मैदान में उतारा है।

ऐसे में हमारे सामने बहुत ही जबर्दस्त चुनौती आ जाती है कि हम एक तरफ तो शासक वर्ग और उसकी तमाम चुनावी पार्टियों की जन-विरोधी नीतियों तथा संशोधनवादियों की तमाम चालबाजियों को बेनकाब करते हुए लाखों-करोड़ों जनता को अपने बैनर तले गोलबन्द कर जन संघर्षों का एक देशव्यापी सैलाब खड़ा करें तथा दूसरी तरफ, भरपूर ताकत के साथ देशव्यापी सशस्त्र कृषि क्रान्तिकारी गुरिल्ला युद्ध के विकास-विस्तार के जरिए जन फौज को शक्तिशाली करें, छापामार क्षेत्रों को आधार क्षेत्रों में बदल डालें तथा बड़े पूंजीपतियों की प्रतिक्रियावादी सत्ता और उसकी राज मशीनरी को ध्वस्त करते हुए ग्रामांचलों में जनता की अपनी शासन-व्यवस्था को सुदृढ़ व विस्तृत करें। साथ ही हमें लाखों-लाख संगठित जनता और उसके उभार को उपरोक्त छापामार युद्ध की ओर निर्देशित करना होगा। तभी हम भारत के दीर्घकालीन लोकयुद्ध को विजय की दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं।

अतः अन्त में हम भारत के तमाम मजदूरों, किसानों, छात्र-युवाओं, मध्य वर्ग, छोटे दुकानदारों, छोटे उद्योगपतियों व व्यापारियों और शिक्षक, डाक्टर, वकील, इंजीनियर तथा तमाम सचेत बुद्धिजीवियों समेत सभी प्रगतिशील, जनवादी, देशभक्त व न्यायप्रिय लोगों से हार्दिक अपील करते हैं – अपनी इस नव गठित पार्टी के बैनर तले लाखों-लाख की संख्या में गोलबन्द हों, भारत के सशस्त्र कृषि क्रान्तिकारी युद्ध में शामिल हों, इसे भारत के कोने-कोने में फैला दें तथा हर तरीके से इसके विकास-विस्तार व सुदृढ़ीकरण में सहयोग करें, क्रान्तिकारी संघर्षों के भी एक विशाल क्रान्तिकारी जन-उभार का निर्माण करें और इस तरह संसदीय रास्ते व संसदीय पार्टियों को ठोकर मारते हुए दीर्घकालीन लोकयुद्ध के रास्ते भारत की नव जनवादी क्रान्ति को सफल बनाकर एक मुक्त, जनवादी, शोषणहीन व समाजवादी भारतवर्ष के निर्माण के इस महायज्ञ को सफल बनाने के लिए आगे आएं।

क्रान्तिकारी अभिवादन के साथ

28 अक्टूबर 2004

केन्द्रीय कमेटी (अस्थाई)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

प्रेस वक्तव्य

सीपीआई (एम-एल) [पीपुल्स वार] और एमसीसीआई का विलय भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का उदय

14 अक्टूबर 2004

21 सितम्बर 2004 को भारत के एक गुरिल्लाजोन में आयोजित एक आमसभा में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के उदय की घोषणा की गई। उस समारोह में जन छापामार योद्धाओं, पार्टी कार्यकर्ताओं और जन संगठन कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। अब हम यह घोषणा देश और दुनिया की तमाम जनता के नाम कर रहे हैं। भारत का माओवादी कम्युनिस्ट केन्द्र और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) [पीपुल्सवार], दोनों पार्टियों का विलय एक नई एकीकृत पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) में हो गया है। इस एकीकृत पार्टी के गठन से देश के मजदूर-किसानों और तमाम मेहनतकश लोगों की तमन्ना पूरी हो गई जो एक असली सर्वहारा पार्टी को चाह रहे थे। एक ऐसी पार्टी जोकि क्रान्तिकारी बदलाव के जरिए नई जनवादी समाज, और बाद में समाजवाद व साम्यवाद का निर्माण करने में उनका नेतृत्व कर सके।

पहले दोनों पार्टियों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमण्डलों के बीच हुए गहन विचार-विमर्श और उसके बाद दोनों पार्टियों की संयुक्त केन्द्रीय कमेटी बैठक में हुई बहसों का नतीजा ही है इस नई एकीकृत पार्टी का गठन। समान दर्जे पर हुई गहरी और रचनात्मक बहसों के फलस्वरूप हम पांच दस्तावेजों को तैयार करके उन्हें अंतिम रूप देने में कामयाब हो सके। वे पांच दस्तावेज इस प्रकार हैं – मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद के शानदार लाल परचम को ऊंचा उठाए रखेंगे, पार्टी कार्यक्रम, भारत की क्रान्ति की रणनीति-कार्यनीति, अन्तर्राष्ट्रीय व देशीय परिस्थिति पर राजनीतिक प्रस्ताव और पार्टी संविधान। इन

दस्तावेजों के अलावा बैठक ने यह भी फैसला किया कि दोनों पार्टियों के प्यारे नेता और शिक्षक शहीद कॉमरेड चारु मजूमदार और कॉमरेड कनाई चटर्जी को इस एकीकृत पार्टी के संस्थापक नेता माना जाए और ऊंचा उठाया जाए। बैठक ने यह भी तय किया कि '60 के उथल-पुथल भरे दौर में ही, खासकर नक्सलबाड़ी विद्रोह में से ही जन्मी ये दोनों पार्टियां भारत के कम्युनिस्ट आन्दोलन के लम्बे इतिहास के क्रान्तिकारी पहलू के सच्चे वारिस हैं। यह एक अजीब सी स्थिति है कि भारतीय क्रान्ति को आगे बढ़ाने के लक्ष्य से ही कार्यरत ये दोनों पार्टियां पिछले 35 सालों से अलग-अलग धाराओं के रूप में रहीं। लाइन से जुड़े लगभग तमाम सैद्धांतिक व राजनीतिक सवालों पर सांझी समझदारी बनाने के लिए हमने तमाम आवश्यक तरीके अपनाए हैं। यह लाइन ही दोनों पार्टियों के एकताबद्ध होने में उसूली आधार थी। इस एकता के आधार पर संयुक्त केन्द्रीय कमेटी की बैठक ने तय किया कि दोनों पार्टियों का एक सांझी पार्टी में विलय हो। यह सांझी पार्टी अब से **भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)** कहलाएगी। कॉमरेड गणपति को एक मत से इस नई पार्टी के महा सचिव चुन लिया गया।

एकीकृत भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का गठन निश्चित रूप से भारत के क्रान्तिकारी आन्दोलन के इतिहास में एक नया मील का पत्थर साबित होगा। देश के क्रान्तिकारी समर्थक, उत्पीड़ित जनता के साथ-साथ हमारे तमाम कतार और दक्षिण एशिया व दुनिया के माओवादी ताकतें लम्बे अरसे से बेहद उत्सुकता से इस इन्तजार में थीं कि मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद की बुनियाद पर खड़ी एक एकीकृत पार्टी का गठन हो। आज उन तमाम लोगों की बहुप्रतीक्षित आकांक्षाएं और स्वप्न सच में बदल गए।

यह नई पार्टी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) भारत के सर्वहारा के संगठित राजनीतिक अगुवा दस्ते के रूप में बनी रहेगी। मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद इसका सैद्धान्तिक आधार होगा। यही इस पार्टी के चिन्तन और तमाम क्रियाकलापों का मार्गदर्शन करेगा। दक्षिणपंथ और वामपंथ के खिलाफ, खासकर संशोधनवाद, जिससे कि भारत के कम्युनिस्ट आन्दोलन को सबसे ज्यादा खतरा है, के खिलाफ यह पार्टी अपना संघर्ष जारी रखेगी। इस एकीकृत पार्टी के बाहर रह गए तमाम सच्चे माओवादी ग्रुपों और शख्सों को एकताबद्ध करने के लिए हमारी यह नई पार्टी कटिबद्ध रहेगी। इस माओवादी पार्टी का फौरी लक्ष्य और कार्यक्रम यही है कि विश्व सर्वहारा क्रान्ति के तहत हमारे देश में जारी नई जनवादी क्रान्ति को आगे बढ़ाया जाए। अप्रत्यक्ष शासन, शोषण, नियंत्रण जैसे नव औपनिवेशिक तरीकों में जारी इस अर्ध औपनिवेशिक व अर्ध सामन्ती व्यवस्था को उखाड़ फेंकना इस क्रान्ति का अहम हिस्सा है। यह क्रान्ति साम्राज्यवाद, सामन्तवाद और दलाल नौकरशाह पूंजीवाद के खिलाफ जारी रहेगी। सशस्त्र कृषि क्रान्तिकारी युद्ध, यानी दीर्घकालीन लोकयुद्ध के जरिए इस क्रान्ति को अंजाम दिया जाएगा। हथियारबन्द ताकत के जरिए सत्ता को छीन लेना ही इसमें केन्द्रीय व मुख्य कार्यभार होगा। ग्रामीण अंचलों से होते हुए शहरों को घेरकर आखिरकार उन्हें कब्जे में ले लिया जाएगा। इसलिए पार्टी के काम में अहम हिस्सा देहाती इलाकों और दीर्घकालीन लोकयुद्ध का ही होगा। शहरी काम इसके सहायक के रूप में रहेगा। चूंकि हथियारबन्द संघर्ष ही संघर्ष का उन्नत और प्रधान स्वरूप रहेगा और सेना ही इस क्रान्ति में संगठन का प्रधान स्वरूप रहेगा, इसलिए हथियारबन्द संघर्ष की भूमिका ही अहम होगी। हथियारबन्द संघर्ष के दौरान संयुक्त मोर्चे का गठन किया जाएगा। जन संगठन और जन संघर्ष आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य भी हैं बशर्ते कि उनका उद्देश्य युद्ध की सहायता करना होगा।

हम यह भी घोषणा करते हैं कि पीजीए और पीएलजीए का विलय एकीकृत **पीएलजीए (जन मुक्ति छापामार सेना)** में हो गया है। सीपीआई (एम-एल) [पीपुल्सवार] की पीजीए और एमसीसीआई की पीएलजीए, दोनों का ही यह इतिहास रहा है कि उन्होंने मौत की परवाह न करते हुए कई संघर्ष किए और अनमोल बलिदान दिए। इस विलय के जरिए उनकी लड़ाकू ताकत में उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी होगी। इस विलय के बाद पार्टी के बेहद फौरी कार्यभार होंगे – सांझी पीएलजीए को पूर्ण विकसित पीएलए (जन मुक्ति सेना) के रूप में विकसित करना और फिलहाल मौजूद गुरिल्ला जोनों को आधार इलाकों में तब्दील करना। इस तरह, एक के बाद एक उभार पैदा करते हुए नई जनवादी क्रान्ति को सफल बनाना होगा। 2 दिसम्बर पीएलजीए का स्थापना दिवस होगा। तीन केन्द्रीय कमेटी सदस्य कॉमरेड्स श्याम, महेश और मुरली की पहली बरसी के दिन, 2 दिसम्बर 2000 को हमारे देश में पहली बार जन गुरिल्ला सेना ने जन्म लिया है।

इसके अलावा, विभिन्न राजनीतिक सवालों पर, जन समस्याओं पर क्रान्तिकारी जन आन्दोलनों की नई उभार निर्मित करने पर यह नई एकीकृत पार्टी ज्यादा जोर देगी। साम्राज्यवाद, सामन्तवाद और दलाल नौकरशाह पूंजीवाद के खिलाफ चलाए जाने वाले इन संघर्षों में व्यापक जन समुदायों को भागीदार बनाने की कोशिश की जाएगी। हमारे देश में साम्राज्यवाद द्वारा जारी बर्बरतम हमले के फलस्वरूप पहले से कंगाल हो चुके लोग बड़े पैमाने पर तबाह होते जा रहे हैं। विशेष रूप से देहाती इलाकों में हजारों की संख्या में लोग आत्महत्या कर रहे हैं। यह नई पार्टी देश में बढ़ रहे साम्राज्यवादी हमले और राजकीय दमन के खिलाफ जनता के व्यापक तबकों को गोलबन्द करती रहेगी। साम्राज्यवाद और सामन्तवाद के खिलाफ होने वाले तमाम आन्दोलनों के लिए समर्थन जुटाएगी। महिलाओं को क्रान्ति में एक जबर्दस्त शक्ति के रूप में गोलबन्द करने और उन्हें संगठित करने पर यह पार्टी विशेष ध्यान देगी। सभी किस्म के सामाजिक उत्पीड़नों, खासकर छुआछूत और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष करेगी। यह पार्टी हिन्दू फासीवादियों, जोकि काफी खतरनाक हैं, को बेनकाब कर, उन्हें अलग-थलग कर परास्त करेगी। साथ ही, अन्य धार्मिक साम्प्रदायिकतावादी ताकतों को भी बेनकाब करेगी। इसके साथ-साथ, यह सांझी पार्टी दिल्ली में सत्तारूढ़ हुए कांग्रेसी शासकों, माकपा/भाकपा और उनके साम्राज्यवादी आकाओं के खिलाफ जन संघर्ष चलाएगी।

हमारी यह नई पार्टी भारतीय शासक वर्गों के विस्तारवादी नीतियों, उनकी मदद कर रहे साम्राज्यवादी सरदारों, खासकर अमेरिकी साम्राज्यवादियों को बेनकाब करते हुए उनका प्रतिरोध करने की नीति जारी रखेगी। सीपीएन (माओवादी) के नेतृत्व में संघर्षरत नेपाली जनता

(शेष पृष्ठ 10 पर ....)

'रेड सन' के सम्पादकमण्डल सदस्य के साथ साक्षात्कार

[यूरोप के पेरू जन आन्दोलन (एमपीपी) का मुखपत्र है 'रेड सन'। वह पेरू की माओवादी पार्टी (पीसीपी) की रिपोर्टें प्रकाशित करती हैं। पिछले जनवरी माह में 'पीपुल्स मार्च' ने यह साक्षात्कार लिया। – सम्पादक]

सवाल – फिलहाल पेरू के क्रान्तिकारी आन्दोलन के सम्बन्ध में ज्यादा खबरें नहीं आ रही हैं। चेयरमैन गोंजालो की गिरफ्तारी के बाद रास्ते में मोड़ आया है न! अब वहां क्या हाल है?

जवाब – यह किसी भी तरीके से इत्तेफाकिया नहीं है। यह कम तीव्रता के संघर्ष की रणनीति (Low-Intensity Conflict Strategy) का हिस्सा है। पेरू में जारी लोकयुद्ध के बारे में जानकारी हासिल करना काफी मुश्किल है। यह साफ तौर पर साम्राज्यवादियों, खासकर यैंकी (अमेरिकी) साम्राज्यवादियों और उनके भाड़े के टट्टू पेरू के शासक वर्गों द्वारा की जा रही साझी साजिश है। लेकिन वे लोकयुद्ध के बारे में जनता को हमेशा के लिए अंधेरे में नहीं रख सकते। पर अब साम्राज्यवाद एक मुहिम के तौर पर खबरों को दबा रहा है। फिलिस्तीन में कोई घटना होती है तो वह मीडिया में बड़ी खबर बन जाती है। लेकिन अगर क्रान्तिकारी कोई कार्रवाई करते हैं तो मीडिया में कुछ भी नहीं छापा जाता। बदकिस्मती से, कुछ कॉमरेडों ने लोकयुद्ध के बारे में खबरें पहुंचाने की स्थिति में रहकर भी अपने राजनीतिक उद्देश्यों की खातिर यह काम नहीं किया। दरअसल, 1991 से लोकयुद्ध रणनीतिक संतुलन की अवस्था में जारी है। सितम्बर 1992 में रास्ते में मोड़ आया था। इसके फलस्वरूप परिस्थिति में कुछ बदलाव आए हैं। पार्टी, सेना और संयुक्त मोर्चा/नई सत्ता, जो कि क्रान्ति के अहम साधन हैं, ने अस्थाई तौर पर पीछे कदम डाला।

उसी समय, 1993 में पेरू के प्रतिक्रियावादियों, खासकर यैंकी साम्राज्यवादियों के सशस्त्र बलों ने शांति-प्रस्ताव वाले खतों का सिलसिला छेड़ दिया। जेल में रहकर समर्पण का रास्ता अपनाने वाले कुछ गद्दारों, संशोधनवादियों/समर्पणकारियों के गुट से उन्होंने सांठगांठ की। इन संशोधनवादियों ने अपनी लाइन को पार्टी के भीतर प्रस्तुत करने के बजाए खुलेआम सामने लाया।

जब उन्होंने यह काम शुरू किया तब वे जेल में थे। हालांकि इस लाइन और उनकी उम्मीदों को पार्टी ने सुचारू रूप से चलाए गए दो-लाइन संघर्ष के जरिए पूरी तरह से साफ कर दिया। इसलिए लोकयुद्ध पल भर के लिए भी नहीं रुका। दूसरी तरफ, दुश्मन ने इन सालों में नई सत्ता पर अपना हमला जारी रखा। विशेषकर बर्बरतम दमन बरपाया। बड़े पैमाने पर चलाए गए कत्लेआमों के बीच ही नई सत्ता सह गई और टिक गई। लेकिन लोकयुद्ध को हुए नुकसानों के चलते कुछ आधार इलाकों को नहीं टिका सके। ऐसी स्थिति में रास्ते में मोड़ से उबारने के लिए उठाए गए कदमों से क्रान्ति के तीनों साधन प्रभावित हुए। मसलन, हाल की गर्मियों में आयाकुचो में टेचिन्ट कम्पनी पर एक कार्रवाई की गई जिसे लोकयुद्ध में एक महत्वपूर्ण और मुख्य घटना कही जा सकती है। वह एक साम्राज्यवादी कम्पनी थी। एक गैस परियोजना में लगी इस कम्पनी के ढांचों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र पुलिस बल तौनात थे। पीएलए के प्रधान बलों की एक टुकड़ी ने इस पूरे इलाके पर अपना कब्जा जमा लिया। पीएलए के सैनिकों ने वहां मौजूद सभी लोगों को बन्धक बनाकर 24 घण्टों तक अपने कब्जे में रख लिया। वहां के मजदूरों के लिए एक सभा भी आयोजित की। इस बीच बेस एरिया से सन्देश मिलने के बाद वे 12 डम्प डाइनामाइट, संचार उपकरणों, दवाओं आदि को जब्त करके लौट गए।

इर कार्रवाई के बाद प्रतिक्रियावादियों में कंपकंपी पैदा हुई। उस इलाके में सुशिक्षित कमाण्डों को हेलिकॉप्टरों में भेजा गया। लेकिन वे एक कॉमरेड को भी नहीं पकड़ सके। पीएलए ने इन तमाम सुशिक्षित बलों को घेरकर मार डाला। इनमें एक उच्च अधिकारी भी था।

लोकयुद्ध के मजबूत गढ़ों में एक माने जाने वाले हुवानाको इलाके में नई सत्ता के खिलाफ पिछले साल बड़े पैमाने पर सफाया अभियान चलाया गया। अक्टूबर 2003 में सशस्त्र बलों द्वारा शुरू किया गया इस ऑपरेशन का नाम "फियरो (लोहा) 2003" था।

नशीले पदार्थों के खिलाफ युद्ध के नाम पर चलाए गए इस प्रति-क्रान्तिकारी अभियान का नेतृत्व यैंकी साम्राज्यवाद ने किया। यहां एक बात गौरतलब है। यैंकी साम्राज्यवाद अभी भी नशीले पदार्थों के खिलाफ युद्ध को नकाब की तरह इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि वह मार्क्सवादी-लेनिनवादी-माओवादी पार्टियों के नेतृत्व में जारी साम्राज्यवाद-विरोधी आन्दोलन से काफी भयभीत हो रहा है। वह जी-तोड़ कोशिश कर रहा है ताकि दुनिया की जनता पेरू में जारी लोकयुद्ध के शानदार रोशनी के बारे में कुछ भी न जान सके।

इस अभियान में उन्होंने हेलिकॉप्टर गनशिपों का इस्तेमाल किया। उनकी मदद से जमीन पर बलों को आगे बढ़ाया। लेकिन पार्टी ने सक्रिय आत्मरक्षा को अपनाते हुए एक जवाबी अभियान की योजना तैयार की। कई घात हमले किए। दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा दिए। पार्टी ने अपने जवाबी अभियान में कामयाबी हासिल की।

जहां तक शहरों का सवाल है, शुरू में शहरों में काम करना काफी आसान था। लेकिन रास्ते में मोड़ आने के बाद वहां भीषण दमन का सिलसिला जारी है। मसलन, आपको एक नारा लिखने के जुर्म में भी जेल में बन्द किया जा सकता है या फिर यातनाएं भी दी जा सकती हैं। अब तो मार भी रहे हैं। जन आन्दोलनों के नेताओं पर कई हमले हुए हैं। इसलिए इस नई परिस्थिति में पार्टी ज्यादा गोपनीय ढंग से जनदिशा को कार्यान्वित कर रही है। मसलन, हाल में हुई शिक्षकों की हड़ताल के साथ-साथ मजदूरों, चिकित्सा कर्मियों, किसानों और अन्य तबकों द्वारा जारी विभिन्न संघर्षों का पार्टी ने कई तरीकों में नेतृत्व किया।

सवाल – पीसीपी (पेरू कम्युनिस्ट पार्टी) और रिम (रिवल्यूशनरी इंटरनेशनलिस्ट मूव्हमेन्ट) के बीच सम्बन्ध किस प्रकार हैं?

जवाब – पीसीपी को रिम में सदस्यता प्राप्त है। पीसीपी का मानना है कि जब तक रिम सही सैद्धान्तिक व राजनीतिक लाइन पर चलेगा तब तक वह दुनिया भर के कम्युनिस्टों को दोबारा एकताबद्ध करने की दिशा में एक आगे कदम है। रिम में, खास कर कुछ कमेटी सदस्यों में

दक्षिणपंथी अवसरवादी कार्यदिशा से मेल खाने वाले संशोधनवादी विचारों की अभिव्यक्तियां देखी गईं। हम इन विचारों के खिलाफ दो-लाइन संघर्ष को विकसित कर रहे हैं। हम कुछ लोगों द्वारा किए जा रहे इस प्रचार का साफ तौर पर खण्डन करते हैं कि हम रिम के खिलाफ हैं। वह गलत है। झूठ है। हम मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद के आधार पर, मुख्य रूप से माओवाद के आधार पर एकता और संशोधनवाद के खिलाफ दोषरहित संघर्ष चाह रहे हैं। इस प्रकार हम विश्व सर्वहारा क्रान्ति में भागीदारी ले रहे हैं। 17 मई 1980 को जब लोकयुद्ध की शुरूआत की गई, तभी से हमारी पार्टी लगातार जोर देकर कहती आ रही है कि हम विश्व सर्वहारा क्रान्ति के तहत ही लोकयुद्ध को विकसित कर रहे हैं। इसलिए हम दो-लाइन संघर्ष विकसित करेंगे। जैसे कि चेयरमैन माओ ने बताया, वह बुरा नहीं है, बल्कि अच्छा ही है।

सवाल – क्या जेल में बन्द चेयरमैन गोंजालो के साथ कोई सम्बन्ध साधा जा रहा है? क्या आप बताएंगे कि फिलहाल उनकी तबियत कैसी है?

जवाब – 1992 से चेयरमैन गोंजालो को पूरी तरह एकांत में कैद कर रखा गया है। पहरा देने वाले गारदों के सिवाए उन्हें कोई नहीं मिल सकता। सचाई यही है। अगर कोई यह कहता है कि उसने चेयरमैन गोंजालो को देखा है या बात की है तो वह या तो प्रतिक्रियावादी सरकार का सदस्य होगा या फिर उसका विरोधी होने का दंभ भरने वाला धोखेबाज होगा। 24 सितम्बर 1992 को उनके ऐतिहासिक भाषण के बाद उनसे आज तक किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं हो सकी। उस दिन के भाषण में उन्होंने हमसे आग्रह किया था कि पार्टी के कार्यभारों और योजनाओं को पूरा किया जाए और लोकयुद्ध को जारी रखा जाए। उनसे बैठक करने इत्यादि नाना प्रकार के जो नकली वीडियो दिखाए जा रहे हैं वे सब शांति समझौते के कपटपूर्ण नाटक का हिस्सा ही हैं। पार्टी ने एक न्यायोचित और वाजिब मांग उठाई – चेयरमैन गोंजालो को राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय टेलिविजन मीडिया के सामने पेश किया जाए और उन्हें खुलकर बोलने का मौका देकर उसका सीधा प्रसारण किया जाए। इससे वह अपने एकांत कारावास से मुक्त हो सकेंगे। लेकिन दुश्मन यह मांग मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि वह जानता है कि अगर ऐसा होगा तो वह विश्व जनता और विश्व क्रान्ति की कामयाबी होगी। उसे डर है कि ऐसा करने से जनता गोंजालो के विचारों को अपना लेगी। यही वजह है कि वह उन्हें पांच मिनट के लिए भी बोलने का मौका नहीं दे रहा है। अब वे कह रहे हैं कि उन पर एक नया मुकदमा चलाएंगे। यह एक और नाटक के अलावा कुछ भी नहीं है। वे कहते हैं कि गोंजालो बोलने से इनकार कर रहे हैं। वह क्यों इनकार करेंगे? यह सब एक छलपूर्ण नाटक है। चेयरमैन गोंजालो की हालत यह है कि उनकी जान अब पहले के मुकाबले ज्यादा खतरे में है। गिरफ्तारी से पहले ही वह सख्त बीमार थे। 1993 में खुद फुजीमोरी ने ही कहा था कि उन्हें जैसे हालात में रखा गया है वहां कोई भी आदमी ज्यादा दिन जिन्दा नहीं रह सकेगा। यह दस साल पहले की बात थी। तब से उन्हें कोई नहीं देखा। हमें इसकी बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। चेयरमैन गोंजालो की जान बचाने के लिए विश्व जनता को आगे आना चाहिए। वह एक महान क्रान्तिकारी नेता हैं। इस धरती पर जीवित सर्वोत्तम मार्क्सवादी-लेनिनवादी हैं वह। यहां ध्यान दें कि गोंजालो की जान को बचाने का आन्दोलन कभी-कभार चलने वाला आन्दोलन नहीं है, बल्कि वह कम्युनिस्ट आन्दोलन का रणनीतिक कार्यभार है। ★

चेयरमैन गोंजालो के एकांत कारावास के खिलाफ न्यायमूर्ति का फैसला

लिमा (पेरू की राजधानी) के एक न्यायमूर्ति ने फैसला सुनाया कि चेयरमैन गोंजालो (असली नाम अभिमेल गुजमन) को दूसरे बन्दियों की तरह सभी अधिकार दिए जाएं। उन्होंने अपने फैसले में यह भी कहा कि बिना किसी पाबन्दी और शर्त के उनसे मुलाकात करने का मौका दिया जाए। पेरू कम्युनिस्ट पार्टी (पीसीपी) का नेता कॉमरेड गोंजालो एक नए नियम के खिलाफ 35 दिनों तक भूख हड़ताल की जिसके तहत उन्हें अपने वकील समेत किसी भी व्यक्ति से मिलने से वंचित किया जाता है। चेयरमैन गोंजालो द्वारा दायर बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति ने इस नियम को अवैध करार दिया। अखबारों में छपी खबरों के मुताबिक, न्यायमूर्ति ने चेयरमैन गोंजालो के एकांत कारावास को भी गैर-कानूनी घोषित किया। उन्होंने अपने फैसले में बताया कि उन्हें दूसरे कैदियों की तरह न देखते हुए आम नागरिक जेल के बजाए वायुसेना के अड्डे के भीतर एक विशेष कालकोठरी में रखने में कोई वैधानिक औचित्य नहीं है। इस पर अपील करने का मन बना चुके वायुसेना के अधिकारी अभी भी न्यायमूर्ति के फैसले को लागू करने से इनकार कर रहे हैं। फिलहाल पीसीपी नेता की वकालत कर रहे मैनुएल फजार्डो ने इसी न्यायमूर्ति के समक्ष एक और याचिका दायर की जिसमें उन्होंने यह मांग की कि इस फैसले को फौरन लागू करने के आदेश जारी किए जाएं। 1992 से चेयरमैन गोंजालो को एकांत में रखा गया है। 1980 से शुरू किए गए लोकयुद्ध का नेतृत्व करने के लिए उन्हें "देशद्रोह" के मामले में दोषी करार दिया गया था। हालांकि बाद में उस फैसले को गैर-कानूनी घोषित किया गया। तबसे चेयरमैन गोंजालो, दूसरे पीसीपी नेता और सदस्य एक नए मुकदमे के इंतजार में हैं।

[ए वरल्ड टु विन न्यूस सर्वीस (14 जून 2004) से साभार]

गरीबों को खोखले वादे – अमीरों को ढेरों तोफे

'मानवीय' परदे की आड़ में 'आर्थिक सुधारों' का अंबार

यह बात सभी को मालूम है कि भाकपा/माकपा के समर्थन से गद्दीनशीन हुई संप्रग (संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन) सरकार ने मानवीय चेहरे वाले आर्थिक सुधारों को लागू करने की घोषणा की है। इन्होंने 'मानवीय चेहरा' इसलिए सामने लाया ताकि आर्थिक सुधारों के खिलाफ वोट डालने वाले लोगों को धोखे में रखा जा सके। भाकपा/माकपा को संतुष्ट करने के लिए भी सरकार को यह जरूरी हो गया। अगर गरीबों के अनुकूल दिखने वाले शब्द नहीं होंगे तो संशोधनवादी नेतृत्व को अपने कतारों के सामने और ज्यादा नंगा होने का खतरा है।

यही वजह है कि ज्यों ही सरकार ने वर्ष 2004-05 का बजट पेश किया, सहज ही, माकपा-अनुकूल अखबारों ने इसे गरीबों का बजट, किसानों के अनुकूल बजट आदि कहकर तारीफ के पुल बांधे। इसी प्रकार बड़े पूंजीवादी वर्गों ने भी इस बजट पर संतोष जताया। हालांकि कुछ शेयर दलालों को इससे संतुष्टि नहीं मिली क्योंकि शेयरों के तमाम लेन-देनों पर 0.15 फीसदी कर लगाने से वे नाराज थे।

अतीत में भाजपा द्वारा पेश किए गए बजटों और वर्तमान बजट में सिर्फ एक ही फर्क है – जहां भाजपा ने 'आर्थिक सुधारों' को भौंड़े और सीधे रूप से लागू किया था, तो वहीं कांग्रेस/माकपा गठजोड़ इस मामले में कुटिलता और चालबाजी का प्रदर्शन कर रहा है। सभी बजटों का एक ही मतलब यह है कि बड़े पूंजीपतियों को बड़े पैमाने पर रियायतें देना और विदेशी पूंजी के प्रवेश के लिए दरवाजे और ज्यादा खोल देना तथा गरीबों पर और ज्यादा कर लगाना। इसके फलस्वरूप गरीबों की जिन्दगी और ज्यादा तबाह होगी तथा अमीर और ज्यादा मुटाएंगे।

साम्राज्यवादी लूट को और ज्यादा छूट

अर्थव्यवस्था के दूरसंचार, उड्डयन, बीमा आदि क्षेत्रों को साम्राज्यवादी लूट के लिए खुला करके कांग्रेस सरकार ने भाजपा से भी बड़ा दुस्साहस किया है। सत्ता में आते ही उसने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में विदेशी पूंजी के लिए दरवाजे खोल दिए। मौजूदा बजट में उसने अविश्वसनीय लगने वाले ऐसे फैसले लिए जिनसे देशवासियों की सम्पत्तियों को लूटना विदेशी डकैतों को और आसान हो जाए। बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी की सीमा 26% से 49% तक बढ़ाई गई। याद रहे, पूर्व में विदेशी बैंकरों के दबाव में भाजपा सरकार ने जब बीमा क्षेत्र में विदेशी पूंजी के प्रवेश की इजाजत दी थी तो बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया था। साम्राज्यवादी डकैत कई सालों से यह मांग करते आ रहे हैं कि उनकी पूंजी को और ज्यादा बढ़ाने का मौका दिया जाए। अब कांग्रेस ने अपने पहले ही बजट में उनकी मांग इस प्रकार पूरी कर दी।

बात यहीं खत्म नहीं हुई, नागरिक उड्डयन क्षेत्र में विदेशी पूंजी की सीमा को 40% से 49% तक और दूरसंचार क्षेत्र में 49% से 74% तक बढ़ा दी। इसके अलावा विदेशी सट्टा पूंजी (विदेशी संस्थागत पूंजी – एफआईआई) को भारी-भरकम रियायतें घोषित कीं। ऋण के कोषों में एफआईआई पर हदबन्दी को 1 अरब डॉलरों से 1.75 अरब डॉलरों तक बढ़ाया। देश में एफआईआई के प्रवेश पर पहले मौजूद पाबंदियों में ज्यादातर को वापिस लिया। अब बिना किसी इजाजत के ही, और बिना किसी रोक-टोक के सट्टा पूंजी देश में खुलेआम प्रवेश कर सकती है। यह बात सभी को मालूम है कि वह यही सट्टा पूंजी है जिसने ने दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं को बुरी तरह तबाह कर रखा है। 1997 में दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों में उत्पन्न संकट इसका अच्छा उदाहरण है। फिर भी कांग्रेस-नीत सरकार इसे पूरी छूट दे रही है। पिछले साल इस सट्टा पूंजी का देश में काफी बहाव हुआ था। अब इसमें बेतहाशा बढ़ोत्तरी होगी जिससे देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा जाएगी।

भाकपा/माकपा पार्टियों ने हमेशा की तरह इसका भी विरोध करने का घिसा-पिटा राग आलापा। इस सचाई को कोई भी नकार नहीं सकता कि कांग्रेस ने बजट प्रस्तावों के बारे में संशोधनवादियों को पहले ही पूरी जानकारी दी होगी। तो फिर इनके 'महान' न्यूनतम साझा कार्यक्रम (सीएमपी) का क्या हश्र हुआ होगा?

ग्रामीण अनुकूल बजट होने का ढोंग

भाजपा के भारत उदय के नारे को ग्रामीण भारत ने पूरी तरह से नकार दिया था। दरअसल इंदिरा गांधी के 'गरीबी हटाओ' के नारे की तरह यह भी एक मजाक बन गया था। तबसे ग्रामीण इलाकों से आत्महत्याओं की खबरें लगातार आ रही हैं। अब तो महाराष्ट्र के मेलघाट इलाके से भुखमरी की खबरें भी लगातार आ रही हैं। विशेषकर 'भूमण्डलीकरण' और आर्थिक सुधारों के युग में जहां हाइटेक, इन्फोटेक तथा आईसीई (इन्फोटेक, कम्यूनिकेशन्स और एन्टरटेनमेन्ट) को तवज्जो दी जा रही है, वहीं ग्रामीण इलाकों स्थिति बद से बदतर होती जा रही है।

इसलिए, वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण को सीएमपी और कृषि क्षेत्र से शुरू किया ताकि जनता को बेवकूफ बनाया जा सके। मीडिया में इस बजट के बारे में यह प्रचार किया गया कि इसमें मुख्य रूप से ग्रामीण विकास पर ज्यादा जोर दिया गया है।

हालांकि मौजूदा संकट के चलते ग्रामीण इलाकों में अत्यधिक लोगों की जिन्दगी तबाह हो चुकी है, फिर भी खेतिहर मजदूरों और गरीब व मध्यम किसानों की स्थिति तो और भी बदतर हो चुकी है। अब यह देखें कि क्या इन तबकों की जनता के लिए इस बजट ने कोई राहत पहुंचाई भी या नहीं।

सीएमपी में यह घोषणा की गई थी कि गरीब तबकों को रोजगार

उपलब्ध कराना ही उसका मुख्य लक्ष्य है। इस पर नजर डालें कि इस बजट में इसके लिए क्या-क्या कदम उठाए गए! इसमें कहा गया है कि सरकार भविष्य में किसी एक दिन राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी विधेयक घोषित करेगी। (इस प्रकार, बकौल सरकार के, वह प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को 100 दिन काम उपलब्ध कराएगी। यह किसी भी आदमी की समझ से परे है कि सरकार यह कैसे सोच रही होगी कि परिवार के एक भी व्यक्ति को अगर सौ दिन काम नहीं मिल रहा है तो उनके घरों में चूल्हे कैसे जल रहे होंगे!!) इस घोषणा के उलट अब इस बजट में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई), जिसके तहत पिछले साल 76.3 करोड़ दिन रोजगार उपलब्ध करवाया गया था, में सरकार ने भारी कटौती करते हुए उसके आवंटन को 9,640 करोड़ से 4,590 करोड़ तक घटा दिया। यानी आधी से ज्यादा कटौती! एसजीआरवाई जैसी लचर योजना में भी अधी से ज्यादा सेंध मारने वाली सरकार को आखिर क्या ग्रामीण रोजगार के सवाल पर रत्ती भर चिन्ता भी है? एसजीआरवाई में 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कटौती से ही यह साफ हो जाता है कि सरकार इस मामले में कितनी ईमानदार है।

सरकार ने यह भी घोषणा की कि वह 150 सबसे पिछड़े जिलों में 'काम के बदले अनाज' योजना लागू करेगी। लेकिन इसके लिए जरूरी आवंटन उसने कुछ नहीं किया। उसका कहना है कि एसजीआरवाई इत्यादि योजनाओं से इसके लिए आवश्यक धन जुटाया जाएगा। यानी इसके लागू होने का मतलब है दूसरी कल्याणकारी योजनाओं में भारी-भरकम कटौतियां अवश्यंभावी है!

इस बजट में अन्त्योदय अन्न योजना (इसके तहत लोगों को चावल और गेंहू सस्ते दामों पर बेचा जाता है) का दायरा डेढ़ करोड़ परिवारों से दो करोड़ तक बढ़ाने की घोषणा भी की गई। लेकिन इसके लिए भी धन आवंटित किए बिना ही सरकार ने यह कह दिया कि खाद्य सब्सिडी से इस पर खर्च किया जाएगा। यानी मौजूदा खाद्य सब्सिडी से ठीक 3,700 करोड़ रुपए की कटौती करके अन्त्योदय योजना का दायरा बढ़ाया जाएगा। इससे गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अन्य गरीब तबकों के लोगों को उपलब्ध खाद्य सब्सिडी अब समाप्त हो जाएगा। दूसरे शब्दों में इसके लिए आवंटन का मतलब सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भारी-भरकम कटौती है !

बड़ी-बड़ी बातों के बावजूद कृषि क्षेत्र को आवंटनों में ठोस बढ़ोत्तरी तो कुछ भी नहीं हुई। सरकार ने मुख्य रूप से व्यापारीकरण पर ही जोर दिया। यह कहना गलत नहीं होगा कि यह जनता के लिए नहीं, बल्कि मन्सॉन्टो कम्पनी के लिए बनाया गया बजट है। चूंकि कृषि मंत्री शरद पवार मन्सॉन्टो कम्पनी के दलाल के रूप में काम कर रहा है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं है। (अब मन्सॉन्टो को बिक चुकी महाराष्ट्र स्थित महीको कम्पनी हमारे देश में अनुवांशिक तौर पर परिवर्तित बीजों को फैलाने में सबसे आगे है।) ग्राणीण क्षेत्र में सिर्फ कृषि अनुसंधान पर ही आवंटन बढ़ाया गया। इससे भी उपरोक्त सचाई साबित हो जाती है। इस मद में 225 करोड़ रुपए से 1,000 करोड़ रुपए तक, यानी 300% आवंटन बढ़ाया गया। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि इसका मोटा हिस्सा आनुवांशिक तौर पर परिवर्तित फसलों के अनुसंधान पर ही खर्चा जाएगा। हाल के दिनों में अनुसंधान मुख्य रूप से सिर्फ इसी काम में हो रहे हैं।

सिंचाई व्यवस्था के लिए पिछले साल की तरह नाम मात्र का आवंटन ही किया गया। साख और कृषि वाणिज्य पर मुख्य रूप से जोर दिया गया। दरअसल बजट की घोषणा से एक दिन पूर्व जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को ही समाप्त करने की पेशकश थी। उसमें कहा गया था कि इस प्रकार आखिर गेंहू, धान जैसे अनाजों के दामों को भी अरजाकतापूर्ण बाजारू शक्तियों के रहमोकरम पर छोड़ दिया जाए। दरअसल डब्ल्यूटीओ भी कई सालों से यही मांग उठाता आ रहा है। डब्ल्यूटीओ की यह मांग है कि खाद्य अनाजों के उत्पादन से नगदी फसलों की ओर रुख किया जाए। इसका निहित अर्थ यह है कि अगर खाद्य अनाजों की कमी होगी तो अमेरिका के विशालकाय भण्डारों से आयात कर लिया जाए और नगदी फसलों का प्रसंस्करण करके सस्ते दामों पर साम्राज्यवादियों को निर्यातित किया जाए। कृषि क्षेत्र को साख की सुविधा को संगठित करने पर और कृषि सम्बन्धी गतिविधियों को चौतरफा फैलाने पर इस बजट में जोर दिया गया। कृषि पर खर्च में बेहद कम वृद्धि करते हुए 1,081 करोड़ से 1,784 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया। कृषि साख को संगठित करने का मतलब है धनी किसानों की मदद करते हुए बाकी लोगों को सूदखोरों के पास भिजवा देना। फिलहाल ग्रामीण साख में बड़ा हिस्सा इन्हीं के हाथों में है। जबकि कर्ज के बोझ से दबकर ही हजारों किसान आत्महत्या कर रहे हों, इस बजट में इस पर एक बात भी नहीं कही गई। नाबार्ड जैसे बैंक सहज ही मुनाफे की दृष्टि से ही कर्ज देंगे। जिन लोगों से वापिस मिलने की उम्मीद होगी उन्हीं लोगों को वे कर्ज देते हैं। ब्याज की दरों में कमी पर इस बजट में एक शब्द भी नहीं कहा गया। (एक किसान को देय कर्ज के मुकाबले एक कार खरीदने वाले को देय कर्ज पर ब्याज काफी कम है!) इस बजट में कृषि और पशुधन के लिए बीमा का प्रस्ताव है। पर इस योजना से भी धनी किसान ही फायदा उठा सकेंगे। साथ ही, वर्षा के अभाव में या समर्थन मूल्य के अभाव में फसल चौपट होने की स्थिति में बीमा की सुविधा के बारे में इस बजट में कुछ भी नहीं कहा गया है।

कृषि उपजों के मूल्यों में गिरावट और कृषि कारकों के दामों में निरंतर वृद्धि – किसानों की इन दो वर्तमान अहम समस्याओं को हल करने के लिए सरकार कतई तैयार नहीं है। अध्ययनों के मुताबिक यह बात उभरकर सामने आ रही है कि पिछले पांच सालों से कृषि से आमदनी में बड़े पैमाने पर गिरावट हो रही है। उदाहरण के लिए, पश्चिम बंगाल में धान उगाने वाले किसानों की आमदनियों में 1996/97 से 2003/04 के बीच 28% गिरावट आई। गन्ना किसानों की आमदनी में उत्तरप्रदेश में 32% और महाराष्ट्र में 40% गिरावट हुई। जहां उत्तरी भारत में किसानों की औसत आमदनी में 10% गिरावट आई, वहीं कृषि कारकों की कीमतें सालाना 7% की दर से, यानी पांच सालों में 35% बढ़ गईं। किसानों के इस गंभीर मसले का हल करने के लिए इस बजट में कोई उपाय नहीं है। विकसित देशों में भारी सरकारी सब्सिडियों के सहारे इस संकट का समाधान किया जा रहा है। लेकिन यहां की सरकारें डब्ल्यूटीओ के सामने घुटने टेककर किसानों को मिल रही

न्यूनतम सब्सिडियों में भी सेंध मारने की कोशिश करते हुए उन्हें घोर गरीबी के गर्त में धकेल रही हैं।

जहां एक तरफ अनाज के ढेर लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ एक जून की रोटी का जुगाड़ करने के लिए किसानों की जेब में पैसा नहीं है – यह हकीकत ही इस बात का सबूत है कि किसान घोरतम गरीबी में डूबे हुए हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लगभग रद्द करके उसके दामों को बाजर के दामों के बराबर करने की वजह से यह बदहाली छाई हुई है। भुखमरियों का कारण बन रही इस मुख्य समस्या को इस बजट में पूरी तरह नजरअन्दाज किया गया। वर्ष 2001/02 से 2003/04 के बीच खाद्य अनाजों का उपभोग 1,58,621 करोड़ से 1,24,560 करोड़ रुपए तक, यानी 34,000 करोड़ रुपए घट चुका है। हमारे देश में साग-सब्जियों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 780 ग्राम है, जबकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए 90 ग्राम काफी है। पर कड़वी सचाई यह है कि भारतवासी रोजाना औसतन 40 ग्राम साग-सब्जियां ही खरीद नहीं पा रहा है। इन तथ्यों से समझा जा सकता है कि यह समस्या कितना विकराल रूप धारण कर चुका है।

इस बजट में "विभिन्न कार्यक्रमों को अन्तिम स्वरूप देने के बाद पैसे आवंटित करने के लिए" योजना आयोग को 10,000 करोड़ रुपए आवंटित करना भी एक और छलावा है। अगर सरकार वाकई विभिन्न कार्यक्रमों में खर्च करने लिए प्रतिबद्ध है तो उन योजनाओं का जिक्र भी इसी बजट में करना चाहिए था। जनता को ठगने का यह एक और नायाब तरीका भर है। विश्व बैंक की कठपुतली (मेन्टेक सिंह अहलूवालिया) की मुट्ठी में बन्द योजना आयोग को अनिश्चितता से आवंटित इन 10,000 करोड़ रुपए से गरीबों की कोई जरूरत पूरी नहीं हो सकेगी, इसका अंदाजा लगाना कठिन नहीं है।

दरअसल यह बजट बातों में ही कृषि के अनुकूल है, पर ठोस रूप से किए आवंटनों की दृष्टि से तो कतई नहीं। अब इस क्षेत्र में जितने भी आवंटन किए गए, वे मुख्य रूप से ग्रामीण आबादी में 5 प्रतिशत रहने वाले संपन्न किसानों को ही फायदा पहुंचाएंगे। सरकार का इरादा यही है कि इसके जरिए कृषि का और ज्यादा व्यापारीकरण करके उसे साम्राज्यवादियों और बड़े पूंजीपतियों के बाजार के अनुकूल ढाला जाए। अन्त्योदय योजना का दायरा बढ़ाने के एक मात्र प्रस्ताव को छोड़ दें (यह अभी तक साफ नहीं है कि अन्त्योदय परिवारों को पहचानने के किसी तंत्र के बिना ही इस योजना पर अमल कैसे हो पाएगा), तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खर्च को घटाना, कृषि और सिंचाई पर खर्च को घटाना, सूदखोरों की भूमिका को नजरअन्दाज करना, एसजीआरवाई में भारी कटौती करना, कृषि उपजों पर आयात शुल्क कम करना, साख पर ब्याज की दरें न घटाना आदि सारे प्रावधानों से यह बजट 80 प्रतिशत ग्रामीण गरीबों को निश्चित रूप से और ज्यादा गरीबी में ही धकेल देगा।

करों में कटौती और दिखावटी सामाजिक कल्याण

इस बजट में कर अदायगी की सीमा को 50,000 से 1 लाख रुपए तक बढ़ाने को लेकर खूब प्रचार हुआ। यह सिर्फ मध्यम वर्गीय लोगों को आकर्षित करने की चालबाजी के अलावा कुछ भी नहीं है। दरअसल इससे मध्यम वर्गियों को ज्यादा कुछ हासिल तो नहीं हुआ, पर एक लाख से थोड़ा ज्यादा कमाने वालों को अब पहले के मुकाबले ज्यादा कर चुकाना पड़ेगा।

इसी प्रकार सामाजिक कल्याण पर खर्च बढ़ाने के बारे में भी खूब ढिंढ़ोरा पीटा गया। चिकित्सा के मामले में सरकारी अस्पतालों में लागू किए गए 'यूज़र चार्जों' को कम करना, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को बढ़ाना, गरीबों के लिए मुश्किलों का सबब बनी दवाओं की कीमतों को कम करने की कोशिश करना, इत्यादि कोई कदम इस बजट में नहीं उठाए गए। भाजपा द्वारा पेश की गई स्वास्थ्य बीमा योजना का ही इसमें जिक्र किया गया है। इस योजना का लाभ काफी कम लोगों को ही मिलेगा। सिर्फ 11 हजार लोग ही इसमें शामिल हुए हैं। फिलहाल मजदूरों के लिए लागू ईएसआईएस जैसी बीमा योजनाओं के अमल का ढंग कैसा है, यह सभी जानते हैं। इसलिए ज्यादातर लोग इसमें शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। ईएसआईएस योजना इतनी भ्रष्ट बन चुकी है कि ज्यादातर मजदूरों को बीमा राशि का भुगतान करने के बावजूद निजी इलाज करवाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इसके अलावा, 1 जनवरी 2005 से सरकार नया पेटेन्ट कानून लागू करने की तैयारियां कर रही है। इससे पहले ही महंगी हुई दवाओं की कीमतों का आसमान छू लेना तय है। बजट में साफ तौर पर बताया गया है कि स्वास्थ्य पर बढ़ाए खर्च का बड़ा हिस्सा पोलियो अभियान में जाएगा।

शिक्षा क्षेत्र पर नजर डाली जाए तो हर तरफ निजीकरण का ही बोलबाला दिखाई दे रहा है। इस बजट में शिक्षा के लिए 4,000 करोड़ अतिरिक्त धन जुटाने के लिए 2% सेस (अधिभार) लगाने की घोषणा की गई है। आखिर क्यों सरकार सामान्य तरीके से धन आवंटित करके खर्च करने के बजाए इस तरह जनता से वसूलना चाह रही है? पुलिस पर खर्च में 1,609 करोड़ रुपए (पिछले साल के 8,331 करोड़ रुपए की तुलना में इस बार 9,940 करोड़ रुपए आवंटित किए गए) की एकाएक बढ़ोत्तरी कर सकने वाली सरकार ने शिक्षा के लिए और धन आवंटित क्यों नहीं किया? दरअसल पूर्व में मध्याह्न भोजन की योजना के लिए जो खर्च किया जाता था उसे भी अब इस नए अधिभार से ही जुटाया जाएगा। और जहां तक सरकार द्वारा की गई 500 आईटीआई की स्थापना की घोषणा का सवाल है, इसका उद्देश्य बड़े पूंजीपतियों और साम्राज्यवादियों के लिए आवश्यक श्रमिकों को तैयार करना ही है।

छोटे उद्योग का क्षेत्र भी इस बजट के हमले से बच नहीं सका। छोटे उद्योग के दायरे से 85 किस्मों को घटाकर उनकी मौजूदा संख्या को 570 से 485 कर दिया गया। आर्थिक सर्वेक्षण में इससे भी आगे जाकर छोटे उद्योग के क्षेत्र को आरक्षण को ही समाप्त करने का प्रस्ताव रखा गया।

हथियार व्यापारियों को मुनाफे ही मुनाफे !

रक्षा बजट में इस बार जितनी बढ़ोत्तरी की गई उतनी आज तक एक मुश्त कभी नहीं की गई। पिछले साल 60,300 करोड़ रुपए रहे रक्षा बजट को इस बार 28% बढ़ाते हुए 77,000 करोड़ रुपए कर दिए गए। इससे भारत की विस्तारवादी सैन्य रणनीति का आभास मिल

जाता है। जबकि एक तरफ पाकिस्तान के साथ शांति प्रक्रिया जारी ही है, तो इसमें इतनी बढ़ोत्तरी नहीं होनी चाहिए थी। इससे यह समझा जा सकता है कि भारत अपने पड़ोसी देशों के प्रति विस्तारवादी नीतियों को व्यापक स्तर पर लागू करने जा रहा है और अमेरिका के रणनीतिक साझीदार के तौर पर बने रहेगा। यह भी स्पष्ट है कि मलक्का जलडमरूमध्य और हिन्द महासागर के इलाके में अमेरिका की ओर से पुलिसिया भूमिका अदा करने में भारत की सेना का और ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। इससे यह भी समझा जा सकता है कि शासक वर्गों की यह मंशा है कि आगे चलकर बर्बरतापूर्ण विद्रोह-विरोधी कार्रवाइयों में भारतीय सेना का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाए। इस दूरगामी उद्देश्य से ही इस बजट को इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया है। इन तमाम जन-विरोधी और देश-विरोधी गतिविधियों के लिए सैन्य खर्च लगातार बढ़ाया जा रहा है।

इस पूरी राशि में 33,484 करोड़ रुपए का एक मोटा हिस्सा पूंजीगत खर्च के लिए रखा गया है। यह पिछले साल 20,953 करोड़ रुपए रहा था। यह बढ़ोत्तरी हथियार व्यापारियों, राजनीतिक व सैन्य नेताओं को मालामाल बनने का बढ़िया मौका प्रदान करेगी!

भाजपा की नीतियां जारी

इस बजट में गरीब व मध्यम तबकों पर कई अन्य रूपों में भी हमला किया गया। बचत राशियों और भविष्य निधि पर ब्याज दर बेहद कम 8% ही रहा करेगी। पेंशन पाने वालों को तो 9% की ब्याज दर से बाण्ड्स (बंधपत्रों) में बचत करने का मौका दिया गया। यह कम से कम मुद्रास्फीती की सालाना दर से भी मेल नहीं खाएगी (सरकार द्वारा तोड़-मरोड़कर किए गए आंकड़ों के आधार पर नहीं, बल्कि वास्तविक आंकड़ों के आधार पर)।

पेट्रोलियम सब्सिडी को लगभग आधा घटा दिया गया – 6,573 करोड़ से 3,559 करोड़ रुपए तक। इसके फलस्वरूप रसोई गैस और मिट्टी तेल की कीमतें पिछले जून 15 को बढ़ाई गई कीमतों से भी ज्यादा बढ़ने की संभावना है। चूंकि खाने के तेलों पर सीमा शुल्क बढ़ाए गए हैं, इसलिए अब उनकी कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा होने वाला है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आवंटन पिछले साल के बराबर ही रखा गया। मुद्रास्फीति की दर से हिसाब लगाया जाए तो इसका मतलब इसमें कटौती की गई है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों के विकास व आर्थिक निगम के लिए काफी कम मात्रा में 50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए।

भले ही इस बजट का खूब ढिंढ़ोरा पीटा जा रहा हो, वास्तव में यह गरीबों, ग्रामीणों और मध्यम वर्गियों के खिलाफ और सम्पन्न वर्गों के अनुकूल साम्राज्यवादियों के आदेशों पर अमल 'आर्थिक सुधारों' की अगली कड़ी ही है। ऐसे में इस बजट पर बड़े व्यापारी वर्गों ने अपनी खुशी जाहिर की है तो आश्चर्य की बात नहीं है। जैसे कि शुरू में ही कहा गया, पिछले बजटों और वर्तमान बजट के बीच सिर्फ एक ही फर्क यह है कि इसने मानवीय चेहरा, या इसे और भी सटीक शब्दों में कहें तो मानवता का नकाब ओढ़ रखा है। इसलिए आज वक्त का तकाजा है कि हम इस नकाब को उतार फेंक दें और कड़वी सचाइयों को उजागर कर दें।

चाहे सत्ता में कोई भी संसदीय पार्टी रहे, आर्थिक सुधारों के अमल के सवाल पर सभी का रवैया एक ही समान है। इनमें से किसी में भी यह हिम्मत ही नहीं है कि वे अपने साम्राज्यवादी आकाओं के लिए मुश्किलें पैदा करने वाला कोई कदम उठाए। सभी पार्टियां साम्राज्यवादियों के सामने नतमस्तक हैं। एक विशालतम और जुझारू साम्राज्यवाद-विरोधी आन्दोलन ही इन देशद्रोहियों द्वारा लागू साम्राज्यवाद अनुकूल नीतियों का सुचारू तरीके से मुकाबला कर सकता है और हरा सकता है। वही आन्दोलन अब नाम मात्र की रह गई भारत की प्रभुसत्ता की लाज बचा सकता है और उसके लगातार जारी पतन को रोक सकता है। ★

(.... पृष्ठ 4 का शेष)

के पक्ष में हमारी यह नई पार्टी ज्यादा सक्रियता से खड़ी रहेगी। भारतीय विस्तारवादियों और अमेरिकी साम्राज्यवादियों द्वारा उनकी फौजी शक्ति के बल पर नेपाल में की जा रही दखलंदाजी का हम दृढ़ता से विरोध करेंगे। पेरू, फिलिप्पीन्स, तुर्की, आदि देशों में माओवादी पार्टियों के नेतृत्व में जारी लोकयुद्धों का हमारी पार्टी समर्थन करती रहेगी। साम्राज्यवाद और प्रतिक्रियावाद के खिलाफ जारी तमाम जन संघर्षों को इस नई पार्टी का समर्थन जारी रहेगा। अमेरिकी साम्राज्यवादियों के नेतृत्व में किए गए हमले और कब्जे के खिलाफ बहादुरी से लड़ रही इराकी और अफगान जनता के प्रतिरोधी संघर्ष को हमारी नई पार्टी का पूरा समर्थन जारी रहेगा।

यह एकीकृत पार्टी सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रीयवाद के परचम को ऊंचा उठाकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर असली मार्क्सवादी-लेनिनवादी-माओवादी ताकतों को एकताबद्ध करने के प्रयास में और ज्यादा सक्रिय भूमिका अदा करेगी। इतना ही नहीं, दुनिया की तमाम शोषित-पीड़ित जनता और राष्ट्रीयताओं के साथ यह पार्टी एकताबद्ध होकर साम्राज्यवाद और उसके गुर्गों के खिलाफ विश्व सर्वहारा क्रान्ति को आगे बढ़ाने के लक्ष्य से उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेगी। इस तरह यह दुनिया भर में समाजवाद, और बाद में साम्यवाद को हासिल करने का रास्ता सुगम बनाएगी।

इन महानतम लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमारे सैकड़ों प्यारे साथियों ने अपने अनमोल प्राणों को न्यौछावर किया है। हमारी केन्द्रीय कमेटी (अस्थाई) शपथ लेती है कि उन तमाम शहीदों द्वारा रोशन किए गए रास्ते पर आखिरी दम तक चलते रहेंगे और उनके सपनों को साकार बनाने के लिए हमारी पूरी शक्ति को केन्द्रित करेंगे।

क्रान्तिकारी अभिनन्दन के साथ,

गणपति

केन्द्रीय कमेटी (अस्थाई) की ओर से

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

28 जुलाई

शहीदों के अरमानों को पूरा करने का संकल्प दोहराते हुए

समूचे दण्डकारण्य में शहीद-सप्ताह सम्पन्न

भारत की क्रान्ति के दौरान अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों को याद करने का दिन है 28 जुलाई। इसी दिन हमारी पार्टी के संस्थापक-नेता, भारत की उत्पीड़ित जनता के प्यारा सपूत कॉमरेड चारु मजुम्दार ने दुश्मन की तीव्र यातनाएं झेलकर अपनी जान की कुरबानी दी थी। तब से लेकर आज तक हजारों लोगों ने भारत की क्रान्ति को सफल बनाने की खातिर अपनी जानें कुरबान कर दी हैं। इनमें पार्टी के सर्वोच्च स्तर के नेता कॉमरेड्स श्याम, महेश और मुरली से लेकर पार्टी सदस्य, पार्टी समर्थक और आम लोग भी शामिल हैं। इन्होंने अपनी कुरबानी से भारत की क्रान्ति की शान बढ़ा दी है। हमारी पार्टी भाकपा (मा-ले) [पीपुल्स वार] और हमारी बिरादराना पार्टी एमसीसीआइ की अगुवाई में देश के कई हिस्सों में जारी जनयुद्ध में पिछले एक साल के दौरान कई साथियों ने दुश्मन से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त किया। इसके अलावा विश्व समाजवादी क्रान्ति के तहत नेपाल, पेरू, तुर्की, फिलिप्पीन्स आदि देशों में जारी जनयुद्धों में भी कई योद्धाओं ने शहादत का परचम ऊंचा उठाया है। साम्राज्यवाद, खासकर अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ते हुए इराक, अफगानिस्तान समेत दुनिया के कई हिस्सों में अनगिनत लोगों ने बहादुराना शहादत दी। हालांकि हम इनमें से कई लोगों की विचारधारा से सहमत नहीं हैं, फिर भी साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ते हुए उन्होंने जो बलिदान दिया उसका हम पूरा सम्मान करते हैं। ऐसे तमाम वीर योद्धाओं को याद करते हुए इस साल भी दण्डकारण्य के गांव-गांव में शहीद सप्ताह कामयाबी के साथ सम्पन्न हुआ। खासकर पिछले एक साल के दौरान दण्डकारण्य में शहीद हुए साथियों में प्रमुख थे – कॉमरेड राजू (आयतू कुंजाम), कॉमरेड रामदास (मोडियम साइबी), कॉमरेड स्वरूपा (पेंटी), आदि। इनके अलावा दुश्मन द्वारा चलाए गए पाशविक दमनचक्र में कॉमरेड बुधराम, कॉमरेड सुखराम, कॉमरेड बुधरी, कॉमरेड चैतू, आदि आम लोग भी शहीद हुए हैं। इन सभी कॉमरेडों को जगह-जगह पर श्रद्धांजलि पेश की गई।

हर साल की तरह इस साल भी दुश्मन ने शहीद सप्ताह को विफल बनाने के लिए अपना आक्रामक अभियान तेज किया। लोगों को डराने-धमकाने के अलावा गिरफ्तारियां, यातनाएं, शहीद स्मारकों में तोड़फोड़ करने आदि काले कारनामों को जारी रखा। लेकिन दण्डकारण्य की संघर्षशील जनता ने पुलिसिया दमन को धता बताते हुए सैकड़ों-हजारों की संख्या में सभाओं में भाग लेकर शहीद सप्ताह को सफल बनाया। इस अवसर पर आयोजित सभाओं और रैलियों में लोगों ने शहीदों के मकसद को पूरा करने का अपना संकल्प दोहराते हुए दण्डकारण्य को मुक्तांचल में तब्दील करने का प्रण किया। शहीदों के आदर्शों से सीख लेते हुए जनवादी राजसत्ता के निर्माण की दिशा में दृढ़ता से कदम बढ़ाने की कसम खाई। शहीदों के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। आइए, इस मौके पर आयोजित कार्यक्रमों के डिवीजनवार ब्यौरे पर नजर डालें।

दक्षिण बस्तर डिवीजन

हर साल की तरह इस साल भी दक्षिण बस्तर की जनता ने शहीद सप्ताह के मौके पर शहीद योद्धाओं को पूरे सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी। "शहीदों के अरमानों को पूरा करेंगे" का नारा लगाते हुए गांव-गांव में सैकड़ों-हजारों लोग इकट्ठे होकर शहीद सप्ताह मनाए। जनता ने 28 जुलाई के दिन शहीदों के स्मारकों के पास इकट्ठे होकर दो मिनट की खामोशी मनाई। 28 जुलाई से 3 अगस्त तक डिवीजन के सभी रेंजों में 2 से 3 जगहों पर बड़ी सभाएं आयोजित की गईं। भारी वर्षा की परवाह न करते हुए लोगों ने इनमें बड़ी संख्या में भाग लेकर शहीद योद्धाओं को श्रद्धांजलि पेश की। खास तौर पर दक्षिण बस्तर डिवीजन में जन्मे कॉमरेड राजू और कॉमरेड भास्कर को जनता ने याद किया जो उसके अपने गांवों में पल-बढ़कर पीजीए के नेता बने थे और दुश्मन के साथ वीरतापूर्वक लड़ते हुए शहादत दी थी। इनके अलावा भारत की क्रान्ति में शहीद हुए तमाम साथियों को भी लोगों ने याद किया। इस मौके पर जनता ने कॉमरेड्स श्याम, महेश, मुरली और सुखदेव की याद में निर्मित स्मारकों को लाल रंग पोतकर उन्हें सुसज्जित किया। जन मिलिशिया, विशेष छापामार दस्ते और पलटन समेत पीजीए की सभी इकाइयों ने लोगों द्वारा आयोजित स्मृति सभाओं को पूरी सुरक्षा प्रदान की। दुश्मन के आने के संभावित रास्तों पर उन्होंने घात लगाया और चारों तरफ गश्त चलाई। यानी एक तरफ दुश्मन के हमलों का मुकाबला करने की तैयारियां करके ही इन आयोजनों को अंजाम दिया गया।

पूरे डिवीजन में 12 जगहों पर बड़ी आमसभाएं हुईं। इनके सुचारू आयोजन के लिए प्रत्येक सभा के लिए एक संचालन कमेटी, वलंटियर दल आदि का गठन किया गया। शहीद साथियों के परिवार जनों से स्मारकों का अनावरण करवाया गया। सभा के पहले जुलूस, स्मारक का अनावरण आदि कार्यक्रम आयोजित किए गए। कोंटा एरिया में शहीद कॉमरेड प्रकाश के स्मारक के पास आयोजित सभा में 2,500 लोगों ने भाग लिया। दोरनापाल एलजीएस के इलाके में एक जगह पर आयोजित सभा में 2,900 लोगों ने भाग लिया।

किष्टारम इलाके में लोगों ने शहीद कॉमरेड राजू की यादगार में स्मारक का निर्माण किया। इस स्मारक का अनावरण शहीद राजू के बड़े भाई कॉमरेड जोगाल ने किया। इस मौके पर आयोजित सभा में 3 हजार लोगों ने भाग लिया। छापामार दस्ते के कमाण्डर कॉमरेड राजेश, केएएमएस अध्यक्ष गंगक्का और सुक्की ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। एलमम एलजीएस इलाके में ताल्लगूडेम शहीदों के स्मारक के पास आयोजित सभा में 2,500 लोगों ने भाग लिया।

पामेड इलाके में 5 जगहों पर सभाएं हुईं। चिलुकापल्ली में 300, गुंडम में 15 हजार, एर्रम में 13 हजार, कंचल में 20 हजार और पावूर में

पालोड गांव में शहीद कॉमरेड राजु को श्रद्धांजलि (इनसेट में उनका स्मारक)

1,480 लोगों की उपस्थिति में ये सभाएं सम्पन्न हुईं।

जेगुरगोंडा इलाके में बुडिगिन में आयोजित सभा में 1,100 लोगों ने भाग लिया। कॉमरेड सुखदेव के स्मारक के पास आयोजित सभा में 3,000 लोगों ने भाग लिया। गांव लिंगगिरी में कॉमरेड भीमन्ना के स्मारक के पास आयोजित सभा में 1,400 और कॉमरेड मल्लेश के स्मारक के पास आयोजित सभा में 1,500 लोगों ने भाग लिया।

उपरोक्त सभी सभाओं में सीएनएम (चेतना नाट्य मंच) के अलग-अलग दलों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। शहीदों की कुरबानियों की प्रशंसा करने वाले नाटक, गीत आदि पेश किए। इन कार्यक्रमों ने जनता में उत्साह बढ़ाया।

28 जुलाई का प्रचार करीब एक माह पहले से ही शुरू किया गया। इसके तहत डिवीजन में 4,000 पर्चे बांटे गए और 1,600 पोस्टर लगाए गए। शहीद सप्ताह के दौरान डिवीजन के कस्बों में वाहनों की आवाजाही बन्द रही और दुकानें बन्द रखी गईं। हालांकि पार्टी ने बन्द का कोई आह्वान नहीं किया था, लेकिन दुश्मन द्वारा पैदा किए आतंकपूर्ण माहौल और उसके दुष्प्रचार के चलते ऐसा हुआ है। दुश्मन के षड़यंत्रों का स्थानीय पार्टी ने जनता के बीच पर्दाफाश किया है।

गड़चिरोली डिवीजन

गड़चिरोली डिवीजन में तीव्र शत्रु दमन के बीचोंबीच ही जनता ने शहीदों को पूरे सम्मान के साथ श्रद्धांजलि देकर उनके अरमानों को पूरा करने का संकल्प दोहराया। क्रूरता का पर्याय बन चुकी गड़चिरोली पुलिस ने क्रान्तिकारी आन्दोलन के खिलाफ जारी चौतरफा हमले के तहत अहेरी एरिया के मर्रिगूडेम और गुंडेरा गांवों की जनता पर यह दबाव डाला कि वह 28 जुलाई के दिन क्रान्तिकारी आन्दोलन के खिलाफ जुलूस निकाले। पुलिस ने उन्हें आदेश दिया कि वे गुंडेरा से रेपनपल्ली पुलिस थाने तक सड़क पर जुलूस निकालें। दमन के कारण लगभग 80 लोग सड़क पर इकट्ठे हो गए। जब वे इकट्ठे हो गए तभी वहां छापामार दस्ता पहुंच गया। छापामारों ने उसी को शहीद सभा में बदलकर शहीदों को श्रद्धांजलि पेश की। लगभग आधा घण्टे में सभा को समाप्त करके वहीं कुछ बैनर भी बांध दिए। जनता ने शहीदों को लाल सलाम कहते हुए और पुलिसिया दमन की निंदा करते हुए नारे लगाए। उसके बाद लोग पुलिस के आदेशों का धिक्कार करते हुए अपने-अपने घर चले गए।

अहेरी इलाके में लगातार बिना रुके जारी तीव्र दमन के बीच ही लोगों ने जहां तहां छोटी-छोटी सभाएं आयोजित करके शहीदों को श्रद्धांजलि पेश की। ग्राम 'एल' में 25 और ग्राम 'वी' में 7 लोग इकट्ठे होकर शहीद स्मारक का अनावरण करके शहीदों को श्रद्धांजलि पेश की। इस मौके पर पूरे एरिया में 15 बैनर और 50 पोस्टर लगा दिए गए।

अहेरी इलाके के चलवाडा गांव में आयोजित शहीद सभा में 90 पुरुषों और 5 महिलाओं ने भाग लिया। गांव गोल्लाकर्जा में आयोजित सभा में 25 और गुड्डिगूडेम में आयोजित सभा में 62 लोगों ने भाग लिया। गुड्डिगूडेम के नाके के पास शहीद स्मारक का अनावरण करके लाल झण्डा उठाया गया और बैनर बांधे गए। वहां पर उपस्थित 30 लोगों के साथ लगभग एक घण्टे तक सभा आयोजित की गई। सभी जगहों में शहीदों की कुरबानियों की प्रशंसा करते हुए उनके सपनों को साकार बनाने का संकल्प लिया गया।

एटापल्लि इलाके में शहीद सप्ताह को विफल बनाने की दुश्मन की तमाम कोशिशों को विफल बनाकर जनता ने शहीदों को याद किया जिन्होंने जनयुद्ध के दौरान अपने प्राणों को न्यौछावर किया। इस इलाके में किए गए प्रचार में 400 पोस्टरों, 300 पर्चों और 12 बैनरों का इस्तेमाल किया गया। सूर्जागढ़ पहाड़ पर लाल झण्डा गाड़ दिया गया। पूरे इलाके में शहीद सप्ताह के बारे में बड़े पैमाने पर प्रचार किया गया। दो गांवों में पहले निर्मित शहीद स्मारकों के पास सभाएं की गईं। एक जगह पर 60 और दूसरी जगह पर 220 स्त्री-पुरुषों ने सभाओं में भाग लिया। कसंसूर इलाके में लोगों ने 10 फुट की ऊंचाई वाला एक स्मारक खड़ा किया। यहां पर आयोजित सभा में 40 पुरुषों और 60 महिलाओं ने भाग लिया। वेडमापल्ली सड़क पर तीन फुट का एक शहीद स्तम्भ बनाया गया। यहां पर आयोजित सभा में 40 लोगों ने भाग लिया। तीन अन्य जगहों पर लकड़ी से शहीद स्तम्भ बनाए गए। इन गांवों में आयोजित सभाओं में कुल 150 लोगों ने भाग लिया। इन सभाओं में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति ने अपने साथ कोई न कोई हथियार उठा लाया। जनता अपने अनुभव से यह बात समझ रही है कि तीव्र शत्रु दमन के बीच हथियारबन्द हुए बिना वह कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सकती।

इसी इलाके के एक अन्य गांव में पीजीए सैनिकों और जनता ने मिलकर शहीद सभा आयोजित की। इसमें 30 छापामारों और 90 ग्रामीणों ने भाग लिया। सभास्थल पर लाल कपड़े से स्मारक बनाया गया और शहीद श्याम, महेश और मुरली की तस्वीरें पेड़ों में टंगाई गईं। जब जनता और छापामार कतारबद्ध होकर खड़े हो गए, स्थानीय एरिया कमेटी सचिव ने झण्डा फहराया। उसके बाद एक अन्य कॉमरेड ने स्मारक का अनावरण किया। अन्तर्राष्ट्रीय गान के बाद शहीदों की याद में दो मिनट की खामोशी रखी गई। शहीदों की याद में नारे लगाने के बाद सभा शुरू हुई। इस सभा को एरिया कमेटी सदस्यों और डिविजनल कमेटी सदस्य ने सम्बोधित किया। उन्होंने 28 जुलाई के महत्व पर और फिलहाल लुटेरी सरकार द्वारा अपनाई जा रही जन विरोधी नीतियों पर

कॉमरेड अमरसाय हलामी

गड़चिरोली डिवीजन, टिप्रागढ़ इलाके के चारवाही गांव के निवासी थे। जन संगठन कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए पार्टी सदस्य के रूप में उभरे। क्रान्तिकारी राजनीति के प्रति उनमें असीम विश्वास था। जन संगठन नेता के रूप में जनता के दिलों में उन्होंने पक्का स्थान हासिल किया। पिछले अप्रैल माह में एक सड़क हादसे में इस कॉमरेड का देहान्त हुआ। आइए, इस कॉमरेड के मकसद को पूरा करने का संकल्प लें।

अपनी बात रखी। उन्होंने यह बात दोहराई कि शहीदों के सपनों को पूरा करते हुए शोषित जनता का राज स्थापित करना ही उन्हें हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

पेरिमिलि इलाके में पुलिसिया दमन का धिक्कार करते हुए सात गांवों की जनता ने शहीद सभा का आयोजन किया। गुरनूर, माडावेल्ली, गेर्रा – इन तीन गांवों के 118 पुरुषों और 30 महिलाओं ने एक स्थान पर इकट्ठे होकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। यहां पर जनता ने लकड़ी से 12 फुट का स्मारक खड़ा किया। सभा के पहले लोगों ने जुलूस निकाला जो कि करीब आधे घण्टे में पूरा हुआ। उसके बाद कॉमरेड कारपा ने झण्डा फहराकर सभा का प्रारम्भ किया। बाद में जनता और छापामारों ने मिलकर दो मिनट की खामोशी रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर वक्ताओं ने गड़चिरोली जिले में जारी पुलिसिया दमन और झूठे सुधार कार्यक्रमों के बारे में अपनी बात रखी। कॉमरेड रघु ने अपने भाषण में कहा कि शहीदों की कुरबानियों की बदौलत ही आज अपनी पार्टी 12 राज्यों में विस्तार कर पाई। शहीदों के अधूरे मकसद को पूरा करते हुए दृढ़ता से लड़कर दण्डकारण्य को आधार इलाके में बदलने के संदेश के साथ सभा का समापन हुआ।

29 तारीख को एरमानार में आयोजित शहीद सभा में 77 और 30 तारीख को ताडिगूडा में आयोजित शहीद सभा में 73 लोगों ने भाग लिया। इन सभी जगहों पर सभाओं में स्थानीय छापामार दस्ता भी शामिल था। शहीद सप्ताह के पहले इलाके में 150 पोस्टरों और 300 पर्चों से प्रचार कार्यक्रम चलाया गया।

गट्टा एरिया में कुल 12 स्थानों पर आयोजित शहीद सभाओं में कुल 28 गांवों के कुल 700 स्त्री-पुरुषों ने भाग लिया। ये सारी सभाएं शत्रु दमन के बीच ही सफल हुईं।

एक स्थान पर आयोजित सभा में शहीद कॉमरेड प्रभाकर की जीवनसंगिनी ने झण्डा फहराया। एक अन्य सभा में शहीद कॉमरेड कोमटी वाचामी की जीवनसंगिनी ने झण्डा फहराया। एक अन्य जगह में हुई सभा में स्थानीय क्रान्तिकारी जन कमेटी के अध्यक्ष ने झण्डा फहराया।

दो जगहों पर स्थानीय जन संगठन अध्यक्षों ने सभाओं को सम्बोधित किया, जबकि दो अन्य जगहों मे जनताना सरकार के अध्यक्षों ने भाषण दिया। केन्द्रीकृत तरीके से हुई इन सभाओं के अलावा इलाके के लगभग 60 गांवों में जनता ने अपनी परम्पराओं से शहीदों को श्रद्धांजलि दी।

भामरागढ़ इलाके के पांच गांवों की 200 लोगों ने एक स्थान पर शहीद सभा का आयोजन किया। इस सभा में एरिया पार्टी कमेटी सचिव ने झण्डा फहराया। एरिया कमेटी सदस्यों ने सभा को सम्बोधित किया। वक्ताओं ने अपने भाषण में यह संदेश दिया कि शहीदों के सपनों को साकार बनाते हुए जनयुद्ध को तेज किया जाए और नौजवान पीजीए में बड़ी संख्या में भर्ती हो जाएं। उन्होंने जनता का आह्वान किया कि आखिरी दम तक शहीदों के रास्ते पर चलें। वक्ताओं ने शहीदों की यह कहकर तारीफ की कि कॉमरेड चारु मजूमदार से लेकर आज कॉमरेड राजू, कॉमरेड रामदास, कॉमरेड स्वरूपा तक अनगिनत वीर योद्धाओं ने जनता की मुक्ति की खातिर अपने अनमोल प्राणों को न्यौछावर करके अपने जीवन को सार्थक बनाया।

उत्तर बस्तर डिवीजन

उत्तर बस्तर डिवीजन के कोइलीबेड़ा इलाके में जनता ने गांव-गांव में शहीद सप्ताह मनाया। साथ ही, इस इलाके में चार स्थानों पर आयोजित बड़ी आमसभाओं में भी जनता ने बड़ी संख्या में भाग लिया। प्रत्येक सभा में 10-20 गांवों की जनता ने भाग लिया।

28 जुलाई से सप्ताह भर पहले ही पूरे इलाके में प्रचार चलाया गया। जन संगठनों और सीएनएम दलों ने प्रचार कार्यक्रम में भाग लिया। पोस्टर लगा दिए। बैनर बांधे। मुख्य सड़क पर स्थित बड़गांव, दुर्गकोंदुल, कोद्दोपाका, संगम, बेटिया, इत्यादि गांवों के मुख्य चौराहों में शहीद स्मारक खड़े कर दिए गए।

मेन्ड्रा गांव में आयोजित सभा में 20 गांवों के 1,500 स्त्री-पुरुषों ने भाग लिया। कडिमे एलजीएस कमाण्डर कॉमरेड निर्मला ने झण्डा फहराकर कार्यक्रम का प्रारम्भ किया। उसके बाद शहीद स्मारक का अनावरण किया गया। बाद में वहां उपस्थित तमाम जनता ने दो मिनट की खामोशी रखकर शहीदों को याद किया। स्थानीय केएएमएस और डीएकेएमएस नेताओं ने सभा को सम्बोधित किया। स्थानीय सीएनएम कलाकारों ने शहीदों पर गीत पेश किए।

एनहोर में आयोजित सभा में 10 गांवों के लोगों ने भाग लिया। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद उनके मकसद को पूरा करने की शपथ ली। उसी प्रकार आटनार में आयोजित सभा में 4, रामपुर में आयोजित शहीद सभा में 3 और वरकड में आयोजित शहीद सभा में 4 गांवों की जनता ने भाग लिया। इस प्रकार पूरे कोइलीबेड़ा इलाके में 50 गांवों में शहीद सभाएं सम्पन्न हुईं।

उत्तर बस्तर के मेन रोड पर खड़े किए गए शहीद स्मारकों को जब पुलिस हटाने लगी थी पीजीए सैनिकों ने उसे सबक सिखाने की ठान ली। 31 जुलाई के दिन कौंडे गांव में पुलिस की एक टुकड़ी स्मारक को ध्वस्त करने की कोशिश कर रही थी। चूंकि उन्हें डर था कि कहीं उसमें बम न रखा गया हो, इसलिए बाकी पुलिस वाले 300 गज दूर रहकर सिर्फ एक ही जवान को आगे भेजा गया था। जब वह स्मारक को हटाने की कोशिश कर रहा था, पास में इसी की ताक में बैठे पीजीए छापामारों ने क्लेमोर माइन विस्फोट करके पुलिस वालों को दौड़ा दिया।

कॉमरेड कल्पना लोगों के दिलों में सदा जिन्दा रहेंगी !

शहीद सप्ताह को सफल बनाने के काम में जब पार्टी, पीजीए और जन संगठनों की सारी इकाइयां जुटी हुई थीं, 1 अगस्त को कॉमरेड कल्पना शहीद हो गईं। पश्चिम बस्तर डिवीजन के मद्देड इलाके के कोवेला एलजीएस में सदस्या के तौर पर कार्यरत कॉमरेड कल्पना दुर्घटनावश नदी में बह गईं जब वह अपने दस्ते के साथ चिंतावागु नदी को पार कर रही थीं। छापामारों को न सिर्फ दुश्मन के साथ बल्कि प्रकृति के साथ भी हर दम चौकसी बरतनी होगी, वरना हमें बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है – यह कड़वा अनुभव कॉमरेड कल्पना हमारे लिए छोड़ गईं। कॉमरेड कल्पना का असली नाम पोज्जे बुरका था। आइए, शहीद सप्ताह के दौरान ही एक और शहीद के रूप में अंकित होने वाली कॉमरेड कल्पना को श्रद्धांजलि पेश करें।

(कॉमरेड कल्पना के जीवन पर विस्तृत रिपोर्ट अगले अंक में पेश करने की कोशिश करेंगे। – सम्पादक)

माड़ डिवीजन

माड़ डिवीजन के कुतल इलाके में जनता ने क्रान्तिकारी स्फूर्ति के साथ शहीद सप्ताह मनाया। 28 जुलाई के पहले ही गांव-गांव में पोस्टरों और पर्चों के जरिए प्रचार किया गया। 28 जुलाई को ग्राम बटनार में एक सभा हुई। इस सभा में आसपास के 9 गांवों से 500 से ज्यादा स्त्री-पुरुषों ने भाग लिया। इसमें बच्चों ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया। सभास्थल से थोड़ी दूरी से लोगों ने एक जुलूस निकाला। अमर शहीदों को जोहार, शहीदों के लक्ष्य को पूरा करने के नारे लगाए। बाद में डीएकेएमएस अध्यक्ष ने झण्डा फहराकर सभा का प्रारम्भ किया। उसके बाद लोगों ने दो मिनट की खामोशी मनाकर शहीदों को श्रद्धांजलि पेश की। बाद में तीन डीएकेएमएस नेताओं ने सभा को सम्बोधित किया। वक्ताओं ने कहा कि इस लुटेरी व्यवस्था को उखाड़ फेंककर नई जनवादी क्रान्ति को सफल बनाना ही शहीदों को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि गांव-गांव में जनताना सरकार के अंगों का निर्माण करते हुए, उनका विस्तार करते हुए शहीदों के सपनों को साकार बनाया जाए। आखिर में स्थानीय एलजीएस कॉमरेडों ने जनता को सम्बोधित किया।

करेलघाट इलाके में 28 जुलाई के मौके पर 6 प्रचार दलों का गठन किया गया। इन दलों ने पूरे इलाके में गांव-गांव जाकर प्रचार किया। उन्होंने लोगों को बताया कि गांव-गांव में शहीद स्मारकों का निर्माण कर लाल झण्डा उठाकर उन तमाम शहीदों को याद करें जिन्होंने जनता की मुक्ति की खातिर अपने प्राणों को न्यौछावर किया। नारायणपुर पुलिस थाने से 400 गज दूरी पर दो बैनर बांधे गए जिनमें शहीदों को लाल सलाम का नारा लिखा हुआ था। एक किलोमीटर दूर स्थित विवेकानन्द आश्रम की दीवारों पर नारे लिखे। बेरेवेडा स्कूल की दीवार पर पेंट से शहीद कॉमरेड राजू की याद में स्मारक का चित्र उतारा गया। नारायणपुर शहर में बड़े पैमाने पर लगाए गए पोस्टरों और पर्चों से पुलिस अवाक सी रह गई। जब उसे लगा कि थाने पर हमला होने वाला है तो वह गश्त आदि बन्द करके थानों में ही सिमटकर रह गई।

इलाके के कई गांवों में लोगों ने पत्थरों से स्मारक बनाकर झण्डा फहराकर शहीद सभाएं आयोजित कीं। तीन स्थानों पर बड़ी सभाएं हुईं। कोडनार में आयोजित सभा में 6 गांवों के 300 स्त्री-पुरुषों ने भाग लिया। पहले जुलूस निकाल कर शहीदों की याद में नारे लगाए गए। मिलिशिया सदस्यों ने अपने अस्त्रों के साथ मार्च किया। उसके बाद जन संगठन सदस्य कॉमरेड रमेश ने झण्डा उठाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। डीएकेएमएस के सदस्यों ने सभा को सम्बोधित किया। उन्होंने माड़ डिवीजन में शहीद हुए कॉमरेड राजू की कुरबानी के बारे में विशेष रूप से बताया।

नारायणपुर के निकट हित्तावेडा गांव में आयोजित शहीद सभा में 6 गांवों से 550 स्त्री-पुरुषों ने भाग लिया। तीन घण्टों तक चली इस सभा के पहले जुलूस निकाला गया। मिलिशिया सदस्यों ने हथियारबन्द मार्च करते हुए गीत गाए। उसके बाद वक्ताओं ने सभाओं को सम्बोधित किया। स्थानीय सीएनएम कलाकारों ने भी गीत पेश किए।

गोटाजमरी गांव में आयोजित एक और सभा में 6 गांवों से 300 लोगों ने भाग लिया। नारायणपुर शहर के पास स्थित इन गांवों में आयोजित इन तमाम सभाओं ने जनता को काफी प्रभावित किया। जनता ने शहीदों के लक्ष्य को पूरा करने के संकल्प के साथ क्रान्तिकारी आन्दोलन में दृढ़ता से आगे बढ़ने की शपथ ली।

कोह्कामेट्टा इलाके के इरकभट्टी गांव में जनता ने 28 जुलाई को शहीद सभा आयोजित की। इस सभा में लगभग 500 लोगों ने भाग लिया। सभा के पहले जनता ने शहीदों के मकसद को पूरा करने के नारे लगाते हुए गांव में रैली निकाली। बाद में कॉमरेड लच्चू ने शहीद स्मारक का अनावरण किया। सीएनएम कलाकारों ने शहीदों की याद में गीत गाए। बाद में स्थानीय दस्ता कमाण्डर कॉमरेड कौसल्या, डिवीजन पार्टी सचिव कॉमरेड पाण्डू ने सभा को सम्बोधित किया। इस सभा में स्कूली छात्रों ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया।

काननार गांव में भी शहीदों की याद में सभा हुई। इस गांव में शहीद कॉमरेड राजू की याद में एक स्मारक बनाया गया। इस सभा को स्थानीय पार्टी और जन संगठन नेताओं ने सम्बोधित किया। कच्चापाल गांव में आयोजित शहीद सभा में लगभग 100 लोगों ने भाग लिया। कोह्कामेट्टा गांव में आयोजित सभा में 600 स्त्री-पुरुषों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के पहले 6 प्रचार दलों ने आसपास के गांवों में प्रचार किया। पर्चे, पोस्टर और दीवार लेखन से प्रचार चलाया गया। इस इलाके के कीहकाड, कुंदला, बासिंग, मुरनार, सोनपुर, मुहंदी, झारावाही, नीरमेट्टा आदि गांवों में भी शहीदों की याद में सभाएं हुईं।

पश्चिम बस्तर डिवीजन

पश्चिम बस्तर डिवीजन के भैरमगढ़ इलाके के तीन एलजीएसों के दायरे में डीएकेएमएस के 12 और केएएमएस के 11 प्रचार दलों ने व्यापक प्रचार अभियान चलाया। पूरे एरिया में 1,000 पर्चे बांटे, 62 बैनर बांधे और 700 पोस्टर चस्पा कर दिए। जांगला, माटवाडा, भैरमगढ़, मिरतुल, पदेड, गंगलूर, नैमेड, बीजापुर आदि कस्बों में भी पोस्टर लगाए गए। जगदलपुर-बीजापुर रोड पर चलने वाली बसों और जीपों में भी बैनर बांधे गए। कई जगहों पर स्कूल भवनों और पुलों पर नारे पेन्ट कर दिए गए। मिरतुल के पास रोड पर एक स्मारक खड़ा कर

दिया गया।

शहीद सप्ताह को सफल बनाने के लिए डीएकेएमएस और केएएमएस रेंज कमेटियों ने विशेष प्रयास किया। रेन्ज कमेटी सदस्यों ने अपने-अपने दायरे के गांवों में प्रचार चलाया। प्रत्येक गांव में पत्थरों से निर्मित शहीद स्मारकों के पास 28 जुलाई के दिन गांव के लोग इकट्ठे होकर दो मिनट खामोशी मनाकर शहीदों को याद किए। पूरे इलाके में 10 स्थानों पर बड़ी आमसभाएं हुईं जिनमें कुल 27 हजार लोगों ने भाग लिया।

मिरतुल इलाके में आयोजित एक सभा में 8 हजार लोगों ने भाग लिया। इस सभा को सम्बोधित करते हुए डीएकेएमएस रेंज कमेटी अध्यक्ष ने बताया कि कॉमरेड्स राजू, रामदास, स्वरूपा ने जनता के लिए अनमोल कुरबानी देकर अपने लहू से हमारे लाल झण्डे की लालिमा बढ़ा दी। उन्होंने आगे बताया कि इस साल अप्रैल में सीआरपी बलों ने कॉमरेड्स बुधरी और चैतू की निर्मम हत्या की है जिससे आने वाले दिनों में ज्यादा क्रूर दमन चलाए जाने के संकेत मिल रहे हैं। अतः इसका मुकाबला करने के लिए हम सभी को मुस्तैदी से तैयार रहना चाहिए।

कॉमरेड पीसो ने अपने भाषण में बताया कि कॉमरेड बुधरी की हत्या से यह स्पष्ट हो रहा है कि शासक वर्ग आने वाले दिनों में खास तौर पर महिलाओं को बर्बरतापूर्ण दमन का शिकार बनाने जा रहे हैं। उन्होंने महिलाओं का आह्वान किया कि महिला संगठन के नेतृत्व में तमाम महिलाएं संगठित होकर पुलिसिया अत्याचारों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएं। संगठित प्रतिरोध के जरिए शासक वर्गों के पाशविक हमले को परास्त करके नई जनवादी क्रान्ति को सफल बनाना ही शहीदों को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी, ऐसा कहते हुए कॉमरेड पीसो ने अपना भाषण समाप्त किया।

अन्य जगहों पर भी इसी प्रकार डीएकेएमएस और केएएमएस नेताओं ने जनता को सम्बोधित किया। इन सभाओं में "शहीदों को जोहार", "शहीदों के सपनों को साकार बनाएंगे" इत्यादि नारे गूंज उठे। स्थानीय सीएनएम दलों ने अपने सांस्कृतिक प्रदर्शनों से लोगों को उत्साहित किया।

इसी समय ग्राम और इलाका स्तर के मिलिशिया दस्तों ने सभाओं को पूरी सुरक्षा प्रदान की। सभास्थलों में पहुंचने वाले सभी रास्तों को उन्होंने सील कर दिया ताकि दुश्मन कदम भी न रख सके। इन दस्तों ने पूरी मुस्तैदी के साथ काम किया ताकि दुश्मन की किसी भी हमले की कोशिश को नाकाम किया जा सके। इस प्रकार इन कार्यक्रमों को कामयाबी के साथ सम्पन्न करने में पीजीए के आधार बलों, यानी जन मिलिशिया ने प्रभावशाली भूमिका निभाई। ✶

आह्वान

एस्सार कम्पनी को मार भगाओ ! बस्तर की सम्पदाओं को बचा लो !!

एस्सार कम्पनी ने बैलाडीला से लौह चूर्ण को पाइपों के जरिए विशाखापट्टनम पहुंचाने की परियोजना शुरू की। 500 किलोमीटर लम्बे इस पाइप मार्ग के लिए लगभग 12 मीटर चौड़ाई में जंगलों को काटा जा रहा है। अधीकृत तौर पर 12 मीटर बताए जाने के बावजूद, एस्सार कम्पनी वन विभाग के अधिकारियों से सांठगांठ करके मनमाने ढंग से, कहीं-कहीं तो 50 मीटर से भी ज्यादा चौड़ाई में जंगलों का सफाया कर रही है। किरन्दुल, कुवाकोंडा, नकुलनार, दंतेवाडा और सुकमा इलाकों के भाजपाई और कांग्रेसी जनपद सदस्य, सरपंच और विधायक इस कम्पनी से रिश्वत लेकर गरीब आदिवासियों की जमीनें कम्पनी के हवाले करवा रहे हैं। नियमों का खुला उल्लंघन करते हुए ज्यादा जंगल और जमीन को हड़पने के बावजूद वे मुंह नहीं खोल रहे हैं। वन विभाग के अधिकारी इस योजना के अन्तर्गत बड़े पैमाने पर अवैध रूप से काटी गई लकड़ी को बेचकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। ये बड़े पैमाने पर धांधलियां करते हुए किसानों को डरा-धमकाते हुए उनकी खेत-जमीनों में गड्ढे खुदवा रहे हैं। इस परियोजना के तहत लाखों बेशकीमती पेड़ काटे जा रहे हैं। गरीब आदमी अपने पेट की खातिर एक पेड़ काटता है या खेत निकालता है तो उस पर मुकदमा चलाने वाला वन विभाग अब लाखों पेड़ अवैध तरीके से काटे जाने के बावजूद चुप्पी साध रहा है।

पानी के दबाव से लौह चूर्ण को प्रवाहित करने की इस योजना के लिए बैलाड़ीला के पास बहने वाली शंखिनी और डंकिनी नदियों से पानी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाएगा। पहले ही पानी की किल्लत से पस्त बस्तर की जनता इससे पानी के भयानक संकट से गुजरने वाली है। बैलाडीला की खदानों से छोड़े जा रहे व्यर्थ पदार्थों के कारण इन नदियों का पानी अब पीने के लायक ही नहीं रह गया। अब यह योजना शुरू होने से पानी पूरी तरह खत्म हो जाने और नदियों के सूखने का खतरा है। बस्तर की जल संपदा, वन संपदा और खनिज संपदा को विनाश होने से और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हाथ में पड़ने से बचाने की जरूरत है। इस इलाके की तमाम जनता को एकजुट होकर प्रतिरोध करने की जरूरत है। मजदूर-किसानों, छात्र-बुद्धिजीवियों और पर्यावरणविदों को इस समस्या की तीव्रता को पहचानकर इस परियोजना के खिलाफ व्यापक आधार वाला आन्दोलन निर्मित करना चाहिए। भाकपा के कुछ नेताओं ने हाल ही में इस परियोजना का विरोध करते हुए अखबारों में बयान जारी किए हैं। इस परियोजना को रोकने के लिए सिर्फ अखबारी बयानों तक सीमित न होकर वास्तविक कार्रवाई में उतरने की जरूरत है। हम सभी तबकों की जनता से, सभी संगठनों और पार्टियों से अपील करते हैं कि वे विभिन्न राजनीतिक दृष्टिकोण रखने के बावजूद इस समस्या पर एकजुट होकर साझा आन्दोलन छेड़ें।

दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी

30 सितम्बर 2004

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

सुलगता मणिपुर

सशस्त्र बलों को उन्मुक्त अधिकार प्रदान करने वाले काले कानूनों के खिलाफ उमड़ा जन आन्दोलन

पिछले 11 जुलाई से मणिपुर भड़क रहा है। सरकारी सशस्त्र बलों को उन्मुक्त अधिकार देने वाले काले कानूनों को वापिस लेने की मांग से शुरू हुआ यह आन्दोलन अब दो माह पूरा होने के बाद भी रोज-रोज ज्यादा से ज्यादा उग्र रूप धारण करता जा रहा है। यह अब इंफाल शहर के अलावा मणिपुर के कोने-कोने में फैलता जा रहा है। गलियां, सड़कें, स्कूलें, कालेज, विश्वविद्यालय, आदि जंगे मैदान में तब्दील हो गए। आए दिन विरोध प्रदर्शन, बंद आदि आयोजित किए जा रहे हैं। हजारों लोग सड़कों पर उतर आ रहे हैं। पुलिस की गोलीबारियों, रबड़ की गोलियों, लाठीचार्ज, टियरगैस शेलों, गिरफ्तारियों और दमन के अन्य खूंखार तरीकों की परवाह किए बिना मणिपुरी जनता अपने आन्दोलन को संगठित और जुझारू ढंग से जारी रखे हुई है। इस आन्दोलन के प्रति मौजूदा 'संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन' सरकार जो रवैया अपना रही है, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह कितनी प्रतिक्रियावादी है और उसका तथाकथित 'जनवाद' कितना झूठा है। वहां के लोगों का मानना यह है कि जनता की आकांक्षा के खिलाफ भारत में मणिपुर का विलय करने के बाद सरकार ने उन्हें हत्या और अत्याचार के सिवाए कुछ नहीं दिया। यही वजह है कि मणिपुरी जनता सहज ही भारत सरकार को एक विदेशी ताकत के रूप में देख रही है।

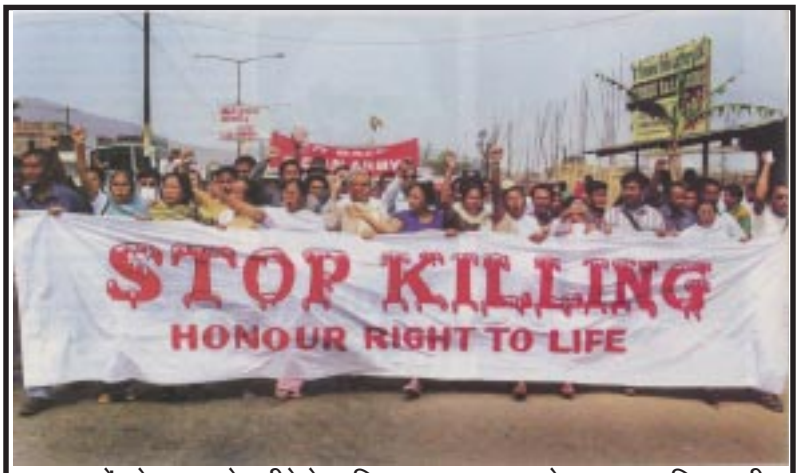

"हत्याओं को बन्द करो! जीने के अधिकार का सम्मान करो!" कहता मणिपुरवासी

मणिपुर में कई दशकों से लड़ाकू संगठनों द्वारा जारी आन्दोलनों को कुचलने के नाम पर केन्द्र सरकार द्वारा थोपे गए काले कानूनों की आड़ में अनगिनत बेकसूर लोगों की जानें गईं। कई महिलाएं सामूहिक अत्याचारों की शिकार हुईं। केन्द्र में सरकार चाहे बदले या न बदले, पर मणिपुर समेत तमाम पूर्वोत्तर इलाके के राज्यों में जनता पर दमन थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक ओर उग्रवादी संगठनों के साथ शांति वार्ता करके उन्हें मुख्य धारा में लाने की बातें करने वाली सरकारें आम जनता पर मनमानी हिंसा और अत्याचार कर रहे सशस्त्र बलों को दण्डित क्यों नहीं करती हैं? उन्हें उन्मुक्त अधिकार प्रदान करने वाले बर्बर कानूनों को भंग करने की जनता की बेहद जनवादी मांग को मानने में वे इतना अड़ियल रवैया क्यों अपना रही हैं? आइए, इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करें।

ज्वालामुखी यूं फूटी

11 जुलाई को असम रायफल्स के जवानों ने थांगजम मनोरमादेवी नामक एक 32 साल की महिला को इंफाल में उनके घर से गिरफ्तार किया। कुछ घण्टों बाद गोलियों से छलनी हुई उनकी लाश वहां से चार किलोमीटर दूर एक पहाड़ी इलाके में मिल गई। असम रायफल्स ने यह घोषणा की कि जब वे उन्हें पूछताछ के लिए वैन में ले जा रहे थे तब नीचे कूदकर भागने की कोशिश की तो उन्हें गोली चलानी पड़ी जिसमें वह मारी गईं। उधर असम से लेकर इधर आन्ध्रप्रदेश तक और एक तरफ कश्मीर से लेकर यहां दण्डकारण्य तक ऐसी मनगढ़ंत कहानियां न जाने कितनी बार दोहराई गई होंगी! लाश पर पड़े निशानों से यह स्पष्ट हो गया कि मनोरमा के साथ पहले सामूहिक बलात्कार किया गया और बाद में खूब यातनाएं देकर उन्हें क्रूरता से हत्या कर दी गई। उनके माता-पिता ने ऐलान किया कि जब तक मनोरमा के साथ यह घोर अत्याचार करने वाले जवानों को दंडित नहीं किया जाएगा और सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) कानून को वापिस नहीं लिया जाएगा, तब तक वे लाश नहीं लेंगे। इससे एक सरकारी अस्पताल में लाश रख दी गई। लेकिन दोबारा शव परीक्षण करने के बाद सरकार ने कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच खुद ही मनोरमा की अन्त्येष्टि करवाई।

इस घटना के खिलाफ 15 जुलाई को मणिपुर की राजधानी इंफाल में स्थित असम रायफल्स के मुख्यालय के सामने 12 महिलाओं ने कपड़े उतारकर प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने हाथों में बैनर-पोस्टर उठाए थे जिसमें यह लिखा गया था – "भारतीय सैनिको! हमें बलात्कार करो, मार डालो!" लगभग 50-60 साल की उम्र की वे महिलाएं जब यह कह रही थीं कि "जब हमारी आंखों के सामने ही अपनी बेटियों की इज्ज़त लूटी जा रही हो तो हमें कपड़े पहनकर भी क्या फायदा? इसलिए वे

मणिपुरी महिलाओं का विरोध प्रदर्शन

हमें भी बलात्कार करें कहते हुए हमने कपड़े उतार दिए", उनकी पीड़ा और आक्रोश को समझा जा सकता है। इस प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले अखिल मणिपुर महिला संगठन की सचिव रमणीदेवी ने बताया कि इसके बावजूद भी कि मणिपुर में अब तक हुई गैर-कानूनी हत्याओं और महिला के साथ हुए बलात्कारों पर हम लगातार विरोध जताते आ रहे हैं, इस पर ध्यान देने वाला ही नहीं है। इसीलिए हमें ऐसा तीव्र कदम उठाना पड़ा, ऐसा उन्होंने बताया। इस घटना के बाद सारे मणिपुर में जनता का गुस्सा भड़क उठा। विरोध प्रदर्शन कई इलाकों में फैल गए। सशस्त्र बलों को उन्मुक्त अधिकार प्रदान करने वाले "सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) कानून" को रद्द करने की मांग को व्यापक समर्थन मिल गया।

32 संगठनों की भागीदारी से बना 'अपुनबा लुप' नामक संगठन इस आन्दोलन का नेतृत्व कर रहा है। प्रदर्शन, जुलूस आदि रूपों में शुरू हुआ यह आन्दोलन शासन का धिक्कार करने वाले आन्दोलन में तब्दील हो गया। 29 जुलाई को 'अपुनबा लुप' द्वारा आयोजित एक विशाल रैली में तीन भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों समेत विभिन्न पार्टियों और संगठनों के नेताओं ने भाग लिया। 15 अगस्त को 'स्वतंत्रता' दिवस के मौके पर छात्र नेता पेबम चित्तरंजन ने आत्मदाह कर लिया। मणिपुरी छात्र संघ की बिशेनपुर इकाई के सलाहकार चित्तरंजन के बलिदान से इस आन्दोलन ने ज्यादा उग्र रूप धारण कर लिया। उसके पहले पांच युवकों ने मुख्यमंत्री के आवास के सामने आत्मदाह करने की कोशिश की थी। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से आग बुझाकर उनकी जान बचाई। 26 जुलाई को दिनेश नामक 28 साल के नौजवान ने इंफाल शहर के बीचोंबीच खुद पर चाकू से वार करके आत्महत्या की कोशिश की। इस घटना से भड़क उठे मणिपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने एक बस समेत राजभवन में घुसने की कोशिश की। इस मौके पर सुरक्षा बलों के साथ हुई झड़प में 22 छात्र घायल हुए। इस घटनाक्रम से परेशान हुए कांग्रेसी मुख्यमंत्रि इबोबी सिंह ने दो बार दिल्ली का दौरा किया। उसका डर यह था कि इस समस्या का सही ढंग से हल न करने पर आन्दोलनकारी सरकारी इमारतों और मंत्रियों को अपने हमलों का निशाना बना सकते हैं। स्थिति को शांत करने के लिए उसने 20 वर्ग किलोमीटर के इंफाल मुनिसिपल इलाके को सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) कानून से मुक्त करने की घोषणा की। यह पूरा 7 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों का इलाका है। लेकिन केन्द्र की संप्रग सरकार की इच्छा के खिलाफ उठाया गया यह फैसला भी जनता को शांत नहीं कर सका। अपुनबा लुप ने इस प्रस्ताव को बेझिझक ठुकरा दिया। समूचे मणिपुर से इस कानून को उठाने की मांग से आन्दोलन को तेज कर दिया। जनता को शांत करने के लिए केन्द्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील को असम रायफल्स को हटाकर इसके स्थान पर बीएसएफ को तैनात करने की घोषणा करनी पड़ी। इसके बावजूद जनता अपनी मांग से थोड़ा भी पीछे नहीं हटी।

राज्य सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत इस आन्दोलन का नेतृत्व कर रहे 30 नेताओं को गिरफ्तार किया। इनमें असम रायफल्स का मुख्यालय कांग्ला किले के सामने निर्वस्त्र प्रदर्शन करने वाली पांच महिलाएं भी शामिल थीं। इसके बावजूद भी यह आन्दोलन जारी है।

इस बीच, मणिपुर में सत्तारूढ़ कांग्रेस नेतृत्व वाले धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबन्धन सरकार के दो मंत्रियों समेत 12 कांग्रेसी विधायकों ने मुख्यमंत्री को चेतवानी दी कि वे इस्तीफा दे देंगे। यह साफ जाहिर है कि जन आन्दोलन की तीव्रता, खास कर पुराने कड़वे अनुभवों को मद्देनजर रखकर ही इन्होंने यह साहस किया। एक ओर केन्द्र सरकार द्वारा इस कानून को वापिस लेने से साफ मना करना, दूसरी ओर अपने ही मंत्रीमण्डल से इस्तीफों की धमकियां – इससे विचलित मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त के भाषण में यह वादा किया कि जब राज्य में अपहरण, धमकी देकर पैसा वसूलना इत्यादि तमाम कार्रवाइयां बन्द होगा और अमन कायम होगा तभी इस कानून को वापिस लिया जाएगा। लेकिन इस घोषणा से लोगों को जले पर नमक छिड़कने जैसा लगा। आन्दोलनकारियों ने एक बस में आग लगाकर और राजधानी में कई जगहों पर अवरोध खड़े करके इस पर विरोध जाहिर किया।

काले कानूनों के घने साये में

ब्रितानी उपनिवेशवादियों से सत्ता की बागडोर हाथों में लेने वाले भारत के दलाल पूंजीवादी और सामंती शासक वर्गों ने विरासत में उनके काले कानूनों और 'फूट डालो - राज करो' वाली कुटिल नीति को भी प्राप्त किया। 1958 में भारतीय संसद द्वारा पारित इस सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) कानून की जड़ें 1942 में ब्रितानी वाइसरॉय लिनलिथगो द्वारा पेश किए गए सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) विधेयक में ढूंढ़ी जा सकती हैं। शब्दों में कुछ हेर-फेर को छोड़ दें तो भारत के शासक वर्ग हू-ब-हू उसी अंग्रेजी कानून को जारी रखे हुए हैं। सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) कानून, 1958 के मुताबिक नॉन-कमिशन्ड अधिकारी भी किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर वारन्ट के बिना ही गिरफ्तार कर सकता है। चाहे कितने भी दिन हिरासत में रख सकते हैं। बिना किसी वारन्ट के घरों में घुसकर तलाशी ले सकते हैं, लोगों को हिरासत में ले सकते हैं, किसी घर में हथियार या बारूद होने के शक पर उसे ध्वस्त कर सकते हैं। हथियार रखने के शक पर किसी भी व्यक्ति को गोली मार सकते हैं। इतना ही नहीं, केन्द्र सरकार की इजाजत के बिना कोई भी व्यक्ति सैन्य बलों के सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं कर सकता, मुकदमा नहीं चला सकता और कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर

सकता। यह है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र कहलाने वाले हमारे देश में अमल कानून!

इस कानून को 1980 से सारे मणिपुर में लागू किया गया। इस कानून को हटाने की मांग भी नई नहीं है। कई सालों से पूर्वोत्तर इलाके के लोग इस गैर-जनवादी व बर्बरतापूर्ण कानून को हटाने की मांग करते आ रहे हैं। शर्मीला नामक एक 33 वर्षीय मणिपुरी महिला 4 नवम्बर 2000 से आमरण अनशन पर हैं जो कह रही हैं कि जब तक इस कानून को समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक वह खाना नहीं खाएंगी। उस समय सुरक्षा बलों द्वारा की गई एक बदले की कार्रवाई में 10 लोगों के मारे जाने के बाद से उन्होंने अपना यह अनशन शुरू किया। उन्हें इंफाल के एक अस्पताल में रखकर जबरन नाक में पाइप लगाकर तरल पदार्थ चढ़ाए जा रहे हैं। जब मुख्यमंत्री ने उनसे मिलकर इंफाल के मुनिसिपल इलाके से इस कानून को हटाने का अपना निर्णय सुनाकर उन्हें अपना अनशन छोड़ने को कहा तो शर्मीला ने साफ तौर पर मना किया। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा कि जब तक समूचे मणिपुर से इस कानून को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। इस कानून को हटाने की मांग के साथ-साथ मणिपुरी लोग काफी सालों से यह मांग भी करते आ रहे हैं कि असम रायफल्स कांग्ला किले को खाली कर दें जिसे उन्होंने अपना मुख्यालय बनाया रखा है। इंफाल शहर के बीचोंबीच स्थित इस किले को मणिपुरी जनता अपनी ऐतिहासिक धरोहर मानती है।

मनोरमा की हत्या ने मणिपुरी जनता को जितना झकझोर दिया, इस घटना के प्रति सशस्त्र बलों और उनके अधिकारियों के रवैये ने उसे उतना भड़का दिया है। इस बलात्कार/हत्या की घटना पर इबोबी सिंह सरकार ने सी. उपेन्द्र की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया। लेकिन असम रायफल्स ने इस आयोग के साथ सहयोग करने से मना कर दिया। उन्होंने अपने जवानों को मुकदमे के लिए आयोग के सामने हाजिर होने हेतु दिए गए आदेश पर गुवाहटी उच्च अदालत से अस्थाई स्थगनादेश हासिल किया। मनोरमा के साथ बलात्कार और उनकी हत्या करने के मामले में आरोपी कर्नल जगमोहन, नायक सूबेदार दिगम्बर दत्ता, रायफलमैन सुरेश कुमार, अजीत सिंह और टी. लोथा ने सुरक्षा कारणों से आयोग के समक्ष उपस्थित होने में अपनी असमर्थता प्रकट की। इस पर अफसोस व्यक्त करते हुए सी. उपेन्द्र ने टिप्पणी की कि असम रायफल्स के मुख्यालय कांग्ला किले से महज 500 गज दूरी पर स्थित आयोग के कार्यालय तक आने में असुरक्षा महसूस करने वाले असम रायफल्स के जवान उग्रवादियों से कैसे लड़ सकेंगे और राज्य की जनता को क्या सुरक्षा मुहैया कराएंगे, मेरी समझ के बाहर है। इस बीच उच्च अदालत ने फैसला सुनाया कि आयोग को अपने दायरे से बाहर के व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने का कानूनी अधिकार नहीं है। जाहिर है, सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) कानून के मुताबिक केन्द्र सरकार की इजाजत के बिना सशस्त्र बलों के सदस्यों के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इसका अंदाजा लगाना भी कठिन नहीं है कि असम रायफल्स ने केन्द्रीय गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय से सलाह-मशविरा के बाद ही उच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया होगा। असम रायफल्स के सहयोग न करने से यह आयोग भंग हो गया।

पहले शव परीक्षण की रिपोर्ट का हवाला देकर असम रायफल्स ने मनोरमा के साथ बलात्कार करके यातनाएं देने के आरोप को ठुकरा दिया। आदमियों को गायब कर देने में माहिर लोगों को शव परीक्षण रिपोर्ट बदलवाने में क्या दिक्कत? लेकिन मनोरमा के माता-पिता ने इस रिपोर्ट पर शंका व्यक्त की तो सरकार ने दोबारा शव परीक्षण का आदेश दिया। दोबारा शव परीक्षण करने वाले डॉक्टर थमंग्लेम ने उपेन्द्र आयोग के समक्ष पेश की गई अपनी रिपोर्ट में कहा कि चूंकि मनोरमा के जननेन्द्रियों पर गोलियों के गंभीर जख्म थे इसलिए यह निर्धारित करना असम्भव था कि उनके साथ बलात्कार किया गया था अथवा नहीं। यह बात स्पष्ट है कि असम रायफल्स के जवानों ने जानबूझकर ही मनोरमा की हत्या इतनी क्रूरतापूर्ण तरीके से की थी। सैन्य अधिकारियों और सरकार का एक और आरोप यह है कि मनोरमादेवी प्रतिबन्धित संगठन पीएलए (जन मुक्ति सेना) की सदस्या थीं और विस्फोटक पदार्थों की विशेषज्ञा भी थीं। तो क्या प्रतिबन्धित संगठनों के सदस्यों के लिए नागरिक अधिकार लागू नहीं होंगे? क्या उनकी हत्या करना, उनके साथ अत्याचार करना सब जायज होंगे? तो फिर "कानून के सामने सब बराबर हैं" की रट लगाने वाले शासकों को अपना नकाब उतार फेंकना होगा। सवाल यह बिल्कुल नहीं है कि मनोरमा किस संगठन की सदस्या थीं। सवाल सिर्फ यह है कि उनके साथ इस वहशी कारनामा करने का अधिकार सुरक्षा बलों को किसने प्रदान किया?

बन्दूकों से लोगों को मार सकते, पर दिलों को जीत नहीं सकते!

भारत सरकार इस भ्रम में है कि वह बन्दूकों की संगीनों से सब कुछ नियंत्रित कर सकती है। सत्तारूढ़ संप्रग सरकार ने खुद को धर्मनिरपेक्षवादी और जनवादी बताते हुए पोटा कानून को वापिस लेने का ऐलान किया। एक तरफ पोटा कानून को वापिस लेने की बात कहते हुए ही दूसरी तरफ उतना ही क्रूर एक और कानून को वापिस लेने की मणिपुरी जनता की मांग ठुकराना उसके दोगलेपन का साफ सबूत है। इस मौके पर यह सचाई फिर एक बार साबित हो गई कि

जब तक काले कानून हटेंगे नहीं, तब तक "मशालधारी महिलाओं" की लड़ाई रुकेगी नहीं!

पहले की भाजपा और अब की कांग्रेस के बीच सिर्फ बोली में ही फर्क है, दमनकारी नीतियों में कोई बुनियादी फर्क नहीं है। इतिहास में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में लगभग 2,000 सालों से अस्तित्व में रहे मणिपुर को इस बदहाली में ला खड़ा करने वाली भारत सरकार के खिलाफ जनता के दिल में तीखी नफरत है। 1891 में अंगरेजों के आक्रमण के साथ ही एक स्वतंत्र राज्य के तौर पर मणिपुर ने अपना अस्तित्व गंवा दिया। तबसे मणिपुर का इतिहास पूरा पराए शासकों के हाथों अपमान, हिंसा, अत्याचार, जुल्म और कत्लेआम का शिकार होने का ही है। भारत को झूठी आजादी मिलने से पहले ही, यानी मार्च 1947 तक ही मणिपुर को एक लिखित संविधान था। इस बात को चाहे कोई भी भुला दें, पर मणिपुरी लोग कभी नहीं भुलाएंगे। शानदार इतिहास, सभ्यता और संस्कृति से समृद्ध मणिपुर को भारत के विस्तारवादी शासकों ने 1 सितम्बर 1949 को भारतीय संघ में जबरन शामिल किया। यह प्रक्रिया इतनी गैर-जनवादी और एकतरफा ढंग से पुरी हुई कि वहां पर जनमत संग्रहण करके लोगों का अनुमोदन हासिल करने आदि कोई तरीका नहीं अपनाया गया। इसके थोड़ा आगे-पीछे पूर्वोत्तर इलाके के सभी राज्यों का भारतीय शासकों ने लगभग इसी तरीके से विलय कर दिया। आज मणिपुर में या अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलनों के भड़कने के पीछे जड़ यहीं है। इसी को अलगाववाद या उग्रवाद के रूप में चित्रित कर भारत सरकार अपने मीडिया के जरिए व्यापक प्रचार करवा रही है। इस प्रचार की तीव्रता इतनी ज्यादा है कि इतिहास की तह में जाने का कष्ट न उठाने वाले आम मध्यम वर्गीय लोग इन राष्ट्रीयताओं द्वारा आजादी और मुक्ति के लिए की जा रही लड़ाइयों को भारत की राष्ट्रीय एकता को तोड़ने वाले अलगाववादी या उग्रवादी आन्दोलन ही समझ बैठते हैं।

इन आन्दोलनों को कुचलने के लिए शासक वर्गों ने काले कानूनों का सहारा लेते हुए क्रूरतापूर्ण दमनचक्र चलाया। हजारों की संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात करके उन्हें उन्मुक्त अधिकार प्रदान किए। सुरक्षा बल आम जनता पर अपनी पाशविक ताकत का प्रयोग करते हुए मनमानी हिंसात्मक कार्रवाइयां कर रहे हैं। सरकार भले ही यह दावा करे कि उग्रवादी आन्दोलनों को कुचलने के लिए ही सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) कानून, अशांत क्षेत्र कानून इत्यादि काले कानूनों को लागू करना पड़ रहा है, पर कठोर सचाई यह है कि इस कानून के लागू रहने के बावजूद पिछले 25 सालों में कोई लड़ाकू संगठन खत्म नहीं हुआ, बल्कि मजबूत ही हो गए। मुख्य रूप से वहां जारी आन्दोलनों के प्रति हमदर्दी रखने वाले लोगों का दमन करने में ही इन काले कानूनों का उपयोग किया जा रहा है। इससे भी बढ़कर, इस कानून की आड़ में लड़ाकू संगठनों के साथ कोई सम्बन्ध न रखने वाले आम लोगों को मार डालना और अत्याचार करना जैसे सुरक्षा बलों का रोजमर्रा का काम बन गया।

समझौताहीन संघर्ष

काले कानून के खिलाफ आन्दोलित मणिपुरी जनता तमाम देशवासियों के सामने खुद को एक मिसाल के रूप में पेश कर रही है। अपने जुझारूपन के लिए जाने जाने वाले मणिपुरी लोग पूर्व में, जून 2001 में जब केन्द्र सरकार और नगा लड़ाकू संगठनों के बीच संघर्षविराम का दायरा मणिपुर के कुछ हिस्सों तक बढ़ाते हुए समझौता हुआ था, एक जबर्दस्त आन्दोलन चलाया था जो कि ऐतिहासिक था। उस आन्दोलन के दौरान कई लोगों ने अपनी जानें कुरबान की थीं। राज्य में विधानसभा भवन को और कई मंत्रियों के घरों को आग के हवाले करके मणिपुरियों ने जुझारू संघर्षों को नए सिरे से परिभाषित किया। इस बार भी आन्दोलन उसी तीव्रता से जारी है। इसीलिए शासक डर से कांप रहे हैं। वे एक तरफ इस आन्दोलन पर पानी फेरने की कोशिश करते हुए ही दूसरी तरफ कुछ रियायतें घोषित कर रहे हैं ताकि लोगों को इस आन्दोलन को समाप्त करने पर मजबूर किया जा सके।

अंग्रेजों की 'फूट डालो - राज करो' वाली कुटिल नीति को सिर पर उठाने लेने वाले असम रायफल्स के अधिकारियों ने सेनापति जिले के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले नगा समुदाय के लोगों से 21 अगस्त को जबरन एक रैली निकलवाई। इस रैली में जनता ने जो तख्तियां उठाईं उन पर ये नारे लिखे गए थे – "असम रायफल्स पहाड़ी इलाकों की जनता के दोस्त हैं", "असम रायफल्स जवानो! हमारी जानों और आत्माओं को बचाएं," आदि। लेकिन बाद में जब नगा जनता ने यह घोषणा की कि सुरक्षा बलों ने उन पर दबाव डालकर यह रैली निकलवाई थी, तो यह कोशिश भी नाकाम हो गई। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले नगाओं और इंफाल घाटी इलाके के निवासी मैते लोगों के बीच झगड़ा पैदा करने की शासकों की यह घिनौनी कोशिश बुरी तरह पिट गई। मणिपुर में बहुसंख्यक मैते (65%) लोगों के साथ-साथ नगा, कुकी, जेलियमग्रांग इत्यादि राष्ट्रीयताओं/कबीलों के लोग सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) कानून को वापिस लेने की मांग पर एकजुटता के साथ लड़ रहे हैं।

मणिपुरी जनता के जुझारू आन्दोलन में महिलाओं की भूमिका उल्लेखनीय है। प्रदर्शनों, रैलियों और अन्य तमाम प्रकार के संघर्षों में महिलाएं अग्रिम पंक्ति में खड़ी हैं। कई महिला संगठन महिलाओं का नेतृत्व कर रहे हैं। इनमें से एक है 'मशालधारी महिलाएं'। इस संगठन के नेतृत्व में महिलाएं कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए रातों में मशालें लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। इसी प्रकार, छात्रों की भूमिका भी उल्लेखनीय रही है। छात्रों ने स्कूलों और विश्वविद्यालयों को छोड़कर संघर्ष का रास्ता पकड़ा। उन्होंने यह कहते हुए कि जब इस कानून के लागू रहते हुए हमें और हमारी बहनों की कोई सुरक्षा नहीं हो तो हमें पढ़कर भी क्या फायदा, अपनी किताबें जला दीं। संघर्ष के दौरान कई अन्य तरीके सामने आए।

सितम्बर माह में अपुनबा लुप के साथ केन्द्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील की बातचीत विफल हुई। आन्दोलनकारियों ने यह खुलेआम कहा कि बातचीत के नाम से उनके आन्दोलन पर पानी फेरने की कोशिश की जा रही है। 20 अगस्त को अपुनबा लुप के प्रवक्ता जगत थौंडम ने साफ तौर पर कहा, "सिर्फ एक ही मांग है हमारी... हमारे पास कोई लम्बी-चौड़ी फेहरिश्त नहीं है। इस कानून को वापिस ले लें। इससे बढ़कर कोई और मांग नहीं है। इससे कम मांग भी नहीं है। तो इस पर बहसबाजी करने की जरूरत ही क्या है?" आशा करेंगे कि मणिपुरी जनता का जायज संघर्ष कामयाब हो। ★

आन्ध्र सरकार के साथ 'शांति' वार्ता जन 'युद्ध' का हिस्सा ही है !

आन्ध्रप्रदेश में पिछले अप्रैल माह में प्रमुखता से उभरा शांति वार्ता का मुद्दा अब एक निर्णायक मोड़ में पहुंच चुका है। देश की जनता, खासकर आन्ध्र की जनता इस शांति वार्ता के प्रति काफी उत्सुकता दिखा रही है। आन्ध्रप्रदेश विधानसभा चुनाव में चन्द्रबाबू के नेतृत्व वाली तेलुगुदेशम सरकार की पराजय और कांग्रेस के सत्तारूढ़ होने के बाद शांति वार्ता की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन सरकार की इस एकतरफा शर्त को कि बातचीत के दौरान नक्सलवादियों को गांवों में हथियारों के साथ नहीं घूमना चाहिए, हमारी पार्टी ने अस्वीकार कर दिया, जिससे इस प्रक्रिया में कई दिनों तक गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हुई थी। आखिरकार सरकार पीछे हटी तब जाकर पार्टी के साथ सीधी बातचीत का रास्ता साफ हो गया। किस पृष्ठभूमि में यह शांति वार्ता संभव हो सकी और यह प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ रही है, इस पर नजर डाली जाए।

शांति वार्ता का इतिहास

1 अक्टूबर 2003 को अलिपिरि के निकट पीजीए के हमले में चन्द्रबाबू बाल-बाल बच गए थे। बाद उसने जनता की सहानुभूति से फिर से सत्तारूढ़ होने के लालच में विधानसभा को भंग करके समय से पहले चुनाव का बिगुल बजा दिया था। नक्सलवाद को प्रमुख मुद्दा बनाकर चुनाव जीतकर क्रान्तिकारी आन्दोलन के दमन को जनता की मंजूरी हासिल करने की नाकाम कोशिश की। तेलुगुदेशम ने अपने चुनावी घोषणापत्र में यह कहा कि अगर नक्सलवादी हथियार त्यागकर मुख्य धारा में शामिल होते हैं तभी उनके साथ शांति वार्ता होगी। जबकि कांग्रेस आदि तमाम विपक्षी पार्टियों ने नक्सलवादियों के साथ बिना शर्त बातचीत करने की घोषणा की। इसके अलावा, कांग्रेस ने यह भी आश्वासन दिया कि वह झूठी मुठभेड़ों को बन्द करेगी; किसानों को मुफ्त में बिजली देगी; और विश्व बैंक के साथ तेलुगुदेशम सरकार द्वारा किए गए तमाम करारों की समीक्षा करेगी। जनता ने चन्द्रबाबू की तमाम जन-विरोधी और साम्राज्यवाद-अनुकूल नीतियों और फासीवादी दमनकारी नीतियों को ठुकराते हुए नकारात्मक वोट डाला जिसके परिणामस्वरूप कांग्रेस सत्ता में आ गई। इसके बाद शांति वार्ता का मुद्दा सामने आया। हालांकि इसके पहले 2002 में चन्द्रबाबू सरकार ने जनता और जनवादियों के दबाव में शांति वार्ता का प्रस्ताव सामने लाया था, लेकिन वह हथियार डलवाने की शर्त पर अड़ी रही। उसने संघर्षविराम की घोषणा न करके फासीवादी कत्लेआम का सिलसिला जारी रखा तो उस समय शांति वार्ता का सिलसिला आगे नहीं बढ़ सका। दरअसल चन्द्रबाबू सरकार को शांति वार्ता के मुद्दे पर ईमानदारी ही नहीं थी। सिर्फ जनवादियों में भ्रम फैलाने के लिए उसने शांति वार्ता का ढोंग रचा था। लेकिन हमारी पार्टी जनता की आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए एकतरफा ढंग से संघर्षविराम की घोषणा करके इस पर ईमानदारी के साथ अमल किया। लेकिन अड़ियल चन्द्रबाबू द्वारा जारी रखे गए फासीवादी हमले के तहत तुपाकुलागूडेम और नेरेल्लावागु की घटनाओं में हमें काफी नुकसान सहना पड़ा।

आन्ध्रप्रदेश में लम्बे अरसे से जारी पुलिसिया दमन चन्द्रबाबू के शासन में अभूतपूर्व स्तर में पहुंच गया। दुश्मन के हमले की तीव्रता को समय पर पहचानकर उसके अनुसार समुचित जवाबी कार्यनीति अपनाने में विफलता के कारण हमारे आन्दोलन को, खासकर उत्तर तेलंगाना में गंभीर नुकसान उठाने पड़े। दुश्मन के दमनचक्र को हराकर हावी होने में समूचे आन्ध्रप्रदेश में हम विफल रहे। आन्दोलन को गंभीर क्षति होने के बावजूद दुश्मन ने अपने हमले की तीव्रता में कुछ भी कमी नहीं की। क्रान्तिकारी आन्दोलन का जड़ से सफाया करने की मंशा से उसने क्रूरतम हमला लगातार जारी रखा। ऐसे हालात में जनता में यह चाहत पैदा हुई कि दुश्मन के हमले बन्द हों, अमन कायम हो और जनवादी अधिकारों की बहाली हो। जनता की यह आशा थी कि इस प्रकार तीव्र दमन की स्थिति में कम से कम सांस लेने का मौका तो मिल जाए। चारों तरफ यह मांग उठती रही कि दोनों पक्ष संयम बरतें और बातचीत के जरिए मसले को हल कर लें।

एक क्रान्तिकारी पार्टी को जनता के हितों के अलावा कोई दूसरा हित नहीं होता। जनता की आकांक्षा के अनुरूप ही तब भी और आज भी हमारी पार्टी ने बातचीत के लिए आगे आई। हमारी पार्टी ने यह ऐलान किया कि जनयुद्ध के तहत बातचीत को भी एक मंच के तौर पर इस्तेमाल करते हुए जन समस्याओं के हल के लिए, खासकर जनता के जीने और आन्दोलन करने के अधिकारों की बहाली के लिए वह तैयार है। नई सरकार के गठन के बाद पार्टी ने सरकार से मांग की कि हमले बन्द करके वार्ता के लिए माकूल माहौल तैयार करे। पार्टी की मुख्य मांगें ये थीं – पुलिसिया हमलों को फौरन बन्द करे, संघर्षविराम की घोषणा करे, हमारी पार्टी पर प्रतिबन्ध हटा दिया जाए और क्रान्तिकारियों के सिरों पर से इनाम हटा दिया जाए। इन मांगों के प्रति जनता का समर्थन जुटाने में हमारी पार्टी कामयाब रही। शुरू में थोड़ा ना-नुकुर करने के बावजूद आखिरकार सरकार को इन मांगों को मानना ही पड़ा। इस प्रकार, हमारे देश के क्रान्तिकारी आन्दोलन के इतिहास में पहली बार, 16 जून को हमारी पार्टी और सरकार के बीच संघर्षविराम लागू हो गया।

कांग्रेस की मजबूरियां

जन आन्दोलनों का दमन करने और जनवादी अधिकारों का हनन करने में कांग्रेस के घोर इतिहास को कोई भुला नहीं सकेगा। श्रीकाकुलम आन्दोलन का दमन, आपातकाल की घोषणा, 1984 में सिखों का कत्लेआम, आशांत क्षेत्र कानून-टाडा जैसे काले कानून तैयार करना, 1992 में हमारी पार्टी पर प्रतिबन्ध लगाना, 1990-94 के बीच झूठी मुठभेड़ों में 600 क्रान्तिकारियों की हत्या – ऐसे कई उदाहरण हैं जो उसकी जन-विरोधी व फासीवादी नीतियों को प्रतिबिम्बित करते हैं। इसके अलावा देश को साम्राज्यवादी मुद्रा संस्थाओं के पास गिरवी रखने, उदारीकरण, निजीकरण व भूमण्डलीकरण की नीतियां शुरू करने और साम्राज्यवादी लूट-खसोट के लिए देश के सारे दरवाजे खोल देने का 'श्रेय' भी उसी को जाता है। पर जनता के नकारात्मक वोट से सत्तारूढ़ हुई कांग्रेस को कुछ चुनावी वायदों को पूरा करना अनिवार्य हो गया। नई सरकार को प्रदेश में अपेक्षतया शांतिपूर्ण माहौल निर्मित करके अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए हमारी पार्टी के

साथ बातचीत करना जरूरी हो गया। इसके अलावा कुछ अन्य समस्याएं भी कांग्रेस के सामने थीं। भारी कर्ज के बोझ से दबी प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तीखा संकट उत्पन्न होने का खतरा है। कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी के चलते उत्पन्न आंतरिक संकट से उबरने और राजशेखर रेड्डी के खेमे को मजबूत होने के लिए थोड़े वक्त की आवश्यकता है। कांग्रेस के सत्तारूढ़ होने के बाद से किसानों ने बड़ी संख्या में आत्महत्या करना शुरू किया तो गंभीर समस्या पैदा हो गई जिसे हल करने के लिए सकारात्मक माहौल की जरूरत है। सबसे अहम, प्रदेश की जनता

इस मौके पर हमारी पार्टी निम्न लिखित मांगें सामने ला रही है :

I. प्रदेश में जनवादी माहौल बनाना चाहिए। जनता के अपनी जनवादी मांगों को लेकर लड़ने के अधिकार को सरकार मान्यता दे।

* आन्दोलनों, शान्तिपूर्ण प्रदर्शनों और सभाओं को सरकार न रोके।
* भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मा-ले) [पीपुल्सवार] और अन्य जन संगठनों पर से प्रतिबन्ध उठाया जाए।
* पीपुल्सवार और जन छापामार सेना और अन्य जन संगठनों के कार्यकर्ताओं के सिर पर इनाम घोषित करने की पद्धति को समाप्त करे।
* ग्रे-हाउण्ड्स बलों, विशेष सुरक्षा बलों (एसएसएफ) और विशेष खुफिया विभाग (एसआईबी) को भंग किया जाए। केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों को वापिस भेजा जाए।
* तमाम राजनीतिक बन्दियों को रिहा किया जाए।
* झूठी मुठभेड़ों में नक्सलवादियों की हत्या करने वाले पुलिस अधिकारियों को समय से पहले पदोन्नति देने और अनधिकारिक रूप से इनाम देने की नीति को बन्द किया जाए।
* गांवों में मुखबिर व्यवस्था को भंग करना चाहिए। पीपुल्सवार के कार्यकर्ताओं को अपनी तरफ रिझाकर उन्हें कोवर्ट दलाल बनाने की नीति को सरकार त्याग दे।
* ग्रीन टाइगर्स, क्रान्ति सेना, पलनाडु टाइगर्स, तिरुमला टाइगर्स, नईम गिरोह आदि तमाम लम्पट गिरोहों को नियंत्रित किया जाए।
* तमाम झूठी मुठभेड़ों की न्यायिक जांच करके जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों को दण्डित किया जाए।
* पार्टी और जन संगठन कार्यकर्ताओं पर दर्ज तमाम मामलों को उठाया जाए।

II. कृषि के क्षेत्र में सुधार लागू किए जाएं।

* भूमि सुधारों को लागू किया जाए। भगवान के नाम रखी जमीनों, सरकारी जमीनों, जंगल जमीनों और जमींदारों की जमीनों को अतीत में जिन किसानों ने कब्जा किया था उन्हीं के नाम कर दिया जाए।
* भूमि हदबंदी कानून को लागू किया जाए।
* सिंचाई की तमाम लम्बित परियोजनाओं को पूरा किया जाए। किसानों को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध की जाएं। पर्याप्त बिजली की आपूर्ति की जाए।
* किसानों की आत्महत्याओं को रोकने के लिए किसानों द्वारा लिए गए तमाम निजी कर्जों को माफ किया जाए।
* सूखे की समस्या को हल करने के लिए स्थाई और समग्र योजना बनाई जाए।

III. फिलहाल अमल उदारीकरण, निजीकरण और भूमण्डलीकरण के स्थान पर स्थानीय संसाधनों पर आधारित औद्योगीकरण व अन्य योजनाओं को लागू किया जाए।

* साम्राज्यवादियों के इशारे पर चल रही विश्व बैंक की तमाम परियोजनाओं और योजनाओं को भंग किया जाए।
* मजदूरों की छंटनी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के निजीकरण को रोका जाए।
* लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योगों को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की प्रतियोगिता से बचाया जाए। सहकारिता की नीति और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को बहाल किया जाए।
* पीने के पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर यूजर चार्ज वापिस लिया जाए।
* विश्व बैंक, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और अन्य देशों के साथ किए गए तमाम समझौते रद्द कर किए जाएं।

IV. जंगल पर आदिवासियों के अधिकार को मान्यता दे।

* आदिवासियों को स्वयंशासन दिया जाए।
* अनुसूचित इलाकों में आदिवासियों की जमीनों को गैर-आदिवासियों के हाथों में जाने और पराई होने से रोकने वाले 1/70 कानून लागू किया जाए। आदिवासियों के आवासीय इलाकों में गैर-आदिवासी आबादी को बसाने की नीति बन्द करे।
* आदिवासी भाषाओं को विकसित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

V. पृथक तेलंगाना प्रदेश का गठन किया जाए।

VI. उत्तरी तटवर्ती इलाका और रायलसीमा के पिछड़े इलाकों को विकसित करने के लिए एक समग्र नीति तैयार की जाए।

VII. दलितों के आत्मसम्मान को अपमानित करने वाले लोगों को सजा दी जाए। कारमचेडु, चुंडूरु, नीरुकोंडा और वेमपेन्टा में दलितों पर हमलों के लिए जिम्मेदार अगड़ी जातियों के लोगों और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे।

* निजी क्षेत्र में नौकरियों में दलितों को आरक्षण दिया जाए।

VIII. सम्पत्ति में महिलाओं को समान अधिकार दे।

* निजी क्षेत्र में महिलाओं को आरक्षण दिए जाए।
* महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को कड़ी सजा दी जाए।

IX. शराब पर सम्पूर्ण पाबन्दी लागू की जाए।

X. अवैध तरीके से सम्पत्तियां कमाने वाले अधिकारियों, राजनीतिक नेताओं और पूंजीपतियों की जांच की जाए। भ्रष्टाचारी अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए।

* कर चोरी करने वाले सम्पन्न लोगों से पैसा वसूला जाए। ✶

और जनवादी लोग सरकार पर यह दबाव डाल रहे हैं कि राज्य में शांतिपूर्ण माहौल बनाया जाए, पिछले इतिहास को न दोहराया जाए और दमनकारी नीतियों को समाप्त करके नक्सलवादियों के साथ फौरन बातचीत शुरू की जाए। ऐसे कई अन्य कारणों से भी कांग्रेस के सामने हमारी पार्टी के साथ बातचीत के अलावा कोई चारा नहीं रह गया।

सरकार के साथ बातचीत के सवाल पर हमारी पार्टी का दृष्टिकोण

हथियारबन्द संघर्ष के जरिए लुटेरी व्यवस्था को ध्वस्त करने के मकसद से संघर्षरत एक क्रान्तिकारी पार्टी को सरकार के साथ, जो लुटेरी वर्गों के राज्य-यंत्र का हिस्सा है, बातचीत करने के लिए आधार ही कहां है? यह सवाल आम तौर पर उठता रहता है। दरअसल दीर्घकालीन लोकयुद्ध के दौरान कई उतार-चढ़ाव, घुमाव और मोड़ आते रहते हैं। हर मोड़ में भी, यानी राजनीतिक परिस्थिति में होने वाले बदलावों के अनुरूप क्रान्तिकारी पार्टी को सही कार्यनीति अपनानी होगी। सरकार के साथ शांति वार्ता भी जनयुद्ध का हिस्सा ही है। युद्ध और शांति दोनों भी जनयुद्ध के दो अविभाजित पहलू हैं। लेकिन, जनता पर रोज होने वाले शोषण और हिंसा को शांति वार्ता खत्म नहीं कर सकती। इस अर्थ में देखा जाए तो शांति अपेक्षापूर्ण ही होगी। इस लुटेरी व्यवस्था को ध्वस्त करके वर्गहीन समाज की स्थापना करने पर ही असली शांति कायम की जा सकती है। एक बात ध्यान में रखनी होगी कि दीर्घकालीन सशस्त्र संघर्ष के जरिए नई जनवादी क्रान्ति को सफल बनाने के हमारे लक्ष्य के सम्बन्ध में सरकार के साथ बातचीत या सौदेबाजी के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। हमारे क्रान्तिकारी युद्ध का लक्ष्य है सामन्तवाद, साम्राज्यवाद और दलाल नौकरशाह पूंजीवाद का सफाया करना, जो देश की प्रगति में प्रमुख बाधा हैं और जो प्रधान दुश्मन हैं, तथा क्रान्तिकारी राजसत्ता की स्थापना हासिल करके नई जनवादी समाज की स्थापना करना। इस रणनीतिक लक्ष्य पर शत्रु वर्गों के साथ कोई चर्चा नहीं की जा सकती – इसमें कोई रहस्य नहीं है।

जनयुद्ध के दौरान थोड़ी सी भी ढील मिल जाती है तो हम उसका इस्तेमाल अपना जनाधार बढ़ाने के लिए, पार्टी और विभिन्न संगठनों को मजबूत बनाने के लिए, अपनी कमजोरियों को सुधारकर ज्यादा उच्च स्तर पर युद्ध का संचालन करने के लिए – एक शब्द में कहें तो जनता को व्यापक पैमाने पर जनयुद्ध में गोलबन्द करने के लिए करते हैं। विभिन्न देशों के अनुभवों से हम यह भी समझ सकते हैं कि शत्रु वर्ग भी इस मौके का फायदा उठाकर क्रान्तिकारी आन्दोलन के खिलाफ एक बड़े हमले की तैयारियां करते हैं। अब भी इस तथ्य को देखा जा सकता है। एक तरफ शांति वार्ता जारी ही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस नीत संप्रग सरकार विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पुलिस अधिकारियों की बैठकें बुलाकर फौरी और दूरगामी योजनाएं तेजी से तैयार कर रही है। केन्द्र सरकार राज्यों को पर्याप्त आर्थिक सहायता करते हुए पुलिस बलों को अत्याधुनिक साधन-सम्पत्ति से लैस करते हुए एक बड़े हमले की तैयारियां कर रही है। इसलिए शांति वार्ता की इस प्रक्रिया को दुश्मन के साथ कूटनीति के मोर्चे में लड़ाई समझकर हमें जनता को विभिन्न राजनीतिक व रोजमर्रा के मसलों पर आन्दोलनों में उतारने पर जोर देना चाहिए। सामन्ती, साम्राज्यवादी और दलाल नौकरशाह पूंजीवादी शोषण के खिलाफ तथा हिन्दू फासीवादी ताकतों के खिलाफ जनता को बड़े पैमाने पर संघर्षों में गोलबन्द करना चाहिए। हमारा यह सतत प्रयास होना चाहिए कि व्यापक जनता इस तथ्य का अनुमोदन करे कि जनयुद्ध का मतलब तमाम जनता द्वारा लुटेरे वर्गों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई है।

लहरों की तरह उमड़ती जनता

सरकार द्वारा हमारे साथ संघर्ष विराम के लिए रजामंदी तथा हमारी पार्टी व अन्य जन संगठनों पर प्रतिबन्ध वापिस लेना जनता की ही जीत है। इक्के-दुक्के अल्प विरामों से पिछले 12 साल से जारी प्रतिबन्ध को हटाने से उत्साहित जनता पार्टी के आह्वान पर बड़ी तादाद में आमसभाओं में भाग ले रही है। शांति वार्ता की इस प्रक्रिया में हमारी पार्टी के अलावा सीपीआई (एम-एल) (जनशक्ति) भी भाग ले रही है। दोनों पार्टियों ने सांझे तौर पर कई जगहों पर आमसभाओं का आयोजन किया। 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीद सप्ताह के दौरान लोगों ने बड़ी संख्या में आमसभाओं में भाग लेकर सरकार के फासीवादी हत्याकाण्ड में जान गंवाने वाले शहीदों को पूरे सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी। 28 जुलाई को वरंगल जिले के एनुमामुला में आयोजित शहीद सभा में दो लाख जनता ने भाग लिया। मौजूदा शांति वार्ता की प्रक्रिया में अपनी पार्टी की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे कॉमरेड्स वरवरराव, गदर और कल्याणराव ने इस सभा को सम्बोधित किया। उसके बाद विशाखा जिले के धाराकोंडा, विशाखा शहर, अनन्तपुर समेत कई जगहों पर आयोजित आमसभाओं में हजारों-लाखों की संख्या में जनता ने भाग लिया। इससे पीपुल्सवार को बन्दूक की ताकत के सिवाए जनता की ताकत नहीं है कहकर अब तक अनाप-शनाप बकते रहने वाले प्रतिक्रियावादी नेताओं और पुलिस अधिकारियों की बोलती बन्द हो गई। जनता की इस उभार से यह स्पष्ट हो गया कि पिछले नौ सालों के दौरान क्रान्तिकारी आन्दोलन को काफी नुकसान होने के बावजूद जनता अभी भी पार्टी के साथ ही है, जनता का लड़ाकूपन अभी भी बरकरार है तथा मौका मिलने पर जनता लहरों की तरह टूट पड़ सकती है।

शांति वार्ता की रट लगाते हुए ही सरकार का टांग अड़ाना

जिस दिन राजशेखर रेड्डी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की, उसी दिन पुलिस ने आदिलाबाद जिले में झूठी मुठभेड़ की। इस पर पत्रकारों ने स्पष्टीकरण मांगा तो राजशेखर रेड्डी ने कहा कि पुलिस अपनी जिम्मेदारियां निभाती रहेगी। लेकिन इस घटना को लेकर जब उन पर दबाव बढ़ा तो उन्होंने कहा कि वह इस घटना पर जांच का आदेश देगा और पुलिस अधिकारियों को झूठी मुठभेड़ न करने का हुक्म देगा। पुलिस महानिदेशक सुकुमारा ने घोषणा की कि वे आक्रामक कार्रवाइयां बन्द करेंगे पर "सामान्य गश्त" जारी रखेंगे। एक ओर बातचीत की प्रक्रिया जारी ही थी, तो दूसरी तरफ वरंगल जिले में पुलिस द्वारा पार्टी में घुसाए गए कोवर्ट (गद्दार) साम्बय्या ने जुलाई के दूसरे सप्ताह में एक षड़यंत्रकारी हमला किया। इस हमले में पार्टी के जिला सचिव घायल हो गए जबकि दो दस्ता सदस्य शहीद हुए। शुरू से ही पुलिस अधिकारियों का एक तबका शांति वार्ता की वर्तमान

प्रक्रिया का विरोध करती आ रही है। वे क्रान्तिकारी आन्दोलन के खिलाफ लम्बे अरसे से चलाई जा रही कोवर्ट कार्रवाइयां अभी भी जारी रखे हुए हैं। सरकार के रवैए से यह स्पष्ट हो रहा है कि इन्हें सरकार से पूरा समर्थन प्राप्त है। बाद में खम्मम जिले में भी कुछ गद्दारों को पकड़ लिया गया जिससे एक बड़ा खतरा टल गया। पार्टी ने इन घटनाओं को जनता के सामने रखकर सरकार को बेनकाब कर दिया जिससे सरकार को सुरक्षात्मक मुद्रा अपनानी पड़ी। जनता ने ऐसी घिनौनी कार्रवाइयों की जमकर निंदा की। बाद में, एनुमामुला सभा को सम्बोधित करने वाले वरवरराव, गदर और कल्याणराव पर राजद्रोह का मामला दर्ज करना भी इस बात का सबूत है कि सरकार के इशारों पर ही पुलिस अधिकारी ऐसी कुटिल साजिशें रच रहे हैं। सरकार ने एक तरफ जनवादी होने की डींग मारते हुए ही दूसरी तरफ इन कॉमरेडों के खिलाफ मामला दर्ज करके यह साबित किया कि वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भी बर्दाश्त नहीं करती। बाद में जब "अज्ञात" लोगों द्वारा कॉमरेड गदर को धमकियां देते हुए फोन करने पर सरकार से शिकायत की गई तो उसने किसी गुमनाम व्यक्ति को गिरफ्तार करके हाथ झाड़ लिए। काले गिरोहों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की पार्टी की मांग को सरकार ने पुरी तरह नजरअंदाज किया।

जब पार्टी के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता का सिलसिला जारी ही था, तब सरकार ने बन्दूकों के साथ गांवों में न घूमने की शर्त सामने लाई। यह पार्टी को निहत्था बनाने के प्रयास के अलावा कुछ भी नहीं है। इस सवाल पर लम्बा गतिरोध बना रहा। आखिर में पार्टी के राज्य कमेटी सचिव कॉमरेड रामकृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा, "भले ही हम बातचीत की प्रक्रिया से बाहर जाएंगे पर हथियार त्यागने का सवाल ही नहीं उठता। फिर भी हम इस मुद्दे को एजेन्डे में जोड़कर चर्चा करने के लिए तैयार हैं ताकि इस एक मात्र मुद्दे को लेकर बातचीत का सिलसिला टूटने की नौबत न आ सके।" 21 सितम्बर को हैदराबाद में आयोजित नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के मौके पर राजशेखर रेड्डी ने केन्द्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील से सलाह-मशविरा करने के बाद इस शर्त से पीछे हटते हुए शांति वार्ता के लिए पार्टी नेताओं को न्यौता दिया ताकि प्रत्यक्ष बातचीत हो सके। पार्टी ने इस न्यौते को स्वीकार करते हुए ही 2 अक्टूबर को वार्ता के लिए आने में अपनी असमर्थता जाहिर करके तारीख को आगे बढ़ाने की अपील की। इस बीच 30 सितम्बर को हमारी पार्टी ने जनशक्ति पार्टी के साथ मिलकर हैदराबाद शहर में "जमीन उसकी जो उसे जोते", "आत्मनिर्भरता" और "शांति" – इन तीन नारों से एक विशाल आमसभा बुलाई। लेकिन इस सभा में आने वालों को रोकने के लिए पुलिस ने दमन का सहारा लिया और सैकड़ों वाहनों को वापिस भेज दिया। पुलिस ने अपने इन कारनामों से साबित किया कि उसे लोकतंत्र के प्रति कितनी घिन है। इसके बावजूद लाखों लोगों ने इसमें भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया।

हथियार त्यागने की हास्यास्पद शर्त

पूर्ववर्ती तेलुगुदेशम सरकार ने किस अड़ियल शर्त के सहारे बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ने से रोका था, कांग्रेस सरकार ने भी ठीक उसी शर्त को दोहराकर वर्तमान प्रक्रिया में गतिरोध पैदा किया। एक तरफ नक्सलवाद को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्या मानते हुए ही दूसरी तरफ नक्सलवादियों को जंगलों में ही रहने को कहना और हथियारों से गांवों में न घूमने की शर्त रखना इस बात की ओर इंगित करता है कि सरकार इसे कानून और व्यवस्था सम्बन्धी समस्या के रूप में ही देख रही है। वास्तव में जब गांवों में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के गुण्डे, हथियारबन्द गिरोह और काले गिरोह हथियार लेकर खुले आम घूम रहे हों और राजनीतिक नेता सशस्त्र गारदों के साथ घूम रहे हों और कई लाइसेन्सशुदा हथियार मौजूद हों, ऐसे में हमारी पार्टी को हथियार छोड़कर घूमने को कहने का मतलब पार्टी को निहत्था बनाने की साजिश ही है। इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि इस बहाने सरकार बातचीत की प्रक्रिया को पटरियों से हटाना चाह रही थी। नक्सलवादियों को जंगलों में रहने को कहना भी बेहद घटिया और हास्यास्पद तर्क है। यह कौन नहीं जानता कि नक्सलवादी आन्दोलन का मतलब जन आन्दोलन है। सरकार ने हमारी पार्टी को इसलिए प्रतिबन्धित किया था ताकि जनता को नेतृत्व से वंचित किया जा सके। अब भी सरकार का यह कहना कि हथियारों को लेकर गांवों में न घूमें और जंगलों में ही रहें, जनता को नेतृत्वहीन करने की कोशिश ही है। लेकिन नित्य दमन के बीच भी, यानी जब गश्त-खोजबीन अभियान, हमले, झूठी मुठभेड़ें इत्यादि जारी हों तब भी हमारी पार्टी जनता के सहयोग से जनता की बीच ही जी रही है। जनता का नेतृत्व कर रही है। इतिहास के हर जानकार को यह मालूम होगा कि भीषण दमन के बीचोंबीच भी जनता में हमारी पार्टी जड़ें जमाती आ रही है। इस बेमतलब की शर्त पर नागरिक चिन्तन मंच के कन्वीनर एसआर शंकरन का सकारात्मक रुख अपनाना बेहद चिन्ताजनक विषय है। लेकिन अत्यधिक जनता इस सवाल पर पार्टी के रवैए से सहमत है, इसका सबूत ही है कि पार्टी द्वारा बुलाई गई सभाओं में वह लाखों की संख्या में भाग ले रही है। जनता के रुझान को भांपकर ही सरकार ने इस सवाल पर मजबूरन पीछे कदम डालकर हमारी पार्टी के इस सुझाव को मान लिया कि इस मुद्दे को एजेन्डे में जोड़कर इस पर बहस की जाए। तब जाकर अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में सीधी वार्ता के लिए रास्ता साफ हो गया। आन्ध्रप्रदेश राज्य कमेटी सचिव कॉमरेड रामकृष्ण ने 2 अक्टूबर को यह घोषणा की कि उनकी अगुवाई में आन्ध्र-उड़ीसा सीमान्त विशेष जोनल कमेटी सचिव कॉमरेड सुधाकर और उत्तर तेलंगाना स्पेशल जोनल कमेटी सदस्य कॉमरेड गणेश समेत तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल सरकार के साथ सीधी बातचीत के लिए आएगा।

इस शांति वार्ता के दौरान पूरा संयम बरतते हुए जनता की समस्याओं को उठाते हुए उनके हल की मांग करना, आमसभाओं व 'जन असेम्बली', आदि कार्यक्रमों का आयोजन कर जनता का समर्थन जुटाना – इत्यादि कार्यक्रमों के जरिए हमारी पार्टी को आन्ध्र की उत्पीड़ित जनता के नेता के रूप में मान्यता मिल गई, इसमें कोई शक नहीं है। जनयुद्ध के दौरान इस मंजिल को कामयाबी के साथ इस्तेमाल करके क्रान्तिकारी आन्दोलन को नई बुल्दियों तक पहुंचाने में तथा जनयुद्ध के लिए असीम उत्पीड़ित जनता का व्यापक समर्थन जुटाकर उसे बड़े पेमाने पर चला सकने के लिए आवश्यक क्षमता व ताकत विकसित कर लें, इस दिशा में कदम बढ़ाने में आन्ध्रप्रदेश की हमारी पार्टी इकाइयों को कामयाबी हासिल हो, यही हमारी आशा है।✶

इराकी जनता का बहादुराना प्रतिरोध
छटपटाहट में अमेरिकी साम्राज्यवाद

इराकियों को आजादी दिलवाने के बहाने अमेरिका के नेतृत्व में गठबन्धन सेनाओं द्वारा इराक के खिलाफ छेड़े गए अन्यायपूर्ण युद्ध के अब डेढ़ साल पूरे हो गए। दो, तीन सप्ताहों में इराक पर कब्जा कर लेने की डींग मारने वाले बुश ने 1 मई 2003 को नाटकीय ढंग से घोषणा की थी कि यह युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन इस घोषणा के बाद ही असली युद्ध, इराकी जनता का न्यायपूर्ण प्रतिरोधी युद्ध शुरू हुआ। इराकियों के इस महान प्रतिरोध में अब तक एक हजार से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की जानें गईं, जबकि कम से कम 6,000 सैनिक घायल हो गए। सिर्फ अप्रैल माह में ही 120 सैनिक कुत्ते की मौत मारे गए। एक दिन भी ऐसा नहीं बीत रहा है कि अमेरिकी फौजों को कोई नुकसान न हुआ हो। अबू ग़रेब जेल में इराकी कैदियों पर अमानवीय अत्याचार करके अमेरिकी साम्राज्यवादियों ने यह गलतफहमी पाल रखी थी कि इस प्रकार वे इराकियों का मनोबल तोड़ सकेंगे। लेकिन इसके उलटे इराकी ज्यादा नफरत के साथ अपने हमलों को तेज कर रहे हैं। खासकर फलूजा और नजफ शहर अमेरिकी फौजों के कब्रगाह बन चुके हैं। इराकी संघर्षकारियों ने इन शहरों को लगभग अपने आधार इलाकों में तब्दील कर लिया। इसके बावजूद भी कि अमेरिकी सेना अंधाधुंध हमले करके सैकड़ों लोगों का कत्लेआम कर रही हो, इराकी हर मकान को एक मोर्चे में बदलकर लड़ रहे हैं। पहले पहल इराकियों को हथियार डालकर आत्मसमर्पण करने की धमकियां देने वाले अमेरिकी अब संघर्षविराम के समझौते के लिए हाथ-पैर मार रहे हैं। खासकर शियाओं के धर्म गुरू मुख्तादा अल सद्र को पकड़ने के लिए वे कई पापड़ बेल रहे हैं।

मार्च 2004 में किए गए एक सर्वेक्षण के मुताबिक 52 प्रतिशत अमेरिकी सैनिकों का मनोबल बुरी तरह गिर चुका है। आफगानिस्तान और इराक युद्धों के शुरू होने के बाद से अब तक अमरिका को 3,64,000 आरक्षित बलों और नेशनल गार्ड सैनिकों को सैन्य सेवाओं के लिए बुलाना पड़ा। फिलहाल इराक में डेढ़ लाख अमेरिकी सेनाओं और कई हजार अन्य देशों की सेनाओं की तैनाती करके, दुनिया को ठगकर संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव करवाकर एक कठपुतली सरकार बिठाने के बावजूद अमेरिका की मुश्किलें घटने का आसार दूर-दूर तक नजर नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका में बहुत जल्द होने वाले राष्ट्रपति चुनाव जीतने की बुश की आकांक्षा इस युद्ध के नतीजों के चलते उलटने की संभावना नजर आ रही है।

व्यापक स्तर का विद्रोह

अप्रैल की शुरूआत से प्रतिरोधी संघर्ष तीखा हो गया। उत्तर में किरकुक में अमेरिकी बलों ने इराकी प्रदर्शनकारियों को गोली मार दी तो उसके जवाब में विद्रोहियों ने पुलिस को गोली मार दी। दक्षिण के बस्रा में विद्रोहियों ने मुनिसिपल कार्यालयों पर कब्जा करके तेल के पाइप लाइनों को उड़ा दिया। इराक में हर तरफ विद्रोह व्यापक रूप से फैल गया। अप्रैल में बग्दाद के निकट एक एहेच-64 अपाचे फौजी हेलिकाप्टर को मार गिराया गया। बस्रा के तेल केन्द्र के निकट तालमेल के साथ किए गए आत्मघाती हमलों में तीन अमेरिकी नौसैनिक मारे गए।

कुत और कुफा शहरों पर पूरी तरह और नजफ पर आंशिक रूप से अल सद्र के नेतृत्व वाली मेहदी सेना का नियंत्रण कायम हो गया। शियाओं की इस विद्रोही सेना ने बग्दाद के सुदूर पूर्वोत्तर में स्थित बखूबा में अमेरिकियों के साथ संघर्ष किया। कई शहरों में पुलिस थानों पर हमले करके हथियार छीनकर जनता में बांट दिए।

अमेरिका की सैन्य कार्रवाइयों के उप निर्देशक जनरल किम्मिट ने मान लिया कि मार्च 2004 से औसतन रोजाना 28 हमले हो रहे हैं और अब विद्रोह नई बुलंदियों पर पहुंच गया है। आमतौर पर आशावादी नजर आने वाला विदेश मंत्री जैक स्ट्रॉ को यह कबूल लेना पड़ा, "प्रेज़र कुकर से ढक्कन बाहर फेंका गया।" गौरतलब है कि स्ट्रॉ ने यह भी स्वीकार किया कि इस विद्रोह का नेतृत्व खुद इराकी कर रहे हैं न कि "विदेशी ताकतें।" 11 अप्रैल को बुश ने मान लिया कि दुराक्रमणकारियों के लिए एक "कठिन सप्ताह" गुजर गया।

समूचे इराक में विद्रोह उभार पर है। विद्रोहियों ने राजधानी बग्दाद के परिसर में एक अमेरिकी तेल काफिले पर घात लगाकर हमला करके उसे जला डाला। 10 अप्रैल को बग्दाद के एक पुलिस थाने पर हमला बोल दिया। बखूबा में विद्रोहियों और दुराक्रमणकारी सेनाओं के बीच तीखा संघर्ष हुआ। शिया विद्रोहियों ने दो दिन की लड़ाई के बाद कुत शहर पर कब्जा पा लिया जो कि इराक के मध्य में स्थित है। वहां तैनात उक्रेइनी सेनाओं को मार भगाकर उन्होंने यह उपलब्धी हासिल की। देश के व्यापक इलाके गठबन्धन सेनाओं के लिए असुरक्षित बन गए। छोटी पर हजारों कार्रवाइयां बिना रुके जारी हैं – निशाना साधकर मारना (स्नाइपिंग), बम हमले, रेड, सरकारी सम्पत्तियों पर कब्जा करना, इत्यादि। कर्बला में संघर्ष बिना रुके जारी है। खुद दुराक्रमणकारी

सेनाओं के अधिकारी यह स्वीकार कर रहे हैं कि विद्रोह में भाग लेने वाले लोगों की संख्या आए दिन बढ़ती जा रही है।

बंधक प्रकरण

इराक में हाल के दिनों में विभिन्न देशों के सैनिक व गैर-सैनिक लोगों को बंधक बनाना संघर्ष का एक व्यापक स्वरूप बन गया है। 17 अप्रैल को विद्रोहियों ने तीन जापानियों को बंधक बनाकर मांग की कि इराक से जापानी बल वापिस जाएं। हालांकि जापान ने अपने अड़ियल रवैए से इस मांग को ठुकरा दिया, फिर भी इराकी छापामारों ने उन्हें सकुशल छोड़ दिया। यहां गौरतलब है कि रिहा होने वालों में से एक नोबुटका, जोकि मानवाधिकार कार्यकर्ता है, ने अदालत में मामला दर्ज किया कि इराक में उनकी जान के लिए जो खतरा पैदा हुआ था उसके लिए जापानी सरकार जिम्मेदार है। दूसरी बार विद्रोहियों ने दो जापानियों का अपहरण करके उनकी मांग पूरी न होने पर मार डाला। फिलिप्पीन्स के दो नागरिकों को बंधक बनाकर इराक से फिलिप्पीन्स की सेनाओं की वापसी की मांग की। जनता के दबाव से फिलिप्पीन्स सरकार को यह मांग माननी पड़ी। सितम्बर के आखिरी सप्ताह में विद्रोहियों ने कुछ अमेरिकियों और ब्रितानियों को बंधक बनाकर इराकी जेलों में बंद महिला कैदियों की रिहाई की मांग की। इस बेहद जायज मांग को ठुकराकर अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ही अपने नागरिकों की हत्या के जिम्मेदार बन गए। बंधक बनाकर विद्रोही वीडियो फिल्मों के जरिए बाहरी दुनिया को अपनी मांगों से अवगत करवा रहे हैं। टीवी, इंटरनेट इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बेहतर उपयोग करते हुए विद्रोही साम्राज्यवादियों के इन औजारों को उन्हीं के खिलाफ पलटा रहे हैं। वे विभिन्न देशों के प्रति अलग-अलग और भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हुए बहुतेरे लोगों को छोड़ रहे हैं जबकि कुछ लोगों की हत्या कर रहे हैं। खासकर अमेरिकी नागरिकों की निर्मम हत्या कर रहे हैं। अमेरिकी सैनिकों को खाना पहुंचाने वाली ठेकेदारी कम्पनी में पेट पालने के लिए काम करने गए हुए नेपाली मजदूरों की हत्या जैसी कुछ अवांछित घटनाएं घटने के बावजूद आमतौर पर यह कहा जा सकता है कि इराकी विद्रोही अपने दावपेंचों पर सुचारू रूप से अमल कर रहे हैं। बंधकों की हत्या पर हाय-तौबा मचाने वाले लोग यह नहीं देख पा रहे हैं कि अबू ग़रेब जेल में इराकियों पर अमेरिकी सैनिकों द्वारा किए गए अमानवीय अत्याचारों और इस तरह की बेहिसाब यातनाओं के बदले में ही इराकी इस प्रकार जायज हिंसा करने को बाध्य हो गए हैं। इराक में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों द्वारा लिया जा रहा हर फैसला और अमल की जा रही हर कार्रवाई नाजायज, अमानवीय और बर्बर हैं। जबकि इसके जवाब में इराकियों द्वारा की जा रही हर कार्रवाई – अपवादस्वरूप चंद घटनाओं को छोड़कर – जायज और समुचित है। बंधकों की सिर कलम करके हत्या करना, फलूजा के परिसर में कुछ अमेरीकी ठेकेदारों को बोटियों में काट कर पुल पर लटका देना इत्यादि घटनाएं पिछले कई सालों से अमेरिका द्वारा इराक पर किए जा रहे अमानवीय हमलों, अत्याचारों और कत्लेआमों के बदले में ही घट रही हैं।

दुराक्रमणकारी सेनाओं का गिरता मनोबल

जबसे इराक पर दुराक्रमण किया गया तबसे अमेरिकी सेनिकों का मनोबल लगातार गिरता जा रहा है। कहां, कब मौत होगी किसी को मालूम नहीं है। वे यह भी नहीं जानते कि वे किस लिए और किसके लिए लड़ रहे हैं। ऐसी अनिश्चित व असुरक्षित माहौल में किसी भी भाड़े की सेना की स्थिति ऐसी ही होगी। हालांकि बुरी तरह गिरते मनोबल को उबारने के लिए दुराक्रमणकारी सेनाओं के आला अफसर लगातार अपने बलों से मुलाकात कर रहे हैं, फिर भी इसका कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है। पेन्टगॉन ने खुद ही यह स्वीकार किया कि 72% फौजी इकाइयों का मनोबल काफी खराब है। इससे भी बदतर यह है कि अमेरिकी सैनिकों को अब अपने कमाण्डरों पर से विश्वास उठ चुका है। आत्महत्या की घटनाएं बढ़ी हैं। इसके पहले आत्महत्याओं की दर प्रति लाख 11.9 थी जो 2003 में 15.6 तक बढ़ गई। अब तक 30 से ज्यादा सैनिकों ने मानसिक तनाव के चलते आत्महत्या कर ली। ईस्टर त्यौहार के मौके पर इटली का राज्याध्यक्ष सिल्वियो बेरलुस्कोनी का दौरा भी गठबन्धन सेनाओं में आत्मविश्वास जगा नहीं सका। अबू ग़रेब जेल में हुए अत्याचारों के उजागर होने के बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री ने गुप्त रूप से दौरा किया, फिर भी इससे स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। खासतौर पर अप्रैल से प्रतिरोध में आई तेजी ने गठबन्धन सेनाओं के नाक में दम कर रख दिया। गठबन्धन सेनाओं के साथ-साथ अमेरिका द्वारा नियुक्त इराकी सुरक्षा बलों, पुलिस व अमेरिका के लिए चोरी-छिपे दलाल का काम कर रहे देशद्रोहियों को किसी भी इराकी विद्रोही नहीं बख्श रहे हैं। अमेरिका के लिए सिरदर्द का एक और विषय यह है कि जब इराकी विद्रोहियों के साथ इराकी सुरक्षा बलों की भिड़ंत होती है तो वे अपना हाथ उठाकर विद्रोहियों के पक्ष में जा मिल रहे हैं। इसलिए अमेरिका जिन इराकियों को भर्ती कर रहा है उन्हें भारी हथियारों के बजाए हल्के हथियार ही दे रहा है। इससे वे विद्रोहियों के हाथों आसानी से मात खा रहे हैं।

इराकियों के प्रतिरोध से अमेरिकी मेरैनों के हौसले पस्त

शुरू-शुरू में इराकी विद्रोह को कुछ भूतपूर्व बाथवादियों और सद्दाम के सहयोगियों द्वारा की जा रही छिटफुट कार्रवाइयां कहकर नकारने वाले अमेरिकी साम्राज्यवादियों को अब यह मानना पड़ रहा है कि यह दुराक्रमण के खिलाफ जनता द्वारा जारी एकजुट संघर्ष है। विभिन्न संगठनों की अगुवाई में जारी इराकी प्रतिरोधी संघर्ष को बदनाम करने के लिए अमेरिका अक्सर यह गलत प्रचार कर रहा है कि विदेशी उग्रवादी इराक में घुसकर हमले कर रहे हैं। लेकिन सचाई यह है कि खुद अमेरिका ही भाड़े के सुरक्षा बलों को ठेके पर लाकर खासकर सुरक्षा की जिम्मेदारी में नियुक्त कर रहा है। इसमें लातिनी अमेरिकी देशों और भारत समेत कई अन्य एशियाई देशों से निजी सुरक्षा संस्थाओं में भर्ती होकर काम करने वाले लोग हैं। इस प्रकार, अमेरिका अपने सैन्य नुकसानों को टालने के लिए युद्ध का भी निजीकरण कर रहा है। फिलिस्तीनी जनता के विद्रोह को क्रूरता से कुचलने में काफी अनुभव प्राप्त इज़्राएली सैन्य अधिकारी अमेरिकी बलों को विद्रोह-विरोधी कार्यनीति में प्रशिक्षण दे रहे हैं। इतना ही नहीं, इज़्राएली खुफिया अधिकारी कुर्द कमांडों को गुप्त रूप से प्रशिक्षण दे रहे हैं ताकि इराकी प्रतिरोध का नेतृत्व व मार्गदर्शन कर रहे नेताओं का सफाया करवाया जा सके।

सिर न झुकाता फलूजा

शुरू से ही फलूजा शहर इराकी विद्रोहियों का मुख्य गढ़ रहा है। पिछले अप्रैल माह में अमेरिकी बलों ने इस शहर के निवासियों का कत्लेआम किया था। दुराक्रमण, अंधाधुंध गिरफ्तारियां, हत्याएं, यातनाएं, आदि के खिलाफ भड़के गुस्से और नफरत की आग को यहां की जनता के संघर्षों में प्रतिबिम्बित होता हुआ देखा जा सकता है। ब्लैकवाटर सेक्यूरिटी कन्सल्टिंग नामक कम्पनी की तरफ से काम कर रहे चार ठेकेदारों को 31 मार्च को विद्रोहियों ने एक ऐम्बुश में मार गिराया। पेन्टागॉन की ओर से काम करने वाली यह कम्पनी अमेरिकी बलों को खाना सप्लाई करने वाले काफिलों को सुरक्षा मुहैया करवाती है। ये लोग जब एक अमेरिकी बेस से बाहर आकर शहर में घुसे तो इराकी योद्धाओं ने ग्रेनेडों से इन पर हमला करके मार डाला। उसके बाद शहर की जनता उनके कारों पर टूट पड़ी। उनकी लाशों को जनता ने घसीटते हुए ले जाकर बोटियों में काट डाला और खंबों से लटकाकर अमेरिकी साम्राज्यवाद के प्रति अपनी तीखी नफरत का इज़हार किया। उसी दिन फलूजा से 15 किलोमीटर दूर स्थित हब्बानिया सड़क के किनारे लगाए एक बम फटने से पांच अमेरिकी सैनिक कुत्तों की तरह मारे गए थे।

इन कार्रवाइयों का बदला लेने के इरादे से 4 अप्रैल को 1,300 अमेरिकी मेरैन सैनिक इस क्षेत्र में उतारे गए। विद्रोह का गढ़ बन चुके फलूजा पर नियंत्रण पाने के लिए भेजी गई तीसरी अमेरीकी सैन्य टुकड़ी थी वह। उन्होंने फलूजा की घेराबन्दी करके कर्फ्यू लागू कर घरों पर लगातार छापेमारियां ओर गिरफ्तारियां शुरू कीं। इसके बावजूद दो दिन बाद भी वे सिर्फ शहर के एक चौथाई के आधे हिस्से पर ही कब्जा जमा सके। एक पखवाड़े तक संघर्ष जारी रहा। मेरैनों ने हेलिकाप्टरों और युद्ध विमानों के जरिए घरों के कतारों पर अंधाधुंध गोलीबारी व गोलाबारी की। एक मस्जिद पर एफ-16 विमानों के हमले में 40 लोगों की जानें गईं। पूरे शहर को कब्जे में लेने की सैनिकों ने जी-तोड़ कोशिश की। घण्टों तक चली आमने-सामने की लड़ाइयों में 50 अमेरिकी मेरैन सैनिक मारे गए। उनकी मदद में भेजे गए इराकी पुलिस बल 'लापता' होकर विद्रोहियों के पक्ष में शामिल हो गए। 12 अप्रैल को स्थानीय इराकियों से गठित 12वीं बटालियन के 620 सैनिकों को फलूजा भेजा गया था। जब वे एक शिया बहुल बस्ती से गुजर रहे थे तो उन पर गोलियां बरसाई गईं जिससे वे भागकर उत्तर इराक के ताजि में मौजूद अपने बटालियन के बेस में लौट गए।

इस पूरे संघर्ष में अमेरिकी बलों ने 600 लोगों की हत्या करके 1,250 लोगों को घायल कर दिया। इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे ही थे। इराक पर दुराक्रमण के बाद किए गए घोरतम कत्लेआमों में यह एक था। अब फलूजा दुराक्रमणकारी सेनाओं के खिलाफ धारदार जन प्रतिरोध का संकेत बन गया। अमेरिका की क्रूरतापूर्ण कत्लेआम की नीति की हर तरफ जमकर निंदा की गई।

चार निजी सैनिकों की मौत के बाद घमण्डी पाल ब्रेमर ने इसका बदला लेने की बात की। इसका अर्थ है वे और ज्यादा कत्लेआम कर सकते हैं। लेकिन बाद में उसे अपमान का घूंट पीकर संघर्ष विराम करके अमेरिकी मेरैनों को फलूजा से पीछे हटाकर ग्रामीण इलाकों में भेजना पड़ा। इस प्रकार फलूजा में छेड़ा गया 'ऑपरेशन फौलादी संकल्प' अमेरिकी मेरैनों के महान पीछे कदम के रूप में समाप्त हुआ। फलूजा संघर्ष ने इराक को बेहद प्रभावित किया। उसने शिया और सुन्नी लोगों के बीच अभूतपूर्व स्तर पर जबर्दस्त एकता को उभारा। दुराक्रमणकारियों के भड़काने के बावजूद इन दो समुदायों के बीच एकता विकसित होना काफी महत्वपूर्ण पहलू है। बग्दाद में हुई एक लड़ाई में शिया और सुन्नी विद्रोहियों ने मिलकर भाग लिया जिसमें तीन अमेरिकी सैनिक मारे गए। लगभग एक हजार शिया लोगों ने कई कारों में सवार होकर अपने साथ खाना और दवाएं लेकर फलूजा में मार्च किया। "सुन्नी-शिया का भेदभाव हम नहीं करेंगे... इस्लामिक एकता जिन्दाबाद... हम शिया-सुन्नी भाई-भाई हैं... अपने देश को कभी नहीं बेचेंगे" आदि लोगों के लगाए नारे रणानाद बनकर गूंज उठे। फलूजा में रहने वाले एक पत्रकार अब्दुल रजाक अल जोरबी ने कहा, "हर गली में संघर्ष छिड़ गया। गलियों में हर आदमी रॉकेट प्रेफेल्ड ग्रेनेड, कलाश्निकोव रायफल, मशीनगन, आदि किसी न किसी हथियार से लैस था। हर इन्सान एक योद्धा बन गया।" इस संघर्ष ने इराकियों के प्रतिरोध को बेहद स्फूर्ति प्रदान की।

दक्षिण व मध्य इराक के शिया इलाकों में संघर्ष का दूसरा मोर्चा

फलूजा को कुल समस्या का आधा हिस्सा ही कहा जा सकता है। जब ठीक "ऑपरेशन फौलादी संकल्प" शुरू हो रहा था तभी दूसरे जंगे मैदान में लड़ाई का बिगुल बज गया। शियाओं का युवा धर्म गुरू 30 वर्षीय मुख्तदा अल सद्र अब इस बहादुराना प्रतिरोधी संघर्ष के आदर्शपूर्ण

नजफ में मोर्टार दागते मेहदी सेना के लड़ाकू

नेता के रूप में सामने आए। चार साल पहले सद्दाम के हाथों मारे गए एक लोकप्रिय धर्म गुरू का बेटा ही अल सद्र हैं। पिछले साल उन्होंने मेहदी सेना के नाम से एक मिलिशिया का निर्माण किया जिसमें उन्होंने हजारों लोगों को भर्ती किया। इराकी प्रशासनिक परिषद के अध्यक्ष रहे पाल ब्रेमर ने अल सद्र के निकट सहयोगी को गिरफ्तार करके उनके तेजतर्रार अखबार को बन्द करवा दिया। अमेरिका के अनुकूल रहने वाले एक उदारपंथी शिया धर्म गुरू की पिछले साल हुई हत्या के मामले में अल सद्र को दोषी करार देते हुए ब्रेमर ने उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया। इससे अल सद्र सड़कों पर आकर अपने साथियों को अमेरिका के खिलाफ 'जेहाद' छेड़ने का आह्वान दिया। बग्दाद के सद्र सिटी में अमेरिकी बलों के साथ संघर्ष शुरू हुआ। दक्षिण व मध्य इराक के कई शहरों को मेहदी सेना ने मुक्त करके अपने कब्जे में लिया। अब वह अपने सैकड़ों योद्धाओं की सुरक्षा में हैं। अगस्त के दूसरे सप्ताह से एक माह तक अमेरिका ने नजफ में भयानक हमले किए। कथित तौर पर अल सद्र द्वारा शरण लिए हुए इमाम अली दर्गाह को मुक्त करने के बहाने अमेरिका ने बर्बरतापूर्ण हमले किए जिसमें सैकड़ों बेकसूर लोग मारे गए। सद्र को मारने, उनकी सेना को निहत्था बनाने और नजफ पर कब्जा करने की अमेरिका की लाख कोशिशों के बावजूद उसे कामयाबी नहीं मिली। वह निडरता के साथ मांग कर रहे हैं कि अमेरिकी सेनाएं वापिस जाएं। उन्हें अंतरिम सरकार में जगह देने की पेशकश करके प्रलोभन में फंसाने के लिए अमेरिका द्वारा की गई सारी कोशिशें अब तक नाकाम रहीं। "जंगी विमानों की आवाज से खौफ न खाएं, निडरता से खड़े रहें" कहकर वे संदेश दे रहे हैं जिससे लोग काफी प्रभावित हो रहे हैं। नजफ और कुफा शहरों में अमेरिका ने वीभत्सपूर्ण हमले किए। इसके बवजूद इन्हें अपने कब्जे में लेने में वह बुरी तरह नाकाम हुआ। अमेरिका ने नजफ में विमानों से बम बरसाकर सैकड़ों योद्धाओं का कत्ल किया। कुफा में 67 मिलिशिया योद्धाओं को गोली मार दी। इनके अलावा कई अन्य बेकसूर लोगों की जानें लीं। फिर भी अभी तक नजफ पर अमेरिका की पकड़ नहीं बन पाई। अल सद्र के नेतृत्व में मेहदी सेनाओं ने मुख्य रूप से दक्षिणी इराक में शानदार विद्रोह चलाया। बुल्गारिया, पोलैण्ड, स्पेइन, उक्रेइन और अमेरिका की भाड़े की फौजों को मुंहतोड़ जवाब दिया।

अन्तहीन संकट में अमेरिका

इराक पर हुए हमले को एक साल पूरा होने के उपलक्ष्य में शियाओं और सुन्नियों ने एकजुटता के साथ प्रतिरोध में तेजी लाई। एक ओर अमेरिका पर दबाव बढ़ने लगा। उसके सारे अनुमान उलट जाने से उसका खर्च बेहिसाब बढ़ गया। अब तक इस युद्ध पर अमेरिका ने 151.1 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च किया। अमेरिकी जनता पर अंधाधुंध कर लगाकर और सामाजिक कल्याण के खर्च में भारी कटौतियां करके अमेरिका सरकार यह राशि जुटा रही है। इससे अमेरिकी जनता में विरोध बढ़ रहा है। इराक का तेल लूटकर मुनाफा कमाने की आशाएं फिलहाल तो पूरी न हो पा रही हैं, जो इस युद्ध के लक्ष्यों में एक है। अमेरिका द्वारा थोपे गए सारे प्रतिबन्धों को सहकर भी सद्दाम जितना तेल निकालता था उतना भी अमेरिका निकाल नहीं पा रहा है। पाइप लाइनों पर निरन्तर हो रहे हमलों ने इस कोशिश को सीमित कर रखा है। इराक के पास मानव विनाशक हथियार होने और अल कायदा के साथ उसके सम्बन्ध होने के जो बहाने अमेरिका ने बताए वे सब जनता में सफेद झूठ साबित हो चुके हैं। इससे दुनिया की जनता में, खास कर अमेरिकी और ब्रितानी जनता में बेहद असंतोष बढ़ गया। बुश और ब्लेइर को अपने-अपने देशों में और दुनिया के दूसरे देशों के दौरों के मौके पर लाखों लाख लोगों के विरोध प्रदर्शन झेलने पड़ रहे हैं। स्पेइन में हुए चुनावों में अज़नार के नेतृत्व वाली दक्षिणपंथी पार्टी पराजित हुई। सत्तारूढ़ हुई नई पार्टी ने अपने चुनावी वादे को अमली जामा पहनाते हुए इराक से अपनी सेनाओं को वापिस बुलाया। फिलिप्पीन्स समेत कुछ अन्य देशों की सरकारों ने भी अपने-अपने देशों में संभावित राजनीतिक संकट को टालने के लिए अपनी फौजों को इराक से बुला लिया। सर्वेक्षणों के मुताबिक अगले कुछ महीनों में अमेरिका और ब्रिटेन में होने वाले चुनावों में बुश और ब्लेइर की पराजय निश्चित है। इससे इस संकट को किसी भी तरह टालकर अपनी चुनावी सम्भावनाओं को बेहतर बनाने की मंशा से बुश-ब्लेइर जोड़ी एड़ी-चोटी का जोर लगा रही है। इराक युद्ध में बुरी तरह डूब चुके अमेरिका के अपने सैन्य नुकसानों और खर्च से बचने के सारे प्रयास आंशिक तौर पर ही सफल रहे। जबकि 20 हजार सैनिकों की बदली करना था तो इस संख्या को भर्ती करने के लिए उसे कई पापड़ बेलने पड़े। कम संख्या में ही सही अमेरिकी सैनिकों के भागने की घटनाएं शुरू हुईं। पेन्टगॉन पर सैन्य बलों के लिए बढ़ रहे दबाव के चलते वह घायल सैनिकों को पर्याप्त आराम दिए बिना ही थोड़ा ठीक होने के बाद युद्ध में भेजा जा रहा है, इसके बावजूद कि डॉक्टर ऐसा करने से मना कर रहे हैं। दूसरी ओर अमेरिकी सैनिकों के परिवार सदस्यों से यह मांग लगातार उठ रही है

"चोरी हुए छह महीनों के बाद...

कुत्ता भौंका" – ऐसी एक लोकोक्ति है। लेकिन इराक पर अमेरीकी-ब्रितानी बलों द्वारा अन्यायपूर्ण तरीके से किए गए दुराक्रमण का खण्डन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के महा सचिव कोफी अन्नान को छह महीने नहीं, बल्कि डेढ़ साल लगे। गत सितम्बर के आखिरी सप्ताह में संयुक्त राष्ट्र संघ की आमसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने इराक पर किए गए हमले को अन्यायपूर्ण कहा। लेकिन तब तक इराक में हजारों बेकसूर लोगों की जानें गईं और कई हजारों लोग स्थाई रूप से अपंग बन गए। अनगिनत लोग अपनी सारी सम्पत्तियां गंवाकर बेघरबार हो गए। इतनी घोर तबाही के बाद ऐसी घोषणा करके अन्नान किसे संतुष्ट करना चाहते हैं? यह सभी को मालूम है कि अमेरिका के दबाव में इराक पर प्रतिबन्ध लागू करने में सक्रियता बरतने वाला संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसके कई प्रस्तावों का खुला उल्लंघन करने वाले इज़ाएल या उसके प्रस्ताव के बिना ही इराक पर एकतरफा हमला बोल देने वाले अमेरिका के खिलाफ आज तक कोई कदम नहीं उठाया। इससे दुनिया की जनता यह साफ तौर पर समझ गई कि संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी साम्राज्यवादियों का औजार भर है। अब अन्नान का पछतावे के अंदाज में यह टिप्पणी करना ऐसे लोगों में फिर से भरोसा जगाने की बेईमान कोशश ही है जिनका अब संयुक्त राष्ट्र संघ पर कोई भरोसा नहीं रह गया है। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ में सचमुच ही ईमानदारी या निष्पक्षता मौजूद हैं, जैसा कि वह खुद कहता है, क्या वह अमेरिका को इस अपराध के लिए न्याय के कटघरे में खड़ा कर सकेगा? क्या वह बुश, ब्लेइर, अज़नार, होवार्ड, रम्सफेल्ड, डिक, स्ट्रॉ, शेरोन आदि को युद्ध अपराधी घोषित कर उन पर न्यायिक मुकदमा चलाने की मांग उठाएगा? ✶

कि उनके बच्चों को वापिस लाया जाए। कुल मिलाकर इराक पर बुश की नीतियों के प्रति तीखा विरोध हो रहा है। इससे पिछले अगस्त माह में बुश ने यूरोप और एशियाई देशों में मौजूद सैनिकों में से 70 हजार सैनिकों को वापिस लाने की घोषणा करके अमेरिकी मतदाताओं को संतुष्ट करने की कोशिश की। शीत युद्ध के बाद से इस प्रकार का फैसला अमेरिका ने पहली बार लिया है।

अबू ग़रेब जेल में हुए अत्याचारों और इराक के पास व्यापक विनाश के हथियार होने के झूठे आरोपों से इराकी प्रशासनिक परिषद की घनघोर बदनामी हुई है। किसी भी तरह एक कठपुतली सरकार की स्थापना किए बिना युद्ध का बोझ संयुक्त राष्ट्र संघ पर थोपना संभव नहीं होगा, यह सोचकर अमेरिका कठपुतली सरकार की स्थापना के लिए उतावला हो गया। लेकिन खुद उसका पालतू कुत्ता अहमद चलाबी "पूर्ण प्रभुसत्ता" की मांग पर अड़ गया तो अमेरिका को उसे कठपुतली सरकार के मुखिया बनाने के प्रस्ताव को वापिस लेना पड़ा। कल तक अमेरिका का तलवे चाटने वाला चलाबी एक ही झटके में अमेरिका का घोर दुश्मन बन गया। इससे उसने सीआईए का मुखबिर और अमेरिका का एक और वफादार कुत्ता इयाद अलावी को कठपुतली सरकार का मुखिया बनाने का फैसला लिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव के बिना ही इराक पर हमला करने वाले घमण्डी अमेरिका को कठपुतली सरकार बिठाने के लिए उसका प्रस्ताव जरूरी हो गया। लेकिन उसे अपने प्रस्ताव को पारित करवाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। पांच बार अपने मसौदे में फेर-बदल करने पड़े।

आनन-फानन में बनी कठपुतली सरकार

वफादार दलाल चलाबी के साथ रिश्ता टूटने के बाद इयाद अलावी के नेतृत्व में अन्तरिम सरकार के नाम से एक कठपुतली सरकार की स्थापना करने का फैसला लिया गया। याद रहे, ठीक इसी तरीके से अफगानिस्तान में हामिद करजई के नेतृत्व में एक कठपुतली सरकार का गठन किया गया था। इराक के दुधमुंहे बच्चे भी यह जानते हैं कि अलावी सीआईए का कट्टर मुखबिर और बदनाम हत्यारा है। इसके अलावा कठपुतली सरकार में जिन-जिन लोगों को नियुक्त किया गया वे सब इसी प्रकार के बदनाम दलाल और हत्यारे हैं। दूसरी ओर इस सत्ता परिवर्तन को झूठा करार देते हुए इराकी विद्रोहियों ने अपने प्रतिरोधी संघर्ष में जून के आखिरी सप्ताह के आते-आते काफी तेजी और तीव्रता लाई। सुरक्षा परिषद के स्थाई सदस्य फ्रांस, जर्मनी और रूस के द्वारा उठाई गई आपत्तियों के चलते पांच बार बदले गए प्रस्ताव को अमेरिका और ब्रिटेन ने पेश किया तो सुरक्षा परिषद ने पारित किया। इस प्रस्ताव के मुताबिक इराक को अमेरिका की देखरेख में पूर्ण "प्रभुसत्ता" दी जाएगी। शियाओं के धार्मिक नेता मुख्तदा अल सद्र ने इसका कड़ा विरोध किया। सुन्नी बहुल "इस्लामिक फ्रन्ट फॅर इराकी रेसिस्टेन्स" नामक संगठन ने अलावी के नेतृत्व वाली सरकार को "नकाबपोश दुराक्रमण" करार दिया।

30 जून को इराकी प्रशासनिक परिषद से पाल ब्रेमर के हाथों से इयाद अलावी को सत्ता सौम्पा जाना था। इस भव्य समारोह में "मुक्ति दाता" जार्ज बुश को भी आमंत्रित करना तय हुआ था। लेकिन इराकियों के प्रतिरोध से डरकर घोषित तारीख को चुपचाप तीन दिन पीछे बदलकर सत्ता परिवर्तन की रस्म चोरी-छुपे पूरी करा दी गई। पाल ब्रेमर की जगह अमेरिकी राजदूत के ओहदे से जॉन नीग्रोपोन्ट ने ली। "उग्रवाद-विरोधी कार्रवाइयों" के विशेषज्ञ के तौर पर इराक में कदम रखने वाले पाल ब्रेमर को आखिरकार बिना किसी को सूचित किए मुंह छुपाकर इराक से लौटना पड़ा। जब साफ तौर पर पूरा देश ही अमेरिकी दुराक्रमण और कठपुतली सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया हो, तब इसके अलावा चारा भी क्या होगा? इराक में अमेरिका ने 3,000 कर्मचारियों के साथ एक विशालकाय दूतावास बनाया जैसा कि दुनिया में कहीं नहीं है। अब यह कार्यालय ही कठपुतली सरकार को नियंत्रित करेगा। लगभग डेढ़ लाख सेना के सहारे वह जनता के गुस्से के शोलों से कठपुतली सरकार को बचाने की कोशिश करता रहेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के मुताबिक सात माह के भीतर इराक में चुनाव सम्पन्न कराना होगा। लेकिन अब तक मिल रही खबरों के मुताबिक चुनावों के मौके पर इराक में व्यापक पैमाने पर प्रतिरोधी संघर्ष भड़क सकता है। देश के व्यापक इलाकों में चुनाव नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन अमेरिका किसी भी तरह इस रस्म को पूरा कर सकता है ताकि

बाहरी दुनिया को धोखा दिया जा सके, जैसा कि हमारे देश में कश्मीर में होता है। इराक में जब तक अमेरीकी फौजें तैनात रहेंगी तब तक चाहे सरकार में कोई भी रहे पर वह स्वतंत्रता नहीं कहलाएगी। उसे कोई प्रभुसत्ता नहीं होगी। यह बात संघर्षशील इराकी जनता अच्छी तरह जानती है।

प्रतिरोध बिना रुके जारी

अमेरिका ने आशा की थी कि इराक में उसकी सेनाओं का स्वागत मुक्ति दाताओं के रूप में किया जाएगा। उसका भरोसा था कि बाथ सरकार के अधिकारियों और सद्दाम की गिरफ्तारी के बाद इराक उसके नियंत्रण में आ जाएगा। अब अमेरिका का यह कहना बिलकुल झूठ है कि उसने इराक को प्रभुसत्ता दी है। इस प्रश्न का अभी भी संतोषजनक व स्पष्ट उत्तर नहीं दिया जा रहा है कि अमेरिकी सैन्य बल इराक में कब तक रहेंगे। इराकी जनता इस झूठी आजादी को मान्यता देने को कतई तैयार नहीं है। इराकी ऐलान कर रहे हैं कि जब तक उनकी धरती से विदेशी सेनाएं वापिस नहीं जाएंगी तब तक प्रतिरोध जारी रहेगा। अमेरिकी सेनाओं की देखरेख में कठपुतली सरकार द्वारा की जा रही चुनाव की तैयारियों का वे ढोंग करार देकर मजाक उड़ा रहे हैं। इराकी जनता के प्रतिरोध-संघर्ष ने यह ऐतिहासिक सचाई फिर एक बार साबित की कि अपेक्षापूर्ण कमजोर ताकत भी शक्तिशाली ताकत से टक्कर ले सकती है और उसके नाक में दम कर सकती है। 19वीं सदी के शुरूआती दिनों में हैती में सफल हुई गुलामों की बगावत से लेकर माओ त्से-तुङ के नेतृत्व में सम्पन्न चीनी क्रान्ति तक, एक हद तक 1950 और 1960 के दशकों में हुए उपनिवेशवाद-विरोधी युद्धों में भी, फिलहाल नेपाल में जबर्दस्त ढंग से जारी जनयुद्ध में इतिहास ने यह बारम्बार साबित किया है कि एक न्यायपूर्ण लक्ष्य के साथ जनता पर निर्भर करते हुए लड़ने वाली छापामार शक्तियां संघर्ष के दौरान एक सेना के रूप में उभरेंगी और शुरू में अपने से गई गुना शक्तिशाली रहे दुश्मन को हरा सकेंगी।

लेकिन इराकी छापामार शक्तियों में ऐसे नेतृत्व, जोकि रणनीतिक लक्ष्यों का सूत्रीकरण कर जनता को एकजुट करने की क्षमता रखता हो, और समुचित सैन्य रणनीति-कार्यनीति का अभाव है। इसका मतलब एक सही लाइन अपना सकने वाली एक नेतृत्वकारी संस्था, यानी एक मार्क्सवादी-लेनिनवादी-माओवादी अगुवा दस्ता इराक में नहीं है। सिर्फ वही उस देश की, तमाम मध्य-पूर्व इलाके की तथा समूची दुनिया की जनता के हितों की वास्तविक रूप से अभिव्यक्ति कर सकती है। आखिरकार वही शक्ति संतुलन को बदल सकेगी। पर यह सच है कि इराकी जनता के महान प्रतिरोधी संघर्ष ने "नई अमेरिकी सदी परियोजना" को यकीनन जोरदार धक्का दिया। दूसरी तरफ अफगानिस्तान भी खुद को यह साबित कर रहा है कि वह अमेरिका द्वारा थोपे गए "विशाल मध्य-पूर्व" ढांचे में नहीं फंसा है। अफगान में अमेरिकी बलों पर हमले तेज हो रहे हैं। और इधर नेपाल, भारत, फिलिप्पीन्स, पेरू, तुर्की, आदि देशों में माओवादियों के नेतृत्व में जनयुद्ध अमेरिकी साम्राज्यवादियों की साजिशों को नाकाम बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। साम्राज्यवाद के खिलाफ उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं और जनता का अन्तरविरोध तीखा हो रहा है। इन संघर्षों का नतीजा ही है कि दुनिया की जनता का नम्बर एक दुश्मन अमेरिका एक साथ कई दिशाओं में अपनी ताकत केन्द्रित न कर पाने की मजबूर स्थिति में पहुंच गया है। निश्चिय ही इसमें इराकी जनता के प्रतिरोधी संघर्ष का महत्वपूर्ण योगदान है। उनकी कामयाबियां दुनिया की तमाम जनता की कामयाबियां हैं। ✶

(.... पृष्ठ 31 का शेष)

दुनिया भर में गुस्से की लहर

इन पाशविक (हालांकि यह पाशविकता से भी बदतर है) अत्याचारों के खिलाफ दुनिया भर में गुस्सा और नफरत की आग फैल गई। यह दबाव बढ़ गया कि गठबन्धन सेनाएं इराक छोड़ दें। 5 मई को अबू ग़रेब जेल के कैदियों के लगभग 10,000 परिवार सदस्यों ने एक प्रदर्शन करके अपने प्रिय जनों की रिहाई की मांग की। मुस्लिम देशों में और अरब जगत् में विरोध की लहर उठी।

पूर्व में कैदी रहे 19 वर्षीय अब्दुल रज्ज़ाक नामक युवक ने यह प्रश्न किया, "इस किस्म के अत्याचारों का शिकार होने के बाद हम अमेरिका से नफरत किए बिना कैसे रह पाएंगे?" शियाओं का विद्रोही नेता मुख्तादा अल सद्र ने यह कहकर अपने गुस्से का इज़हार किया, "इराकी कैदियों पर हिंसाचार करके आनन्द प्राप्त करने वाले सैडिस्टों से किस तरह का जनवाद व स्वतंत्रता की उम्मीद कर सकेंगे?"

अब निचले स्तर के अधिकारियों और आम सैनिकों के खिलाफ कोर्ट मार्शल चलाए जा रहे हैं। साफ जाहिर है कि हल्की-सी सजाओं से इन्हें छोड़ा जाएगा। पर उच्च स्तर के सैन्य अधिकारियों को तो वे छूएंगे भी नहीं। इसीलिए पारदर्शिता बरतने का ढिंढ़ोरा पीटने वाला रम्सफेल्ड अपनी गवाही के दौरान इस सवाल का जवाब देने से टाल गया कि जब इराकी कैदियों के साथ पूछताछ करते हुए हिंसाचार किया जा रहा था तब उच्च स्तर के कमाण्डर के बतौर कौन थे। दरअसल यह बात पिछले मई में खुल गई थी कि रम्सफेल्ड और रक्षा खुफिया विभाग के सहायक सचिव स्टीफेन कोम्बोन दोनों ने 2003 में ही इसकी मंजूरी दी थी कि इराक में पूछताछ के "कठोर" तौर-तरीके अपनाए जाएं। अमेरिकी सेना ने चंद कमिशन्ड और नॉन-कमिशन्ड अधिकारियों को ही निलम्बित किया। उसका कहना है कि बाकी सब ठीक-ठाक है ! हे अमेरिकी जनवाद, तुझे सलाम !!

दुनिया भर में रम्सफेल्ड के इस्तेफे की पुरजोर मांग उठी। यातनाओं के खिलाफ अन्तर्राष्ट्रीय नियम और जेनीवा समझौते के उल्लंघन के लिए उस पर युद्ध अपराधों की सुनवाई करने वाली अदालत में मुकदमा चलाया जाना चाहिए, यह मांग भी उठी। पर इराकी जनता साम्राज्यवादियों को जरूर सजा देगी। मानवजाति को शर्मसार कर देने वाली बर्बरतापूर्ण यातनाओं और अत्याचारों के दृश्यों को देख चुकी विश्व जनता, खासतौर पर इराकी जनता और भी सख्त नफरत से अमेरिकियों के खिलाफ लड़ेगी। उसकी और उसके सहयोगी देशों की सेनाओं को ऐसी मार मारकर भगा देगी जैसे कि पागल कुत्तों को खदेड़ा जाता है। वह दिन ज्यादा दूर भी नहीं है। ✶

अबू ग़रेब जेल में इराकी कैदियों पर अमेरिकी सैनिकों के अमानवीय अत्याचार

इराक को स्वतंत्रता दिलाने के बहाने उस पर हमला करने वाले अमेरिका का बेहद घिनौना चेहरा अब सामने आ गया। उसका अमानवीय चरित्र दुनिया की जनता की नजरों के सामने तस्वीरों समेत उजागर हुआ है। अबू ग़रेब जेल में इराकी नागरिकों पर अमेरिकी सैनिकों द्वारा किए गए पाशविक अत्याचारों के दृश्यों को देखकर विश्व जनता स्तब्ध रह गई। बेसहारा कैदियों के प्रति अमेरिका द्वारा अमल 'जनवाद' अब नंगा हो गया। चूंकि इन्हें इनकार करना मुमकिन नहीं है, इसलिए अमेरिकी सैन्य व प्रशासनिक अधिकारी माफी मांग रहे हैं। गिद्ध से भी बदतर रम्सफेल्ड को अपमान का घूंट पीते हुए यह मानने पर मजबूर होना पड़ा कि सैनिकों की ये कार्रवाइयां पाशविक, बर्बर और अमानवीय हैं।

नंगा करके बिजली के झटके दिए जाने का दृश्य

लेकिन, हकीकत यह है कि जनवरी के आखिर से ही इन तस्वीरों के बारे में अमेरिकी रक्षा विभाग को साफ तौर पर जानकारी थी। हालांकि उसने इसकी अंदरूनी जांच का आदेश दिया, पर उसकी तमन्ना यही थी कि तथ्यों को सेना दफ्तर की चारदीवारी के बीच ही दफना दिया जाए। लेकिन अमेरिका के कुछ टीवी चैनल और अखबार इन तस्वीरों को हासिल करने में कामयाब हो गए। उसके बाद रम्सफेल्ड और उसके अनुयायियों ने यह अपील करते हुए इन तस्वीरों के प्रसारण को टालने की पुरजोर कोशिश की कि इससे इराक में मौजूद अमेरिकी फौजों को खतरा हो सकता है। सीबीएस टीवी चैनल ने पहले तो रम्सफेल्ड की बातें मान लीं पर उन्हें तब प्रसारित किया जब उसे यह मालूम हुआ था कि वे तस्वीरें दूसरों के हाथ में भी आ गईं।

सशस्त्र बलों के अत्याचारों के सम्बन्ध में जनता को स्पष्ट और न ठुकरा सकने वाले सबूत मिलने का यह बेहद दुर्लभ मौका था। जनवादी परम्पराओं के बारे में बढ़ा-चढ़ाकर डींग हांकने वाला अमेरिका दुनिया भर में मानवाधिकारों का हिमायती होने का दिखावा करता है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय उसके अनुकूल न रहने वाले देशों में होने वाले मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में हर साल रिपोर्टें प्रकाशित करवाता है। अब इन तस्वीरों के बाहर आने के बाद विश्व मानवाधिकार रिपोर्ट के वार्षिक प्रकाशन को "तकनीकी कारणों" से स्थगित कर दिया जो कि मई में होना चाहिए था। अगर ये तस्वीरें उजागर नहीं होतीं तो उस रिपोर्ट में वह अपने रिकार्ड को बेहतर बताते हुए अपना पीठ जरूर ठोंक लेता।

रम्सफेल्ड को यह साफ तौर पर मालूम है कि हकीकत को दबाना सम्भव नहीं है। यही वजह है कि उसने अमेरिकी संसद सदनों में जुबानी गवाह देते हुए कहा कि "इससे भी दिल दहला देने वाली तस्वीरें मौजूद हैं।" सेनेट और प्रतिनिधि सभा के चुनींदा सदस्यों को लगभग 1,600 तस्वीरें दिखाई गईं। इन बेहद बर्बरतापूर्ण दृश्यों को देखकर कई लोग हक्का-बक्का रह गए। वे यह देखकर भौचक हो गए कि उनकी उन्नत मूल्यों वाली सभ्यता इस दुनिया को सभ्यता के दुश्मनों से बचाने की किस प्रकार कोशिशें कर रही है।

गॉर्डियन अखबार ने लिखा है कि अमेरिकी और ब्रितानी सैन्य बलों को सिखाए जाने वाले तरीकों से जेल में किए गए अमानवीय यौन अत्याचार मेल खाते हैं। दरअसल अमेरिकी सेना किस प्रकार कैदियों के प्रति अपमानजनक बरताव कर रही है और नियमों का उल्लंघन कर रही है, इसकी रिपोर्ट 16 माह पहले ही उजागर हुई। उस रिपोर्ट में सबूत के साथ जिक्र किया गया था कि काबुल के परिसर में स्थित बग़राम वायुसेना अड्डे में तथा डिगो गार्शिया में अमेरिकी खुफिया अधिकारी संदिग्ध व्यक्तियों को यातनाएं दे रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मीडिया ने इस रिपोर्ट को ज्यादा अहमियत नहीं दी। अमेरिकी कांग्रेस ने इसका नजरअन्दाज किया। अमेरिकी सरकार ने इसे ठुकरा दिया।

नुकसान नियंत्रण

चूंकि अमेरिकी रक्षा विभाग को पहले ही मालूम था कि किसी न किसी दिन ये अपमानजनक कार्रवाइयां उजागर होकर रहेंगी, इसलिए वह नुकसानों के नियंत्रण के लिए तैयार हो चुका था। उसने बिना किसी टाल-मटोल के अत्याचारों को कबूल किया। उसके बाद मेजर जनरल आन्टोनियो तगुबा द्वारा पेश गोपनीय रिपोर्ट अखबारों को लीक हुई। इसीलिए रम्सफेल्ड ने कबूल किया कि इससे भी घिनौनी तस्वीरें मौजूद

एक कैदी पर कुत्ते को उकसाता अमेरिकी सैनिक

नंगा खड़ा करके हिंसाचार का दृश्य

हैं। बुश, रम्सफेल्ड और ब्लेइर ने इसमें अपनी भूमिका से इनकार करते हुए सारा दोष निचले स्तर के अधिकारियों और सैनिकों के सिर मढ़कर "गहरी" क्षमा याचना की। रम्सफेल्ड ने इसे "गैर-अमेरिकी और मति-भ्रमित" कार्रवाई की संज्ञा दी।

इस "मति-भ्रमित" सिद्धान्त को नकारने वाले कई और तथ्य भी रोशनी में आए। रक्षा विभाग के अधिकारियों ने स्वीकार किया कि अमेरिकी हिरासत में 37 इराकी और अफगान कैदियों की मौत हुई है। ये सब दिसम्बर 2002 के बाद ही हुईं। इस प्रकार के 35 मामलों की जांच करने पर पता चला कि इनमें से 10 मामले ऐसे थे जो बलात्कार, हमला, घायल करने, आदि से जुड़े हुए थे। ग्वान्टेनामो की खाड़ी की कैदियों के सम्बन्ध में तो किसी को कोई जानकारी नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में कैदियों के सम्बन्ध में सारी जानकारी गुप्त रखी गई है। कैदियों के हालात के बारे में जानना तो और भी मुश्किल है। उन्हें अपनी सुरक्षा करने की कोई कानूनी प्रक्रिया उपलब्ध नहीं है। जेनीवा समझौता भी उन पर लागू नहीं होता!

इराकी कैदियों पर किए गए यौन दुराचार, जैसा कि मेजर जनरल ए. मार्क्स ने बताया, "बुरे काम करने वाले चंद बदमाश सैनिकों" द्वारा ईजाद नहीं किए गए। सेना के प्रश्नकर्ताओं को प्रशिक्षण देने वाले इस अधिकारी ने कहा कि वे ऐसे तरीके कतई नहीं सिखा रहे हैं। लेकिन सचाई इसके ठीक उलटी है और वह यह है कि यौन सम्बन्धी अपमान विशेष बलों द्वारा प्रयुक्त तरीकों का हिस्सा है। अब ये तरीके सामान्य बलों और निजी प्रश्नकर्ताओं के लिए भी लागू करवा रहे हैं। इस तकनीक को आर2आई (रेसिस्टेन्ट टु इंटरागेशन) के नाम से बुलाया जा रहा है। इराक से वापिस आए एक भूतपूर्व ब्रितानी विशेष बल अधिकारी ने कहा कि यह तरीका अमेरिका और समूचे यूरोप में सिखाया जा रहा है ताकि "पकड़े जाने के बाद लगने वाले झटके की स्थिति को लगातार जारी रखा जा सके।" "सभ्यता" के सर्वोच्च मूल्य इस प्रकार नंगे हो रहे हैं!!

यह उजागर होने के बाद कुछ कैदियों को रिहा कर दिया गया, इसलिए अब ज्यादा सबूत मिल रहे हैं जो तस्वीरों से भी बढ़कर हैं।

कैदियों की गवाही

मेजर जनरल तगुबा द्वारा जुटाई गई गवाहियां रक्षा विभाग द्वारा की गई अंदरूनी जांच का हिस्सा थीं। इन गवाहियों को जनवरी 2004 में जुटाया गया। हालांकि इस जांच रिपोर्ट को गुप्त रखा गया था, लेकिन बाद में वह लीक हो गई।

इसमें जिन यातनाओं का जिक्र किया गया वे बाहर आने वाली तस्वीरों के दृश्यों से भी बदतर थीं। कैदियों ने अपने बयानों में कहा – अमेरिकी अधिकारी उन पर बैठकर जानवरों की तरह सवारी करते थे; महिला सैनिक कैदियों को यौन सम्बन्धी अपमानों का शिकार बनाती थीं; पखाने में खाना फेंककर उसे उठाकर खाने को मजबूर करते थे; जननेंद्रियों को बिजली के झटके देते थे; सुअर का मांस और शराब का सेवन करने पर मजबूर करके इस्लाम को छोड़ने को जबरन कबूलवाते थे; बेदम पिटाई करते थे; इत्यादि कई घनघोर हिंसात्मक व घृणास्पद तरीकों के बारे में बताया। एक बाप को उसके बेटे के साथ नंगा बनाकर मुरगियों की भांति एक बक्से के अन्दर रख दिया गया। कई कैदियों को नंगा बनाकर उन्हें एक के ऊपर एक को गिराकर उन्हें समलिंग संपर्क करने पर मजबूर किया। उनके जननांगों पर रायफलों की कुंदों से मारा जाता था। उनके शरीर पर अमेरिकी अधिकारी पेशाब करते थे। कई अन्य बर्बरतापूर्ण यातनाओं के बारे में भी कैदियों ने बताया जिनकी आम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। 372वीं मिलटरी पुलिस कम्पनी का सदस्य चार्लेस गारनेर और एक महिला अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल जेनिस कार्पिनस्की दोनों अबू ग़रेब जेल में क्रूरता का पर्याय बन गए। विद्रोह को कुचलने के लिए बनाए गए इस प्रकार के जेल इराक में कुल 16 हैं। इन अत्याचारों के बारे में खबरें बाहर आने के बाद 240 कैदियों को रिहा कर दिया गया। अभी 7,000 कैदी जेलों में हैं। इसके अलावा कई अन्य अनधीकृत सेल (कोठरियां) भी हैं। अमेरिकियों के बेसों के बगल में रहने वाली इन कोठरियों में किसी को भी प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी जाती। *(शेष पृष्ठ 29 पर....)*

अमेरिकी सेनाओं के अत्याचारों के खिलाफ इराकियों का प्रदर्शन

विलियम हिन्टन (1919-2004)

एक क्रान्ति के साक्षी रहे जन लेखक

15 मई 2004 की सुबह अमेरिका के शिकागो शहर में विलियम हिन्टन का देहान्त हो गया। विलयम हिन्टन का नाम सुनते ही हमें चीन के शान्सी राज्य स्थित लांगबो गांव याद आता है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में उस गांव में सम्पन्न क्रान्तिकारी भूमि सुधारों का विस्तृत वर्णन करते हुए उनके द्वारा लिखित किताब '*फानशेन*' याद आती है। एडगार स्नो, एग्नेस स्मेड्ली और नार्मन बेतून के साथ अब विलियम हिन्टन का नाम भी जुड़ गया जिन्हें दुनिया की जनता हमेशा याद रखती है। इन अमेरिकियों ने न सिर्फ चीनी क्रान्ति, जिसने दुनिया की एक-चौथाई आबादी की जिन्दगी बदल डाली थी, के महत्व को काफी पहले ही पहचान लिया था बल्कि काफी मुश्किलों का सामना करके उस क्रान्ति में तहेदिल से भाग लिया था। जब वह क्रान्ति प्रगति पर थी उसके पूरे परिणामक्रम को इन्होंने शानदार ढंग से लिपिबद्ध किया।

1919 में जन्मे हिन्टन अपने सत्रह साल की उम्र में ही रोटी कमाने की खातिर सुदूर पूर्वी देशों की ओर पलायन किया था। जब वह बरतन साफ करते हुए जीविका चला रहे थे तब उन्हें जापान के एक अंग्रेजी अखबार में रिपोर्टर के रूप में छह माह तक नौकरी मिल गई। बाद में वह जापान से दक्षिण कोरिया होते हुए चीन को और बाद में वहां से सोवियत संघ, पोलैण्ड, जर्मनी होते हुए फिर से अमेरिका लौट गए। वहां उन्होंने एक मालवाहक जहाज में नाविक के रूप में काम किया।

1942 में उन्होंने एडगार स्नो की किताब "रेड स्टार ओव्हर चाइना" पढ़ी थी। उस किताब ने उनकी जिन्दगी ही बदल डाली। खुद उन्हीं के शब्दों में उसने उनके विश्व दृष्टिकोण को शांतिवाद से मार्क्सवाद की ओर पलट दिया। ऐसे दिनों में जबकि दुनिया में अत्यधिक लोग चीन को चांग काई-शेक की कुमिंताङ के साथ ही जानते थे, एडगार स्नो के जबर्दस्त प्रयासों की बदौलत ही दुनिया को लाल चीन के बारे में जानकारी मिल गई। स्नो ने एनान जाकर यह पहचान लिया था कि चीन का भविष्य पूरा कम्युनिस्टों के नियमबद्ध और जुझारू संघर्ष में ही छिपा हुआ है। वहां पर उन्होंने जिन-जिन उत्साहपूर्ण विषयों को देखा उन तमाम को अपनी रचनाओं के जरिए दुनिया के सामने पेश किया था। 1945 में विलियम हिन्टन युद्ध सूचना कार्यालय के कर्मचारी के तौर पर चीन पहुंचे थे। वह माओ और चौ एन-लाइ से कई बार मिले थे। 1947 में वह संयुक्त राष्ट्र संघ सहायता व पुनरावास परिषद के सदस्य के रूप में फिर चीन गए थे। काम पूरा होने के बाद भी वह वहीं रुक गए।

शांग्सी के निकट उत्तरी विश्वविद्यालय में कुछ समय तक पढ़ाने के बाद 1948 में हिन्टन भूमि सुधारों की टोली में शामिल होकर लांगबो गांव गए थे। वहां वह 8 महीने रहे थे। वहां पर लागू किए गए भूमि सुधारों के बारे में उन्होंने जो एक हजार पन्नों से ज्यादा विवरणात्मक नोट्स लिखे थे। हरेक विषय की गहराई से जांच करते हुए लिखे गए उन नोट्स को अमेरिकी सीमा शुल्क विभाग ने जब्त करके आंतरिक सुरक्षा पर सेनेट कमेटी को (इसी को बदनाम "ईस्टलैण्ड कमेटी" कहा जाता है) सौम्प दिया। अमेरिकी खुफिया विभाग एफबीआई ने उन्हें तीव्र प्रताड़नाएं दीं। उनके पासपोर्ट को जब्त किया। पढ़ाने या किसी भी काम में उन्हें नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध लगाया। ट्रक मेकैनिक के तौर पर उन्होंने काम करना चाहा तो वह काम भी करने नहीं दिया गया। इससे उन्होंने अपनी मां से विरासत में मिली जमीन पर खेतीबाड़ी शुरू की। लगभग 15 सालों तक वह किसान के रूप में खेतीबाड़ी करते हुए ही दूसरी ओर सांस्कृतिक क्रान्ति की उपलब्धियों पर व्याख्यान देते रहे। उसी दौरान उन्होंने ईस्टलैण्ड कमेटी के खिलाफ लम्बी कानूनी लड़ाई लड़कर अपने नोट्स को वापिस पा लिया।

नोट्स दोबारा हाथ में आने के बाद उन्होंने लांगबो गांव में लागू किए गए भूमि सुधारों पर, जिसमें उन्होंने भागीदार व प्रेक्षक के रूप में भाग लिया था, एक समग्र किताब लिखना शुरू किया। इस प्रकार 1966 में *फानशेन* किताब बन गई। कई बड़े-बड़े प्रकाशकों द्वारा इस किताब को छापने से इनकार किए जाने के बाद मंथ्ली रिव्यू प्रेस ने इसे प्रकाशित किया था। इस किताब को जबर्दस्त कामयाबी मिल गई। लाखों प्रतियां बिक गईं। लगभग दस भाषाओं में उसका अनुवाद किया गया। डेविड हेर नामक एक नाटककार ने *फानशेन* को नाटक का स्वरूप देकर लन्दन में पहली बार इसका मंचन किया। बाद में उस नाटक को दुनिया के कई हिस्सों में प्रदर्शित किया गया। चौ एन-लाई की पहल पर उसे चीनी भाषा में भी अनूदित किया गया। 1971 में चौ एन-लाई ने हिन्टन को दोबारा चीन आने का न्यौता भेजा।

फानशेन में न सिर्फ भूमि सुधारों के पीछे चलने वाले वर्ग संघर्ष का

(शेष पृष्ठ 34 पर ....)

जनयुद्ध के दौरान शहीद हुए

कॉमरेड्स रानू और प्रेमलाल को क्रान्तिकारी सलाम !

मुक्तांचल के निर्माण के लक्ष्य से आगे बढ़ रहे दण्डकारण्य के क्रान्तिकारी आन्दोलन ने हाल ही में दो युवा और बहादुर योद्धा खो दिए। जुलाई के आखिरी सप्ताह में कॉमरेड रानू की मृत्यु दुर्घटनावश बन्दूक फायर होने से हुई। और 27 सितम्बर को कॉमरेड प्रेमलाल जब पुलिस से एक बन्दूक छीनकर आ रहे थे तब पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी में शहीद हो गए। इन दोनों जांबाज नौजवान कॉमरेडों को 'दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी' पूरी नम्रता के साथ श्रद्धांजलि पेश करती है। इन दोनों की जीवनियों का सक्षिप्त परिचय नीचे पेश है।

कॉमरेड रानू – फौलादी इरादों की मिसाल

कॉमरेड रानू का जन्म दन्तेवाड़ा जिला, बीजापुर तहसील के गुंडेमाड़ गांव में हुआ था। घर पर उनका नाम था गुड्डू एमला। गरीब परिवार में जन्मे कॉमरेड गुड्डू बचपन से ही खेतीबाड़ी का काम करते रहे। इंद्रावती नदी के किनारे स्थित उनके गांव में 1999 में क्रान्तिकारी आन्दोलन की गतिविधियां शुरू हुईं। ज्यों ही इस क्षेत्र में इंद्रावती दस्ते की गतिविधियां शुरू हुईं, कॉमरेड गुड्डू गांव के संगठन में सदस्य बन गए। इस इलाके में जमींदारों और वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ चलाए गए जन संघर्षों में कॉमरेड गुड्डू ने सक्रिय भाग लिया। सूखे के दिनों में पार्टी ने जमींदारों के घरों पर हमले करके अनाज जब्त करने का आह्वान किया तो कॉमरेड गुड्डू ने उन हमलों को अंजाम देने में जनता का नेतृत्व किया। इसी दौरान उन्होंने फैसला कर लिया कि वह भी पार्टी में पूर्णकालीन कार्यकर्ता के रूप में शामिल होकर देश की मुक्ति के लिए संघर्ष करेगा। जब उन्होंने अपने इस निर्णय से स्थानीय पार्टी जिम्मेवारों को अवगत कराया तो पार्टी ने उनका यह प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार किया। तब तक कॉमरेड गुड्डू विवाहित थे। 2001 में वह अपनी बीवी और दो नन्हे बच्चों को छोड़कर अपनी पूरी जिन्दगी को क्रान्ति के लिए समर्पित करते हुए दस्ते में शामिल हो गए। जनता के बीच उन्होंने रानू के नाम से काम करना शुरू किया। पहले से ही मेहनती और धैर्य के साथ काम करने वाले रानू को छापामार जिन्दगी में उत्पन्न कठिनाइयों से उबरने में ज्यादा समय न लगा। उनके स्वभाव और पार्टी व जनता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को देखते हुए स्थानीय एरिया पार्टी कमेटी ने उनका चुनाव तकनीकी कामकाज करने वाली टीम के सदस्य के रूप में किया। उस टीम में शामिल होने के बाद उन्होंने खुद को सचमुच "मजदूर" बनाते हुए सर्वहारा अनुशासन को आत्मसात कर लिया। उनके दस्ते में भर्ती होने के कुछ ही दिनों बाद उन्हें यह बुरी खबर मिली थी कि घर में बीमारी के कारण उनका प्यारा नन्हा बच्चा चल बसा। इसके बावजूद उन्होंने अपने दर्द को अपने सीने में ही छुपा लिया।

कॉमरेड रानू

जब वह तकनीकी जिम्मेदारियों में थे तभी वहां की कमेटी ने उन्हें पार्टी सदस्यता दी। अनपढ़ता और अपने काम के औजारों से कोई परिचय न होने के बावजूद उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ कई काम सीख लिए। क्रान्ति के लिए उन्होंने न सिर्फ बन्दूक चलाना सीखा, बल्कि हथौड़ा, पेंचकश, वेर्नियर कालिपर्स इत्यादि कई औजारों से काम करना भी सीख लिया। बन्दूकों की मरम्मत करते हुए उन्होंने छापामारों का साथ दिया। पार्टी ने जब-जब दुश्मन के बलों के खिलाफ कार्यनीतिक प्रत्याक्रमण अभियान का आह्वान किया तब-तब वह अपने औजारों को छोड़कर बन्दूक उठाकर जंगे मैदान में कूद पड़े थे। कॉमरेड रानू अपने साथियों और जनता में लोकप्रिय बने थे। मेहनती स्वभाव, विनम्रता, दृढ़ संकल्प, बहादुरी, इत्यादि उनकी विशिष्टताएं थीं। क्रान्ति में पूर्णकालीन कार्यकर्ता के रूप में भर्ती होने के बाद बीवी-बच्चों को देखने के मौके काफी कम मिलने के बावजूद उन्होंने क्रान्ति की खातिर बेल्शेविक संकल्प के साथ काम किया। जुलाई के आखिरी सप्ताह में शहीद सप्ताह के दौरान ही जब वह टट्टी जाकर आ रहे थे तब उनके पैर के नीचे एक पत्थर फिसलने से वह गिर पड़े। तभी उनकी लोड़ की हुई बन्दूक का घोड़ा दब जाने से गोली चली और उनके सीने से निकल गई। कॉमरेड रानू की मौके पर ही मौत हो गई। जैसा कि फिलिप्पीन्स की कम्युनिस्ट पार्टी नेता कॉमरेड जोस मारिया सिसॉन ने कहा, "मरने का ढंग नहीं, बल्कि युद्धों से हासिल निचोड़ एक इंसान को योद्धा बना देता है। बीमारी से मरने वाला योद्धा है। अवांछित हादसे में शहीद होने वाला योद्धा है। दुश्मन की गिरफ्त में यातनाएं झेलकर मरने वाला योद्धा है। सवाल यह नहीं कि कैसे मरा, बल्कि किसके लिए मरा – यही शहादत का फैसला करता है।' साथी कॉमरेडों और स्थानीय जनता ने मिलकर क्रान्तिकारी परम्पराओं के साथ कॉमरेड रानू की अन्त्येष्टि की। उमड़ते आंसुओं को पोंछकर उनके अधूरे लक्ष्य को पूरा करने का संकल्प लिया। ✶

कॉमरेड प्रेम – अदम्य साहस का दूसरा नाम

27 सितम्बर को जगदलपुर-रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित फरसगांव के हाट बाजार में गश्त पर आए पुलिस वालों पर पीजीए की एक ऐक्शन टीम ने हमला बोलकर एक पुलिस वाले को घायल कर उसकी रायफल छीन ली। इस टीम की अगुवाई कर रहे कॉमरेड प्रेमलाल मड़ावी जब पुलिस की एसएलआर उठाकर दौड़कर आ रहे थे तब दुश्मन ने पीछे से गोली मार दी। कॉमरेड प्रेम वहीं गिर पड़े। प्रेमलाल मड़ावी कांकेर जिले की केसकाल तहसील के ग्राम मंडानार का निवासी थे। वह शादीशुदा थे और उनके दो बच्चे भी थे। मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे कॉमरेड प्रेम काफी सालों से क्रान्तिकारी आन्दोलन में अंशकालिक कार्यकर्ता के तौर पर काम करते आ रहे थे। उनका पूरा परिवार ही क्रान्ति का समर्थक था। उनके एक छोटे भाई पार्टी में पूर्णकालीन कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं।

गांव में संगठन के सक्रिय सदस्य रहे प्रेम पार्टी के बताए हर काम को बेझिझक पूरा किया करते थे। उस इलाके में जनता के हर संघर्ष में उनकी भूमिका हुआ करती थी। आसपास के गांवों के लोगों में वह काफी लोकप्रिय थे। पार्टी और जन संगठनों द्वारा आयोजित सभाओं में वह वक्ता रूप में भाषण देते थे। वह खुद एक अच्छे कलाकार भी थे। पीजीए के गठन के बाद दण्डकारण्य में तेज हुई जन मिलिशिया की कार्रवाइयों के पीछे प्रेम जैसे कार्यकर्ताओं का ही योगदान महत्वपूर्ण रहा। 2003 में आमाबेड़ा हाट-बाजार में पुलिस पर हमला करके एक पुलिस वाले का सफाया करके उससे एसएलआर छीनने की कार्रवाई में भी कॉमरेड प्रेम की शानदार भूमिका रही। 27 सितम्बर को भी उन्होंने एक पुलिस वाले को गंभीर रूप से घायल कर उसकी एसएलआर छीनने में कॉमरेड प्रेम ने बढ़िया पहलकदमी की। शेर के बछड़े के पकड़ने के लिए शेर की मांद में घुसना होगा। दुश्मन से रायफल छीनना है उस पर झपट्टा मारना होगा जिसके लिए बहादुरी व पहलकदमी बेहद जरूरी हैं। कॉमरेड प्रेम में ये दोनों गुणों का अद्भुत समावेश था। उन्होंने दण्डकारण्य की समूची युवा पीढ़ी और जन छापामारों के सामने एक मिसाल कायम की। आज सीपीआई (एम-एल) [पीपुल्सवार] और एमसीसीआई के विलय के बाद पुनर्गठित एकीकृत पीएलजीए (जन मुक्ति छापामार सेना) कॉमरेड प्रेम की कुरबानी को सदा याद रखेगी। कॉमरेड प्रेम के बहाए खून का जरूर बदला लेगी। ✶

(.... पृष्ठ 32 का शेष)

वर्णन था, बल्कि उसमें भाग लेने वाले लोगों के बारे में और उनकी खूबियों और खामियों के बारे में बेहतरीन तरीके से चित्रित किया गया। दरअसल यही उस किताब की खासियत थी। वह किताब यह स्पष्ट करती है कि भूमि सुधार का कार्यक्रम ऊपर से सिर्फ निर्देशित किया गया था, न कि लागू किया गया था। किताब बताती है कि संघर्ष के दौरान किसानों ने खुद ही जीवन्त बुद्धिजीवी-कार्यकर्ताओं को तैयार कर लिया था और बाद में उन्हीं लोगों ने काडरों के रूप में उस आन्दोलन का नेतृत्व किया था। हिन्टन में उस किताब में बेहतरीन तरीके से दर्शाया कि वह संघर्ष कैसे नाटकीय प्रक्रियाओं से गुजरते हुए कम हिंसा के साथ आगे बढ़कर सामन्ती और दुष्ट मुखियाओं के प्रभुत्व को पूरी तरह तहस-नहस किया जो कई पीढ़ियों से कायम था।

फानशेन के बाद हिन्टन ने *आइरन ऑक्सेन, शेनफान,* आदि किताबें लिखीं। ये सभी किताबें चीनी क्रान्ति की कामयाबियों का बखान करने वाली ही हैं। उन्होंने कई बार चीन का दौरा करके कृषि प्रशिक्षण के काम में भाग लिया। उन्होंने लांगबो गांव का कई बार दौरा करके अपने खुद के पैसे खर्च कर खेती में नई तकनीक पेश की। वह लांगबो को अपना दूसरा गृहनगर बताया करते थे। यही कारण है कि लांगबो के निवासियों ने 2002 में अपने गांव के मेयर को बुजुर्ग व बीमार हिन्टन को देखने के लिए अमेरिका के बोस्टन शहर भेजा जहां वह 80 साल की उम्र में एक अस्पताल में दिल का इलाज करवा रहे थे। उन्होंने हिन्टन के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए लांगबो में प्रकाशित "विलियम हिन्टन : चीनी जनता का पुराना दोस्त" नामक एक खूबसूरत किताब की एक प्रति लाकर दी।

डेंग सियावो पिंग के नेतृत्व में लाए गए पूंजीवादी सामाजिक सम्बन्धों के प्रति हिन्टन ने अपनी असहमति व्यक्त की। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा अपनाई गई पूंजीवादी लाइन को उन्होंने सिरे से नकार दिया। इस लाइन की आलोचना करते हुए उन्होंने अपनी जिन्दगी के आखिरी दिनों में "चीन : एक असम्पूर्ण संघर्ष" नामक किताब लिखी। इस किताब को भारत में प्रकाशित किया गया। चीन में सत्तारूढ़ संशोधनवादियों और अमेरिकी साम्राज्यवादियों के सांस्कृतिक क्रान्ति को एकतरफा और कठमुल्लावादी ढंग से खारिज करने के रुझान को उन्होंने बार-बार नकार दिया। किसानों और आम जनता में मौजूद क्रान्तिकारी परिवर्तनशील शक्ति के प्रति उनका विश्वास अटल है। यह उन्होंने खुद के अनुभव से प्राप्त समझदारी के आधार पर बना लिया।

1996 में वह भारत आए थे। यहां के क्रान्तिकारी संगठनों के लोगों से उन्होंने कई विषयों पर बात की। भारत में क्रान्ति के भविष्य पर उन्होंने बेहद उम्मीद जताई। सीधे, स्पष्ट और स्नेहपूर्ण बरताव करने वाले किसान और क्रान्तिकारी विलियम हिन्टन ने अन्तर्राष्ट्रीय सर्वहारावाद के एक अच्छे उदाहरण के रूप में जिया। उनकी जिन्दगी मार्क्सवादी क्रान्तिकारी व्यवहार का नमूना थी। सीखने और सिखाने में उन्हें न तो सांस्कृतिक अन्तर न ही पीढ़ीगत अन्तर से कोई दिक्कत हुई। जन लेखक व मार्क्सवादी बुद्धिजीवी विलियम हिन्टन को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उनकी तरह जिएंगे। ✶

पीएलजीए (जन मुक्ति छापामार सेना)

की चौथीं वार्षिकी के मौके पर ...

2 से 8 दिसम्बर तक स्थापना सप्ताह मनाएं !

फासीवादी दमनात्मक नीतियों पर चलती छत्तीसगढ़ सरकार

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों के पहले से ही भाजपा नक्सलवादियों के कठोरतापूर्ण दमन पर जोर देती रही। अब सत्ता में आने के बाद उसने दमनात्मक नीतियों में रोज-रोज तेजी ला रही है। मुख्य रूप से लोकसभा चुनावों के दौरान उसने बस्तर की जनता पर जो दमनचक्र चलाया वह काफी भयानक था। न सिर्फ क्रान्तिकारी आन्दोलन पर, बल्कि आम जनता पर भी भाजपा सरकार की पुलिस आए दिन हिंसा व अत्याचार कर रही है। हिरासती हत्याएं आम हो चुकी हैं। गौरतलब बात यह है कि चाहे किसी भी इलाके में भाजपा की पुलिस आदिवासियों, दलितों और अन्य पिछड़े तबकों के लोगों पर ही हिंसा और अत्याचार ढा रही है।

पहले जब कांग्रेस सत्ता में थी तभी भाजपा ने पोटा कानून लागू करने की मांग की थी। अब वह सत्तारूढ़ होने के बाद नए कानून की रूप-रेखा तैयार करने में जुट गई। केन्द्र में कांग्रेस की अगुवाई में बनी संप्रग सरकार के पोटा को वापिस लेने की घोषणा करने के बाद रमन सिंह सरकार ने "छत्तीसगढ़ विशेष सुरक्षा अधिनियम 2004" की तैयारियां शुरू कर दीं। जल्द ही वह इसे कानून का शक्ल देने वाली है। इस काले कानून के जरिए वह पुलिस बलों को उन्मुक्त अधिकार देकर क्रान्तिकारी आन्दोलन के प्रति हमदर्दी रखने वाली आम जनता पर क्रूरतापूर्ण दमन ढाएगी।

भाजपा के सत्ता में आने के बाद से अब तक अविभाजित बस्तर में पुलिस व सीआरपी बलों ने तीन सामान्य किसानों की हत्या की। विधानसभा चुनाव के थोड़े दिन पहले हुई हत्याओं को भी मिलाया जाए तो हाल के महीनों में कुल पांच सामान्य किसान पुलिसिया हत्याकाण्ड का शिकार हो गए। 16 नवम्बर 2003 को पुलिस बलों ने कांकेर जिले (उत्तर बस्तर) के जीरमतराई गांव में बुधराम और सुखराम नामक दो किसानों को तब गोली मार दी जब वे अपने खेतों में काम कर रहे थे। बाद में इन्हें नक्सली घोषित किया गया। 2 अप्रैल 2004 को दन्तेवाड़ा जिले (माड़ डिवीजन) के भैरमगढ़ तहसील के धरमा गांव में बुधरी नामक महिला और एक किसान चैतू की हत्या की। बुधरी के साथ पहले सामूहिक बलात्कार करके बाद में गोली मार दी। पुलिस ने उसे मुठभेड़ बताकर एक महिला नक्सली की मौत होने की घोषणा की। बुधरी की अंत्येष्टि के बाद नदी में नहाने गए चैतू को पुलिस ने पीट-पीटकर मार डाला। 20 अप्रैल को दंतेवाड़ा जिले (दक्षिण बस्तर) के कोत्ताचेरुवु गांव के निवासी हडमा मरकाम नामक 50 साल के किसान को पुलिस ने तब गोली मार दी जब वह महुए बीन रहा था। बाद में मुठभेड़ की कहानी गढ़ दी गई। जहां आन्दोलन वाले इलाकों में आम लोगों की झूठी मुठभेड़ों में हत्या की जा रही है, वहीं बाहरी इलाकों में आम लोगों की पुलिस हिरासत में हत्या की जा रही है और उसे आत्महत्या की संज्ञा दी जा रही है।

क्रान्तिकारी आन्दोलन का दमन करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस व अर्ध सैनिक बलों को तैनात करने के साथ-साथ उन्हें अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कांकेर जिलों समेत बीजापुर, नारायणपुर पुलिस जिलों को बड़ी संख्या में वाहन दिए जा रहे हैं। पुलिस थानों की किलेबन्दी करने के काम को अहमियत देते हुए उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है। क्रान्तिकारी आन्दोलन के खिलाफ मुकम्मल तौर पर युद्ध के लिए तमाम जरूरी तैयारियां सरकार कर रही है। राज्य सरकार ने केन्द्र से नक्सली समस्या के समाधान के लिए सहायता के रूप में 186 करोड़ रुपए देने की मांग की है। खुफिया एडीजी ओपी राठौर ने बताया कि इसमें से पुलिस बलों के लिए आधुनिक हथियार, बुलेटप्रूफ जैकेट, बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाले वाहन आदि की खरीदी के लिए खर्चा जाएगा। सरकार ने नक्सल प्रभावित इलाके में एक विशेष बटालियन की स्थापना के लिए बजट में 8 करोड़ रुपए का आवंटन किया। पिछले साल बस्तर में पुलिस को 10 भारी, 25 मध्यम दर्जे के वाहनों के अलावा 331 मोटार सायकिल उपलब्ध करवाए गए। अपने जगदलपुर दौरे के दौरान छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने कहा कि बस्तर को सीआरपीएफ के तीन बटालियन स्थाई रूप से दिए गए। एक ओर फौजी तैयारियां करते हुए ही सरकार बड़े पैमाने पर सड़कें बनाने की योजनाएं लागू कर रही है। लेकिन सड़कों का निर्माण आन्दोलन के दमन के नाम से नहीं बल्कि जनता के विकास के नाम से किया जा रहा है। सरकार बड़े पैमाने पर यह दुष्प्रचार कर रही है कि नक्सलवादी विकास के विरोधी हैं और वह खुद जनता का विकास चाहती है। कहा जा रहा है कि अबूझमाड़ इलाके में आक्रामक अन्दाज में विकास कार्यक्रम लागू किए जाएंगे और करोड़ों रुपए खर्चे जाएंगे।

सरकार यह भी कह रही है कि बस्तर में मिजोरम की तर्ज पर आर्मी ट्रेइनिंग स्कूल की स्थापना की जाएगी। कथित रूप से बीजापुर या नारायणपुर में बनाए जाने वाली इस स्कूल में पुलिस बलों को जंगल वारफेर में उच्च कोटि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले से ही आन्ध्र के ग्रे-हाउण्ड्स द्वारा प्रशिक्षित विशेष टास्कफोर्स के दस्ते आन्दोलन के दमन में लगाए जा रहे हैं। आन्ध्र की कुख्यात एसआईबी (विशेष जांच शाखा) की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में रमन सिंह सरकार ने भी एक खुफिया संस्था बनाई। सेना के अधिकारी भी बस्तर के दौरे करते हुए आन्दोलन के दमन की रणनीति तैयार करने में अपनी सलाहें दे रहे हैं।

रमन सिंह सरकार एक ओर ये तमाम तैयारियां करते हुए ही दूसरी ओर कभी-कभार यह कह रही है कि वह नक्सलवादियों के साथ शांतिवार्ता करने के लिए तैयार है। बिना किसी ठोस प्रस्ताव के ही और पार्टी द्वारा पहले ही सुझाए गए प्रस्तावों का कोई ठोस जवाब दिए बिना ही शांतिवार्ता की रट लगाना इस बात का सबूत है कि रमन सिंह सरकार में इस सवाल पर ईमानदारी का अभाव है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार आन्दोलन का दमन करने का ही इरादा रखता है, इसके सामाजिक व आर्थिक जड़ों तक जाने का उसका कोई इरादा नहीं है। लेकिन इतिहास में कई बार साबित हो चुका है कि दमन प्रतिरोध को ही जन्म देता है। क्रान्तिकारी आन्दोलन के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किए जा रहे व्यापक दमनकारी हमले को जनता और जन मुक्ति छापामार सैनिक निश्चित रूप से एकजुटता के साथ लड़कर हरा देंगे और जनयुद्ध को आगे बढ़ाएंगे। ✶

सीआरपी बलों के अत्याचारों के खिलाफ
माड़ जनता की जबर्दस्त रैली

मार्च 2003 से बस्तर में तैनात सीआरपी बलों के अत्याचार दिन-ब-दिन हद से बढ़ते जा रहे हैं। उत्तर बस्तर, माड़, दक्षिण बस्तर और पश्चिम बस्तर के गांवों में सीआरपी बलों द्वारा अमल हिंसा और जुल्म के कई खबरें सामने आ रही हैं। कई अन्य घटनाएं प्रकाश में आए बिना ही वहीं के वहीं दबा दी जा रही हैं। 17 जून को माड़ डिवीजन के डौला इलाके के मढोनार गांव में सीआरपी बलों द्वारा मचाए गए आतंक और उसके जवाब में जनता द्वारा किए गए संघर्ष का ब्यौरा इस प्रकार है –

17 जून को साआरपी और स्थानीय पुलिस के संयुक्त दल ने मढोनार गांव पर धावा बोल दिया। उन्होंने वहां दो संगठन सदस्यों को गिरफ्तार किया जिनके पास कुछ दवाएं थीं। आज के पुलिसिया राज में विस्फोटक पदार्थ रखना ही नहीं, बल्कि जान बचाने की दवाएं रखना भी गुनाह हो गया! पुलिस का तर्क है कि वे नक्सलवादियों की थीं। लेकिन गांव की जनता कह रही है कि वे उसकी अपनी हैं। सरकार चाहे माने या न माने पर यह एक कड़वी सचाई है कि तथाकथित आजादी को आए 57 साल गुजरने के बावजूद आज भी बस्तर की जनता छोटी-छोटी बीमारियों से बैमौत मर रही है। इसी पृष्ठभूमि में यहां पिछले 25 सालों से संगठित हुए क्रान्तिकारी आन्दोलन के प्रयासों की बदौलत कई गांवों में जनता खुद आगे आकर स्वास्थ्य केन्द्र बना ले रही है और अपने ही बल पर दवाएं खरीद कर खुद ही अपना इलाज करवा रही है। पार्टी और क्रान्तिकारी जन संगठन की यह कोशिश जारी है कि हर गांव से एक-दो नौजवानों को दवा-दारू देने का प्राथमिक प्रशिक्षण दिया जाए। पुलिस ने कथित तौर पर नक्सलियों के लिए ले जाई रही दवाएं जो पकड़ीं, वे वास्तव में गांव की जनता द्वारा अपने जन स्वास्थ्य केन्द्र के लिए जुटाई गई थीं। लेकिन पुलिसिया दिमाग को इन सब बातों से क्या लेना-देना! उन्होंने युवकों को पकड़ कर बेदम पीटना शुरू किया। पुलिस के लिए एक और दिक्कत यह थी कि उस गांव में शहीदों की याद में निर्मित 25 फुट का स्मारक मौजूद था। जिन लोगों का सफाया करने के लिए वह दिन-रात जंगलों में छान मारती है और हाथ-पांव मारती है उनके प्रतिरूप इस तरह गांवों में खुलेआम दिखाई देना, और तो और उन्हें जनता के दिलों में जगह मिलना पुलिस को रास नहीं आया। इसलिए पुलिस की एक टुकड़ी स्मारक को गिराने के लिए गई। लेकिन जनता यह सब देखकर चुप रहने को तैयार नहीं थी। लोगों ने यह समझकर कि मुकाबला किए बिना अपने लोगों को छुड़ा नहीं पाएंगे और स्मारक को नहीं बचा पाएंगे, सब इकट्ठे हो गए। बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष – सभी ने हाथ में डंडा, झाड़ू इत्यादि जो औजार-हथियार मिला उठा लिया। और वे पुलिस से भिड़ गए। यह संघर्ष 10 मिनट तक चलता रहा। इसमें 20 लोग, ज्यादातर महिलाएं घायल हो गईं। फिर भी लोगों ने इसकी परवाह किए बिना ही कि पुलिस के पास अत्याधुनिक आग्नेयास्त्र मौजूद हैं, उनसे आमने-सामने टक्कर ली। इस संघर्ष में तीन महिलाएं बुरी तरह घायल हो गईं। इस संघर्ष के जरिए उन्होंने स्मारक को गिराने की पुलिस की कोशिश को नाकाम कर दिया।

छोटाडोंगर पुलिस थाने का घेराव

मढ़ोनार में हुए जुल्म और संघर्ष की खबर कुछ ही घण्टों के अन्दर आसपास के करीब 35 गांवों फैल गई। अगले दिन, 18 जून को लगभग 2,500 स्त्री-पुरुष इकट्ठे हो गए और अपने हाथों में कुल्हाड़ी, हंसिया, तीर-धनुष इत्यादि हथियार उठाकर छोटाडोंगर की ओर कूच कर गए। उन्होंने थाने का चारों ओर से घेराव करके मांग की कि गिरफ्तार लोगों की रिहाई की जाए, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले पुलिस जवानों को दण्डित किया जाए और घायल महिलाओं का इलाज करवाया जाए। जनता के गुस्से के सामने सिर झुकाते हुए पुलिस गिरफ्तार लोगों को अदालत में पेश करने तथा घायल महिलाओं को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाने को राजी हो गई और महिलाओं पर किए गए जुल्मों के लिए माफी मांगी।

नारायणपुर रैली

इस घटना के बाद समूचे नारायणपुर क्षेत्र में सीआरपी बलों के अत्याचारों के प्रति विरोध की लहरें उठीं। सभी तबकों के लोगों और यहां तक कि बुर्जुवाई पार्टियों के सदस्यों ने भी इस घटना का विरोध किया। विभिन्न तबकों के लोगों ने, खासकर महिलाओं ने "बस्तर महिला संघर्ष समिति" के नाम से एक मंच का गठन किया। इस समिति के बैनर तले नारायणपुर में रैली निकालने का प्रस्ताव किया गया। 23 जून को सम्पन्न इस रैली में 15 हजार लोगों ने भाग लिया। इनमें महिलाओं की संख्या ही ज्यादा थी। आसपास के कुल 100 गांवों के लोगों ने इस रैली में भाग लिया। सुबह के 11 बजे नारायणपुर के नजदीक गड़बेंगाल गांव में रैली शुरू हुई जो नारायणपुर की गलियों से गुजरते हुए पीओ के कार्यालय पहुंची। "सीआरपी वालो, वापिस जाओ", "अत्याचारियों को सजा दो", आदि नारों से नारायणपुर की पूरी बस्ती ही गूंज उठी। इस रैली को विफल बनाने के लिए पुलिस ने जी-तोड़ कोशिश की। कुतुल

छत्तीसगढ़ में बस्तर के विलय के खिलाफ ...

अलग बस्तर राज्य के गठन की मांग के समर्थन में ...

1 नवम्बर को 'बस्तर बन्द' को सफल बनाएं !

और सोनपुर की सड़कों से आने वाली जनता को पुलिस ने डरा-धमकाकर पीछे लौटा दिया। इस मौके पर 'बस्तर महिला संघर्ष समिति' ने पीओ और राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा जिसमें पांच प्रमुख मांगें थीं –

1) महिलाओं पर जुल्म करने वाले सीआरपी जवान माफी मांग लें।
2) घायल महिलाओं का पूरा इलाज किया जाए।
3) बस्तर से सीआरपी बलों को वापिस भेजा जाए।
4) गिरफ्तार दो संगठन कार्यकर्ताओं को बिना शर्त रिहा किया जाए।
5) जनता द्वारा निर्मित स्मारकों को तोड़ना पुलिस बन्द करे।

सीआरपी और पुलिस बलों के अत्याचारों और हिंसाकाण्ड के खिलाफ हजारों की संख्या में जनता के सड़कों पर उतरने से शासक काफी चिन्तित हो गए। टीवी चैनलों और अखबारों के जरिए इन अत्याचारों के बारे में बाहरी दुनिया को काफी जानकारी मिल गई जिससे लोग समझने लगे हैं कि बस्तर में क्या हो रहा है। साथ ही, इस पूरे घटनाक्रम से जनता को अपनी संघर्ष शक्ति पर विश्वास दोगुना हो गया। ✶

उत्तर बस्तर में पीजीए का एम्बुश

कांकेर जिला एसपी समेत छह पुलिस वाले घायल

6 सितम्बर को सीआरपीएफ, स्पेशल टास्कफोर्स और सीएएफ के सैकड़ों बलों ने बड़े पैमाने पर खोजबीन अभियान शुरू कर दिया। उत्तर बस्तर में, मुख्य रूप से कोइलीबेड़ा इलाके में जारी क्रान्तिकारी आन्दोलन को कुचलने की मंशा से पुलिस ने अपनी तरह का यह बड़ा अभियान शुरू किया। लेकिन इस इलाके की जनता ने धमिकियों की परवाह न करते हुए पुलिस का सहयोग करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। भारी बरसात के दौरान इस इलाके में पहुंचने के लिए उफनती नदियों को नावों में ही पार करना होगा। लेकिन स्थानीय जनता ने इन्हें अपने नावों में पार करवाने से मना कर दिया। इससे पुलिस को खुद ही नाव चलाने पर मजबूर होना पड़ा। जब वह लापरवाही के साथ मेंढकी नदी पार कर रही थी तो अचानक नाव उलट गई थी। इस हादसे में एक पुलिस जवान नदी में डूबकर मरा था तो नाव में सवार बाकी पुलिस जवान तैरते हुए पार कर गए। लेकिन इस दौरान पुलिस ने कुल छह बन्दूकें नदी में खो दीं।

इस बीच नदी के उस पार पीजीए सैनिकों को यह पता चला था कि बड़े दमन अभियान चलाने की मंशा से पखांजूर से निकले पुलिस बल नदी पार कर रहे हैं। इसके तुरन्त बाद वे नदी के किनारे पहुंच गए। तब पुलिस वाले इस पार डेरा डालकर अपने मरे साथी की लाश और नदी में गिरी बन्दूकें खोजने में जुटे हुए थे। पुलिस को देखने के बाद छापामारों ने कुछ गोलियां चला दीं ताकि उन्हें हैरान किया जा सके। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। बाद में छापामार वापिस चले गए।

अगले दिन पुलिस ने तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर रेडियो और अखबारों के जरिए यह प्रचार किया कि पुलिस और नक्सलवादियों के बीच हुई गोलीबारी में पांच नक्सली मारे गए और एक पुलिस जवान को गोली लगने से नदी में गिरकर मारे गए। इस बयान का खण्डन करते हुए पार्टी की उत्तर बस्तर डिवीजनल कमेटी सचिव कॉमरेड सुजाता ने एक प्रेस वक्तव्य जारी किया। उस वक्तव्य ने उन्होंने खुलासा किया कि दरअसल ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं थी जिसमें पांच नक्सलवादी मारे गए हों और यह भी कि पुलिस जवान के नदी में बहकर मारे जाने के लिए वे जिम्मेदार नहीं हैं बल्कि खुद पुलिस ही जिम्मेदार हैं। उनकी लापरवाही की वजह से ही उनकी नाव उलट गई थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके छापामारों ने पुलिस की नाव पर गोलीबारी जैसा कुछ नहीं किया। उन्होंने पुलिस बलों की यह कहकर आलोचना की कि पीजीए बलों के हाथों मिली पराजय पर परदा डालने के लिए ही वे ऐसा दुष्प्रचार कर रहे हैं।

दूसरी तरफ, जनता से पूरी जानकारी हासिल करने के बाद, अगर पुलिस वाले दोबारा आएं तो उनका मुकाबला कर सकें, इसके लिए पीजीए सैनिक तैयार हो गए। 6 सितम्बर को जब पुलिस दल अपनी खोई हुई बन्दूकें तलाशने की मंशा से आ रही थी तो डोंगरी गांव के पास पीजीए ने उन पर घात लगाकर हमला कर दिया। इस हमले में कांकेर जिला एसपी पीएस ठाकूर, सीआरपीएफ सहायक कमाण्डेंट समेत चार अन्य पुलिस वाले घायल हो गए। इनमें दो की हालत गंभीर थी।

इस हमले के बाद सरकार ने लांगकुमेर को जिले का अस्थाई एसपी नियुक्त किया। इसके नेतृत्व में पुलिस वालों ने परतापुर गांव में डेरा लगाकर नदी में बन्दूकें तलाशने की कोशिश की। पर जन मिलिशिया ने कई बार उनके कैम्प पर हमला करके उन्हें हैरान-परेशान कर दिया। नदी पार करने के लिए पुलिस जो नाव इस्तेमाल कर रही थी उसे भी मिलिशिया ने गायब कर दिया। इससे पुलिस का मनोबल बुरी तरह टूट गया। और उनके सारे प्रयास विफल हो गए।

एक तरफ पुलिस को हैरान-परेशान करते हुए ही दूसरी तरफ पुलिस की खोई हुई बन्दूकें जब्त करने के लिए पीजीए बलों ने जनता की सक्रिय मदद से खोज-बीन जारी रखी। इससे उन्हें पांच बन्दूकें मिल गईं। इनमें एक लाइट मशीनगन, एक एके-47 और तीन एसएलआर रायफलें थीं। इस प्रकार जनता को मारने के लिए उपयोग किए जाने वाले पुलिस के आधुनिक हथियार जन सैनिक बलों के हाथ में आ गए। इस पूरे घटनाक्रम से आक्रमण अभियान चलाने की पुलिस की योजना बुरी तरह विफल हो गई। एक पुलिस जवान का नदी में डूब मरना, जिला एसपी समेत छह पुलिस वालों का घायल होना, नदी में बन्दूकें डूब जाना, उनका फिर से पीजीए सैनिकों के हाथों में पड़ जाना, पुलिस के दुष्प्रचार का पर्दाफाश होना – इन सभी घटनाओं ने दुश्मन को जितना झकझोर दिया, इस इलाके की जनता और पार्टी व पीजीए के कतारों को उतना ही उत्साहित किया। ✶

सभा - सम्मेलन

15 अगस्त को दण्डकारण्य जनता ने मनाया 'काला दिवस'

15 अगस्त 1947 की झूठी आजादी को बेनकाब करते हुए दण्डकारण्य के गांव-गांव में पार्टी और जन संगठनों ने व्यापक प्रचार किया। भले ही शासक यह ढिंढ़ोरा पीटें कि आजादी के 57 बरस पूरे हो गए हैं पर जनता को रोज-रोज यह ज्यादा स्पष्ट हो रहा है कि यह आजादी झूठी है। भारत के शासक वर्ग एक तरफ साम्राज्यवादियों के आदेशों को सिर पर उठाकर देश के हितों की गिरवी रखकर, देश की सम्प्रभुता को मिट्टी में मिलाते हुए, दूसरी तरफ आजादी का जश्न मनाना सरासर धोखेबाजी है। आज भी जनता भुखमरी, कुपोषण, बीमारी, सूखा-अकाल, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार आदि ज्वलंत समस्याओं से पीड़ित है जबकि मुट्ठी भर लुटेरे मालामाल हो रहे हैं। गरीबों और सम्पन्न लोगों के बीच खाई रोज-रोज बढ़ती जा रही है। ये सारे हालात यह साबित कर रहे हैं कि यह असली आजादी नहीं है। पिछले 25 सालों से क्रान्तिकारी आन्दोलन में संगठित हो रही दण्डकारण्य जनता शुरू से ही 15 अगस्त को काले दिवस के रूप में मनाती आ रही है। ज्यों-ज्यों जनता की राजनीतिक चेतना बढ़ रही है, त्यों-त्यों इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। दूसरी ओर सरकार अखबारों के जरिए यह प्रचार करवा रही है कि 15 अगस्त को काला दिवस मनाना देशद्रोह है। दरअसल देशवासियों के हितों के साथ खिलवाड़ करते हुए विदेशी साम्राज्यवादियों और उनकी मुद्रा संस्थाओं के हाथों बिक चुकी सरकारें ही देश के साथ बड़ी गद्दारी कर रही हैं। पहले भी, जबकि राजग सत्ता में था और अब भी, जबकि संप्रग सत्ता में है, हमारे देश में देशद्रोहपूर्ण नीतियां ही लागू हो रही हैं। इसलिए असली आजादी पाने के लिए देशवासियों की प्रगति और आत्मनिर्भरता के रास्ते में रोड़े बने सामंतवाद, साम्राज्यवाद और दलाल नौकरशाह पूंजीवाद को जड़ों से उखाड़ फेंककर जनता की जनवादी राजसत्ता कायम करनी होगी। इसी लक्ष्य से हमारे दण्डकारण्य में और देश के कुछ अन्य हिस्सों में हमारी पार्टी और हमारी बिरादराना पार्टी एमसीसीआई के नेतृत्व में क्रान्तिकारी आन्दोलन जारी है। क्रान्ति के जरिए ही शोषित-पीड़ित जनता को असली आजादी मिल सकती है जो देश का 80 प्रतिशत है। काले दिवस के मौके पर आयोजित सभाओं में उपस्थित लोगों को मुख्य रूप से इन्ही विषयों पर जोर देते हुए संदेश दिया गया।

माड़ डिवीजन में ...

कुतुल गांव में काले दिवस के मौके पर आयोजित सभा में 250 लोगों ने भाग लिया। इनमें छात्र भी शामिल थे। पहले गांव की गलियों में जुलूस निकालकर लुटेरी सरकार और साम्राज्यवाद के खिलाफ बड़े पैमाने पर नारे लगाए गए। बाद में आयोजित सभा को जन संगठन कार्यकर्ताओं में सम्बोधित किया। वक्ताओं ने बताया कि 15 अगस्त को सत्ता सिर्फ गोरे लुटेरों के हाथों से काले लुटेरों के हाथों में आई है, जबकि असली आजादी नहीं मिली है। उन्होंने जनता को समझाया कि इस तथाकथित आजादी के बाद 57 साल गुजरने के बावजूद भी देशवासियों की बुनियादी समस्याओं का कोई समाधान न हो सका। अगर जनता अकाल, बेरोजगारी, बीमारी इत्यादि अपनी बुनियादी समस्याओं को लेकर लड़ती है तो सरकारें दमन का प्रयोग कर रही हैं। ऐसे में यह कैसी आजादी होगी, ऐसा वक्ताओं ने जमकर आलोचना की। वक्ताओं ने आगे कहा कि आज दण्डकारण्य के गांव-गांव में निर्मित *जनतना सरकार* के अंग ही जनता को असली आजादी और सच्चे जनवाद की गारन्टी दे सकती हैं, अतः उन्हें मजबूत बनाते हुए जनयुद्ध को व्यापक तौर पर फैलाते जाने से ही देशव्यापी *जनतना सरकार* के निर्माण की दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं।

कोह्कामेट्टा इलाके में मुरनार, वेच्चा और गुड्डापारा गांवों की जनता ने एक स्थान पर बैठक कर काला दिवस मनाया। इन गांवों के स्कूली छात्रों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। कुल लगभग 250 लोगों ने झूठी आजादी के खिलाफ नारे लगाते हुए जुलूस निकाला। बाद में लोगों ने काला झण्डा उठाया। डीएकेएमएस के सदस्यों ने झूठी आजादी को बेनकाब करते हुए गीत पेश किए। उसके बाद कुछ वक्ताओं ने सभा को सम्बोधित किया। उन्होंने अपने भाषण में 15 अगस्त की गद्दारी पर अपनी बात रखी। क्रान्तिकारी नारों और गीतों से उत्साह के साथ सभा सम्पन्न हुई।

कोह्कामेट्टा इलाके के इरकभट्टी गांव में भी जनता ने झूठी आजादी के खिलाफ काला दिवस मनाया। इस सभा में जनता ने "ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है' कहकर नारे लगाए। बाद में काला झण्डा गाड़ दिया गया। गांव के संगठन अध्यक्ष ने उपस्थित लोगों को सम्बोधित किया। उन्होंने अपने भाषण में असली आजादी के लिए लड़कर शहीद हुए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरू, सुभाषचन्द्र बोस, आजाद चन्द्रशेखर, गुण्डाधुर, बाबूराव सेडिमेक आदि क्रान्तिकारियों को याद किया। उन्होंने गांधी, नेहरू, आदि दलाल नेताओं की यह कहकर आलोचना की कि उन्होंने उन शहीदों के अरमानों के साथ गद्दारी की। बाद में कोह्कामेट्टा दस्ता कमाण्डर कॉमरेड कौसल्या और महिला दस्ता कमाण्डर कॉमरेड नीला बाई ने सभा को सम्बोधित किया। इस सभा में 250 लोगों ने भाग लिया। क्रान्तिकारी गीतों के गायन के साथ सभा का समापन हो गया।

पश्चिम बस्तर डिवीजन में ...

भैरमगढ़ इलाके में कुल 12 गांवों में झूठी आजादी का पर्दाफाश करते हुए सभाएं हुईं। एक-एक गांव में करीबन 350-400 लोगों ने भाग लिया। इन सभाओं को सम्बोधित करने वाले वक्ताओं ने कहा कि हमारे देश को आजादी मिलने के दावे किए जाने के बावजूद अत्यधिक जनता को कुछ नहीं मिला। सत्ता में चाहे कांग्रेस रहे या भाजपा, प्रदेश की जनता की जिन्दगी में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आया, नहीं आएगा भी। उन्होंने जनता का आह्वान किया कि हमारी जिन्दगी को बदलने के लिए क्रान्तिकारी आन्दोलन में संगठित होकर गांव-गांव में जनता की राजसत्ता के अंगों का निर्माण करें।

शहीद-ए-आज़म भगत सिंह की बरसी

गड़चिरोली डिवीजन के भामरागढ़ इलाके के गोपनार व दोबूर गांवों में जनता ने 23 मार्च को शहीद-ए-आज़म भगत सिंह की बरसी के मौके पर सभाएं आयोजित कीं। ब्रितानी साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने वाले भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव को अंग्रेजी शासकों ने 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी। भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव ऐसे

क्रान्तिकारी थे जिन्होंने यह चाहा और सपना देखा था कि देश को सम्पूर्ण आजादी मिले और वह मुट्ठी भर लुटेरों के हाथों में न चले जाए बल्कि देश के मेहनतकश किसान-मजदूरों को मिले। उन्होंने यह ऐलान किया था कि इसके लिए क्रान्ति के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आज दण्डकारण्य में जारी क्रान्तिकारी आन्दोलन उन तमाम शहीदों के मकसद को पूरा करने की दिशा में ही आगे बढ़ रहा है। इसीलिए दण्डकारण्य की जनता हर साल 23 मार्च को भगत सिंह और उनके साथियों को याद करके साम्राज्यवाद के खिलाफ उनके द्वारा छेड़े गए संघर्ष को पूरा करने का अपना संकल्प दोहराती है। सभा के पहले लोगों ने "भगत सिंह अमर रहें", "साम्राज्यवाद मुर्दाबाद", "पोटा कानून को रद्द करो" आदि नारे लगाते हुए जुलूस निकाला। बाद में आयोजित सभा में बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि भगत सिंह को मौत की सजा देने में गांधी और नेहरू ने अंग्रेजों के साथ सांठगांठ की थी। उन्होंने वर्तमान शासकों की यह कहकर खिल्ली उड़ाई कि गांधी-नेहरू के वारिस ही आज 23 मार्च को भगत सिंह की बरसी मना रहे हैं। उन्होंने जनता को बताया कि राजग सरकार ने पोटा कानून लाकर जनता का लौह पैरों से दमन करते हुए कई बेकसूर लोगों को जेलों में डाल रही है। जहां कांग्रेस इस कानून का विरोध करने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश की कांग्रेस-राकांपा गठबन्धन सरकार इस कानून का अमल कर रही है। वक्ताओं ने कहा कि इससे कांग्रेस का दोगलापन साफ साबित हो जाता है। वक्ताओं ने आगे कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जार्ज बुश द्वारा छेड़े गए तथाकथित "उग्रवाद विरोधी युद्ध" में शामिल होने वाली राजग सरकार ने उसी के नक्शेकदम पर चलते हुए जनता पर पोटा कानून लादा है। आखिर में लोगों ने जार्ज बुश और वाजपेयी के पुतले जला दिए। इसके साथ ही सभा का समापन हुआ।

अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस – मई दिवस

गड़चिरोली जिले की एटापल्ली तहसील के गट्टा एरिया में एक स्थान पर आयोजित सभा में तीन गांवों से 140 स्त्री-पुरुषों ने भाग लिया। सभा को सम्बोधित करने वाले वक्ताओं ने अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के महत्व और उसके इतिहास के बारे में बताया। 1886 के मई में अमेरिका के मजदूरों द्वारा किए गए ऐतिहासिक संघर्षों के बारे में तथा उनकी न्यायोचित मांगों के बारे में विस्तारपूर्वक बताया। वक्ताओं ने कहा कि आज सराकारें मई दिवस को सरकारी पर्व में बदलकर उसके क्रान्तिकारी सारांश को लोगों से छुपा रही हैं। क्रान्ति में मजदूर वर्ग की भूमिका तथा मजदूर-किसान एकता के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने यह भी बताया कि गड़चिरोली जिले में भी बांस कटाई आदि कामों में आदिवासी मजदूरों को पूंजीपतियों द्वारा किस तरह लूटा जा रहा है। उन्होंने विस्तार से बताया कि मजदूर-किसान एकता क्रान्ति में काफ़ी महत्वपूर्ण है।

इसी जिले के अहेरी इलाके के कुरुंबापल्ली गांव में भी 1 मई को 40 लोगों ने बैठक करके अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया। रापल्ली गांव में आयोजित एक और सभा में 30 लोगों ने भाग लिया। लाल झण्डा फहराए जाने के बाद दुनिया भर में मजदूर वर्ग द्वारा किए गए बहादुराना संघर्षों और उनकी कुरबानियों को याद किया गया। मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़कर शहीद हुए कॉमरेडों के सम्मान में दो मिनट खामोशी मनाकर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर बोलते हुए वक्ताओं ने सरकार द्वारा अमल की जा रही मजदूर-विरोधी व किसान-विरोधी नीतियों की जमकर निंदा की। मजदूर दिवस के मौके पर साम्राज्यवाद व दलाल नौकरशाह पूंजीवाद के खिलाफ जनता ने नारेबाजी की। साथ ही, समतामूलक समाज की स्थापना के लिए तथा नई जनवादी क्रान्ति की सफलता के लिए लड़ने की शपथ ली।

22 अप्रैल को जनता ने मनाया पार्टी का जन्म दिवस

गड़चिरोली डिवीजन के पेरिमिलि इलाके के ताड़िगांव रेंज में एक स्थान पर 22 अप्रैल को पार्टी का जन्म दिवस मनाया गया। इस मौके पर 250 स्त्री-पुरुषों ने भाग लिया। सबसे पहले पार्टी का झण्डा फहराकर शहीदों को श्रद्धांजलि पेश की गई। बाद में सभा की अध्यक्षता करते हुए कॉमरेड रघु ने कहा कि हमारी पार्टी ने दक्षिणपंथी अवसरवाद और संशोधनवाद के खिलाफ समझौताहीन संघर्ष के दौरान ही जन्म लिया है। उन्होंने आगे कहा कि जबसे हमारी पार्टी का जन्म हुआ, तभी से शासक वर्ग फासीवादी दमन का प्रयोग करते हुए इसे कुचलने का प्रयास करते आ रहे हैं। इसके बावजूद हमारी पार्टी रोज-रोज शक्तिशाली बनते हुए आज एक देशव्यापी पार्टी के रूप में उभर चुकी है। बाद में कॉमेरड सुधीर व कॉमरेड करपा ने भी उपस्थित जनता को सम्बोधित किया।

उत्तर बस्तर में 8 मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस

8 मार्च के पहले से ही केएएमएस और डीएकेएमएस के सदस्यों ने गांव-गांव जाकर अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के महत्व के बारे में प्रचार किया। पर्चे, पोस्टर और दीवार-लेखन के जरिए जनता में व्यापक प्रचार किया गया। बारदा एलजीएस इलाके के मुलाइ और बारदा गांवों में आयोजित महिला दिवस के कार्यक्रम में 1,500 स्त्री-पुरुषों ने भाग लिया। इनमें महिलाओं की बड़ी संख्या थी। इन सभाओं का आयोजन केएएमएस रेंज कमेटी ने किया। अन्तागढ़ रेन्ज में 8 मार्च के मौके पर 14 गांवों से आए 500 महिलाओं ने एक बैठक आयोजित कर अपनी समस्याओं पर चर्चा की। किसकोड्डो रेंज में केएएमएस रेंज कमेटी अध्यक्षा की अगुवाई में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। उन्होंने झण्डा फहराकर कार्यक्रम का प्रारम्भ किया। बाद में लोगों ने उन तमाम स्त्री-पुरुष शहीदों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने महिला मुक्ति के लिए लड़कर अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। बाद में वक्ताओं ने सभा को सम्बोधित किया। मेचानार गांव में आयोजित एक और सभा में 700 पुरुषों और 300 महिलाओं ने भाग लिया। इस सभा में दो स्थानीय गुरिल्ला दस्तों और स्थानीय सीएनएम टीमों ने भाग लिया। इन्होंने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए उनसे जनता काफी उत्साहित हुए। इस मौके पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में भाग लेने वाली महिलाओं ने पितृसत्ता के रूपों के बारे में चर्चा की। इसमें महिलाओं ने ये विचार व्यक्त किए कि महिलाओं को सम्पत्ति पर अधिकार हो, जबरिया विवाह और बाल विवाह की प्रथा बन्द हो, लड़कियों की मर्जी के बिना ही शराब पीकर शादी का रिश्ता तय करने की प्रथा बन्द हो, उत्पादन से सम्बन्धित कामों में महिलाओं को समान भागीदारी का हक मिले तथा तमाम प्रकार का भेदभाव बन्द हो। सेमिनार के आखिर में, तमाम महिलाओं ने बढ़ती साम्राज्यवादी संस्कृति की घुसपैठ और उसके साथ-साथ फैल रही उपभोक्तावादी संस्कृति के खिलाफ नारे लगाए। ★

14वीं लोकसभा चुनावों के मौके पर अमल
फासीवादी पुलिस दमन - बहादुराना जन प्रतिरोध

(पिछले अंक में हम 14वीं लोकसभा चुनावों के बहिष्कार पर और उस मौके पर सरकार द्वारा अमल पुलिस दमन के सम्बन्ध में पूरी रिपोर्टें पेश नहीं कर सके। प्रस्तुत अंक में और ब्यौरे के साथ कुछ अन्य रिपोर्टें पेश कर रहे हैं। – सम्पादकमण्डल)

लोकसभा चुनावों के मौके पर लुटेरी सरकार द्वारा बर्बरतापूर्ण दमन चलाए जाने के बावजूद जनता ने बड़ी संख्या में झूठे चुनावों का बहिष्कार किया। चुनावी पार्टियों के नेताओं ने संघर्ष इलाकों में कदम रखने का साहस ही नहीं किया। उनका प्रचार पूरा सिर्फ उन्हीं गांवों तक सीमित रहा जो कि मेन रोड पर स्थित हैं या जहां पर पुलिस थाने मौजूद हैं। अत्यधिक मतदान केन्द्रों में मतदान कर्मी आए ही नहीं थे। इसके बावजूद यह रिपोर्ट की गई थी कि वहां पर मतदान बड़ी संख्या में हुआ है। इन चुनावों के मौके पर सरकार द्वारा अमल दमन और उसके जवाब में जनता व जन छापामार सैनिकों द्वारा अमल कार्रवाइयों की रिपोर्टें डिवीजनवार पेश हैं।

दक्षिण बस्तर डिवीजन

जेगुरगोंडा एरिया में ...

चुनाव बहिष्कार के विषय पर डीएकेएमएस व केएएमएस कार्यकर्ताओं से राजनीतिक कक्षा ली गई। बाद में डीएकेएमएस के 13 और केएएमएस के 9 दलों ने कुल 63 गांवों में प्रचार किया। इस प्रचार में स्थानीय सीएनएम इकाइयों ने भी भाग लिया। इस मौके पर तीन जगहों में बड़ी आमसभाएं सम्पन्न हुईं। इनमें 35 गांवों से लगभग 3,000 लोगों ने भाग लिया। इस इलाके में कुल 40 बैनर, 80 पोस्टर व 2,000 पर्चे लगाए-बांटे गए। इसके अलावा कई गांवों में दीवारों पर नारे लिखे गए। डाम्बर रोड के ऊपर भी पेन्ट से चुनाव बहिष्कार के नारे लिखे गए। इस प्रकार चुनाव बहिष्कार का प्रचार बड़े पैमाने पर किया गया, जबकि चुनाव प्रचार के लिए राजनेताओं ने इस इलाके में कदम तक नहीं रखा।

दमन

पुलिस व अर्ध सैनिक बलों ने मार्च के आखिरी सप्ताह से ही दमन बढ़ा दिया। जेगुरगोंडा और चिन्तलनार में डेरा जमाए हुए दो कम्पनी बीएसएफ ने रात के समय दस्तों के लिए घात लगाना, दिन में गांवों पर छापेमारियां करना आदि जुल्मी कार्रवाइयां जारी रखीं। चिन्तलनार एएसआइ सिंगर की अगुवाई में कोत्तागूडेम, मोर्रुम आदि गांवों पर छापेमारियां की गईं। लेकिन जनता पुलिस की गिरफ्त में नहीं आई। अप्रैल की शुरूआत से बासागूडेम पुलिस ने लिंगागिरी, धर्मारम, डोलिगूडेम, कोर्पागूडेम, सार्किनगूडा, अवुटुम, आदि गांवों में हमले किए। 20 अप्रैल तक इन गांवों में पुलिस ने 6-7 दफे गश्त की। चिन्ना तर्रेम गांव में आई पुलिस ने 25 मुरगे उठा लिए। एक किसान को उसने बुरी तरह पीटा।

13 अप्रैल को पुल्लमपाड गांव में चिन्तलनार पुलिस ने एक महिला के साथ बलात्कार की कोशिश की। लेकिन वह महिला पुलिस की गिरफ्त से निकल भाग गई। इस गांव से पुलिस ने कुल 26 मुरगे और 2 बकरे उठा लिए। 2 अप्रैल के दिन भी पुलिस ने इस गांव पर छापेमारी की। चिन्तलनार पुलिस ने ताडिमेट्टा गांव के बगल में स्थित जंगल में दस्तों के लिए चार बार घात लगाया। पुलिस ने अपनी झोंपड़ियां बनवाने के लिए रावुगूडेम, लच्चिगूडेम, किष्टारम और कोत्तागूडेम गांवों की जनता को डरा-धमकाकर जबरन बेगारी काम करवा लिया। बासागूडेम पुलिस ने राजुपेन्टा और कोत्तागूडेम गांवों में दो किसानों की बुरी तरह पिटाई की। कोरसागूडेम में एक और पेगिडिपल्ली में दो लोगों की पिटाई करके उन्हें रास्ता दिखाने को जबरन ले जाकर बाद में छोड़ दिया। धर्मापुरम गांव में यह चेतावनी दी कि संगठन कमेटी सदस्य आकर आत्मसमर्पण करें वरना उनके घर जला दिए जाएंगे।

जन प्रतिरोध

- अप्रैल में बासागूडेम से चिन्ना तर्रेम आए पुलिस व बीएसएफ बलों पर पीजीए के आधार बलों की टीम ने बारूदी सुरंग का विस्फोट करके हैरान कर दिया।
- 20 अप्रैल, मतदान के दिन चिन्तलनार से वोटिंग मशीनों के साथ पेद्दा बोडिकेल की ओर रवाना हुई टुकड़ी पर तुम्मिरिगूडेम के निकट मिलिशिया टीम ने क्लेमोर माइन के विस्फोट कर हमला किया। फायरिंग करते हुए पुलिस वापिस चली गई।
- इसकी आवाज सुनकर मदद में निकली चिन्तलनार पुलिस पर एक और मिलिशिया टीम ने ग्रेनेड से हमला किया। इससे पुलिस घबराकर थाना वापिस भाग गई।
- 20 अप्रैल को ही जेगुरगोंडा से पेंटा गांव आकर लौट रहे पंजाब कमाण्डो बलों पर पीजीए दस्ते ने पीछे से हमला बोल दिया जिससे वे फायर करते हुए भाग गए। हड़बड़ाहट में वे पानी और खाने के डिब्बे भी छोड़ गए जिन्हें जनता ने उठा लिया।
- 22 अप्रैल को जब बीएसएफ की दो कम्पनियां मतदान पूरा करके वापिस जा रही थीं तब पीजीए छापामारों ने हमला बोल दिया। इसमें एक बीएसएफ जवान मारा गया जबकि दो अन्य बुरी तरह घायल हो गए। जोगुरगोंडा से दन्तेवाडा जाने वाली सड़क पर हुई इस घटना से दुश्मन डर से कांप उठा।

चुनाव बहिष्कार

मतदान के दिन पुलिस सिर्फ छह मतदान केन्द्रों में आई थी जहां सड़क की सुविधा थी। आधे घण्टे के अन्दर ही वापिस चली गई। इन गांवों के लोगों में से कोई भी वोट नहीं डाला। सारे वोट पुलिस ने ही डाल लिए। पर जेगुरगोंडा और चिन्तलनार गांवों में, जहां पर पुलिस थाने हैं, और गांव मखरम में बहुत कम संख्या में लोगों ने वोट डाला। बाकी वोट पुलिस ने ही डाल लिए।

किष्टारम एरिया में ...

फरवरी से ही विभिन्न हथियारबन्द इकाइयों और पार्टी इकाइयों ने चुनाव बहिष्कार का प्रचार अभियान शुरू किया। अप्रैल में पूरे इलाके में प्रचार अभियान चलाया गया। डीएकेएमएस और केएएमएस के 29 दलों ने इस प्रचार अभियान में भाग लिया। इसमें सीएनएम के दस्ते भी शामिल थे। सीएनएम ने 8 जगहों पर आमसभाएं आयोजित करके जनता से झूठे

चुनावों का बहिष्कार करने का आह्वान किया। एक स्थान पर हाट बाजार में सांस्कृतिक प्रदर्शन आयोजित किया गया। कुल 90 गांवों में यह प्रचार का सिलसिला चला। लगभग 500 पर्चे और 50 पोस्टर इस प्रचार में खर्चे गए। चुनाव लड़ने वाली लुटेरी पार्टियों का इस इलाके में कोई अता-पता तक नहीं चला। चुनाव प्रचार के लिए इस इलाके में एक भी आदमी ने कदम नहीं रखा।

दमन

किष्टारम इलाके में मौजूद तीन पुलिस थानों के अलावा सीआरपीएफ और बीएसएफ की तीन कम्पनियों को तैनात किया गया। इन्होंने साझे तौर पर गांवों में धावा बोलकर जनता पर हमले किए। 9 मार्च को सुकमा एएसपी और कोंटा एसडीओपी की अगुवाई में सीआरपी बलों ने गोल्लापल्ली, किष्टारम से होकर टेट्टेमडुगु, पालोडी तक जाकर गांवों पर छापेमारियां कीं। इसमें माराइगूडेम, गोल्लापल्ली और किष्टारम के थानेदारों समेत कुल 105 पुलिस वालों ने भाग लिया। टेट्टेमडुगु गांव में वे तीन घरों में घुसकर कुल 10,700 रुपए की नगद, एक भरमार, चांदी, सोना, मुरगे, साखा मांस, कुल्हाड़ियां, तीर-धनुष, जन सरकार द्वारा दिए गए जमीन के पट्टे उठा ले गए। कुछ पुलिस वालों ने तो घरों से खाना, पेज-पसिया और शराब को भी उठा लिया। लगभग एक घण्टे तक चले आतंक के ताण्डव के बाद उन्होंने अपने साथ एक किसान को ले जाकर उसके साथ काफी मारपीट करके छोड़ दिया। जाते-जाते पालोडी गांव में एक किसान के घर में घुसकर सायकिल भी उठा ले गए। मार्च महीने में सिंगनमडुगु गांव के निवासी मडकाम मासाल को किष्टारम पुलिस ने तब गिरफ्तार कर लिया जब वह अपने निजी काम पर आन्ध्र जाकर आ रहा था। उसके विरुद्ध गलत मामले दर्ज करके जेल भेजा गया। सुकमा पुलिस अब इससे थाने में बेगारी में रसोई का काम करवा रही है। 7 अप्रैल को अम्मापेन्टा गांव पर पुलिस ने हमला किया पर एक भी व्यक्ति पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। जाते-जाते वेदापाड से तीन और मंगेलगूडेम से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर ले गए। किष्टारम पुलिस थाने में इन्हें यातनाएं देने के बाद एक व्यक्ति को जेल भेज दिया गया जबकि बाकी को छोड़ दिया गया। तीगेल गांव में भी छापेमारी करके भूतपूर्व दस्ता सदस्य दिनेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एक संगठन नेता का पीछा करके जब वह नहीं मिले तो पुलिस उनकी सायकिल उठा ली।

गोल्लापल्ली पुलिस ने वेंजलवाइ गांव पर चार बार हमले किए। कुल पांच लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक संगठन सदस्य की खूब पिटाई करके उसे जबरन गांवों, पहाड़ों और नालों में घुमाया। बाद में इन पांचों को जेल भेज दिया। वेंजलवाई में डीएकेएमएस नेता धर्माल के घर पर हमला करके घर जला दिया। इसमें रोजमर्रा की कई जरूरी चीजें जलकर राख हो गईं। इसके अलावा 2 हजार रुपए की नगद, महुआ, गहने, कपड़े, मुरगे, इमली, तेल, सुअर इत्यादि जितना भी मिला उठा ले गई। मोसलिमडुगु से एक और वेंजल से एक किसान को तब गिरफ्तार किया जबकि वे महुए के फूल बीन रहे थे। इन्हें गोल्लापल्ली थाने में तीन दिन रखकर तरह-तरह की यातनाएं देने के बाद छोड़ दिया गया। वेंजलवाई में स्थित मोटु शहीदों के स्मारक को पुलिस ने कुछ हद तक ध्वस्त किया। 7 अप्रैल को पुलिस ने राइगूडेम गांव पर छापेमारी करके वहां एक विवाह समारोह में भाग ले रहे ग्रामवासियों को पकड़ लिया। उनमें से आठ युवकों को अलग करके साथ ले गई। दो दिन बाद इनमें से सात व्यक्तियों को छोड़ दिया, जबकि एक व्यक्ति, जो जन संगठन का सदस्य था, कुछ दिन और गोल्लापल्ली थाने में ही रखकर खूब यातनाएं देकर बाद में जेल भेज दिया। भट्टीगूडेम गांव पर हमला करके तीन किसानों को गिरफ्तार किया और इनमें से दो लोगों को जेल भेज दिया।

मराइगूडेम पुलिस गंगिलेर गांव पर छापा मारकर पांच लोगों को गिरफ्तार किया। इन्हें खूब यातनाएं देने के बाद चार को छोड़ दिया एक को जेल भेज दिया।

निम्मलगूडेम गांव के दो डीएकेएमएस नेताओं और बूटाल (करिगुण्डम) में एक डीएकेएमएस रेंज कमेटी नेता को आन्ध्र पुलिस ने गिरफ्तार कर बिजली के झटकों से क्रूरतापूर्ण यातनाएं देने के बाद जेल भेज दिया। 15 अप्रैल को अम्मापेन्टा गांव आ रही पुलिस ने सड़क पर किसानों को देखकर उन पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी।

इसके अलावा कासारम, बूटाल, दोरमंगुम, पूसुगूडेम, गंगाराजू, सिंगारम, चंद्रुगूडेम आदि गांवों पर भी पुलिस ने छापेमारियां कीं। लेकिन जनता इनके हत्थे नहीं चढ़ी। मतदान के दिन 20 अप्रैल को सिंगारम गांव के लिए निकले पुलिस वालों ने वंजलवाई और सिंगारम गांवों में महुआ बीनने वाले किसानों (ज्यादा महिलाएं ही थीं) की घेराबन्दी कर डरा-धमकाकर जबरन मतदान केन्द्र ले जाकर वोट डलवाया। सिंगारम गांव में घरों में घुसकर चावल और मुरगे उठाकर खा लिए। चंद्रगूडेम आए पुलिस वालों ने ग्रामवासियों को डरा-धमकाकर जबरन वोट डलवा लिए।

इस प्रकार किष्टारम एरिया में मार्च 2004 से प्रारम्भ हुआ पुलिस का दमन अभियान अप्रैल के आखिर तक जारी रहा। कुल 18 गांवों पर छापेमारियां की गईं। इनमें से कुछ गांव तो ऐसे थे जिन पर चार-चार बार हमले किए गए। कुल 33 लोगों को गिरफ्तार कर उनमें से 16 को जेल भेज दिया।

जन प्रतिरोध

पुलिस के हमलों को देखते हुए जनता ने गांवों में संतरी तैनात रखने, पुलिस के आते ही गांव खाली करने, इत्यादि तरीके अपनाए।

- मार्च में टेट्टेमडुगु और पालोडि गांवों पर छापेमारी करके जा रही

कोत्ताचेरुवु गांव में झूठी मुठभेड़

20 अप्रैल को बीएसएफ जवानों का एक दल कोत्ताचेरुवु गांव के लिए निकल पड़ा। गांव के बाहर महुआ बीन रहे मडकाम हडमा नामक किसान को उन जवानों ने नजदीक से गोली मार दी जिससे उसकी तत्काल ही मौत हो गई। वह करीब 55 साल की उम्र का एक आम किसान था। वह बहरा भी था, इसलिए पुलिस की आहट को भी नहीं सुन सका था। पुलिस ने इसे मुठभेड़ के रूप में चित्रित करने के लिए जंगल में कुछ गोलियां दागकर, चार मोर्टार शेल दागकर कहानी तैयार की। उन्होंने यह प्रचार किया कि वहां से कुछ दूर पर मिलिशिया द्वारा बिछाए गए बम से इस किसान का सम्बन्ध था। लेकिन स्थानीय जनता को यह अच्छी तरह मालूम था कि यह बिलकुल मनगढन्त कहानी है। पुलिस वाले हडमा की लाश को मोटार सायकिल पर रखकर थाने में ले गए थे। उसके बाद गांव की जनता, खासकर महिलाओं ने थाने में जाकर हडमा की लाश मांग लाई। तब तक वह सड़ चुकी थी। पुलिस इस भ्रम में है कि इस प्रकार की घिनौनी कार्रवाइयों के जरिए वह जन आन्दोलन को दबा सकती है। लेकिन सच तो यह है कि गेन्द को जितने जोर से जमीन पर पटक दोगे तो उतने ही जोर से वह उछल पड़ेगी।

ग्रामीण महिलाओं का प्रतिरोध

कोत्ताचेरुवु गांव में पुलिस मडकाम हडमा की झूठी मुठभेड़ में हत्या करके लाश एर्राबोर थाना ले गई। बाद में गांव की महिलाएं थाना जाकर पुलिस से लड़कर अपने ग्रामवासी की लाश लाई थीं। इसके अलावा रेगडी और मोसलु गांव की महिलाओं ने भेजी पुलिस के साथ लड़कर गिरफ्तार ग्रामवासियों को रिहा करवा लिया। महिलाओं के इन संघर्षों ने इस इलाके में तमाम जनता को प्रेरणा दी।

पुलिस पर पीछे से कुछ मिलिशिया सदस्यों ने हैरान करने की मंशा से हमला किया। इस हमले से डरकर 105 पुलिस वाले जहां के वहीं जमीन पर लेट गए और 10 मिनट तक चिल्लाते रहे। बाद में उठकर तेजी से भाग गए।

- 10 अप्रैल को बूटाल जा रही पुलिस पर मिलिशिया दस्ते ने सुअरों को मारने के लिए प्रयुक्त बम का विस्फोट किया जिसके जवाब में पुलिस ने सैकड़ों गोलियां व्यर्थ में चलाईं।
- 18 अप्रैल को गांवों पर छापेमारी करने के लिए गोल्लपल्ली से निकल रहे बीएसएफ व स्थानीय पुलिस बलों पर पीजीए के सैनिकों ने हमला किया, दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक गोलीबारी चलती रही। इससे पुलिस की आक्रामकता पर एक हद तक अंकुश लग गया।
- 20 अप्रैल को मतदान के दिन जनता से जबरन वोट डलवाने के लिए चंद्रुगूडेम आकर जा रही बीएसएफ-पुलिस दल पर पीजीए सैनिकों ने हमला किया। 10 मिनट तक गोलीबारी चली। इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ।

मतदान प्रक्रिया

इस इलाके में कुल 100 गांव हैं। मतदान के दिन गोल्लापल्ली पुलिस दो गांवों (सिंगारम और चंद्रुगूडेम) में वोटिंग मशीनें लेकर आई जहां मतदान केन्द्र थे। उन्होंने जनता को पकड़कर धमकी देकर जबरन वोट डलवाए। इस प्रकार सिंगारम में 39 मत और चंद्रुगूडेम में 12 मत पड़े थे। बाद में किष्टारम पुलिस ने खुद को तीन दलों में बांटकर पुलिस थाने से कुछ दूर जंगल में जाकर एक जगह बैठकर खुद ही वोट डाले थे। कोंटा पुलिस आंध्र की सीमा में आने वाले गांव मल्लापेन्टा से दुरमा की ओर आने वाले रास्ते में जंगल में बैठकर खुद ही वोट डालकर वापिस गई। मराईगूडेम पुलिस के डर से आसपास के तीन-चार गांवों के लोगों ने वोट डाले। किष्टारम और गोल्लापल्ली गांवों, जहां पुलिस थाने मौजूद हैं, में लोगों ने वोट डाले। इस प्रकार देखें तो 88 गांवों में मतदान का पूरा बहिष्कार हुआ, जबकि 12 गांवों के लोगों ने कम संख्या में सही मतदान में भाग लिया।

कोंटा इलाके में ...

इस इलाके में बहिष्कार का प्रचार मार्च के आखिर से शुरू हुआ। इसमें डीएकेएमएस के 12 और केएएमएस के 12 प्रचार दलों ने भाग लिया। इस इलाके में सीएनएम के दलों ने चुनाव बहिष्कार के प्रचार में उत्साह के साथ भाग लिया। कई जगहों पर बड़ी-बड़ी आमसभाएं आयोजित की गईं। जनता ने कई जगहों पर मशाल-जुलूस भी निकाला जिसमें झूठे चुनावों का बहिष्कार करने का नारा प्रमुख रूप से लगाया गया। राजग के पिछले आठ साल के शासन में हमें कुछ नहीं मिला कहते हुए जनता ने वाजपेयी और आडवाणी के पुतले जला दिए। तमाम जन संगठन कार्यकर्ताओं ने इस प्रचार कार्यक्रम में सक्रिय भाग लिया। बुर्जुवाई पार्टियों का चुनावी प्रचार इस इलाके में कहीं भी दिखाई नहीं दिया। सिर्फ भाकपा के लोगों ने सिर्फ कोंटा और दोरनापाल कस्बों तक आकर प्रचार किया। उससे बढ़कर गांवों में कदम रखने का साहस ही नहीं किया।

पुलिसिया दमन और अर्ध सैनिक बलों द्वारा तेज गश्त और खोजबीन अभियान इस इलाके में भी जारी थे। कुल 120 लोगों को गिरफ्तार करके उन्हें काफी यातनाएं देकर उनमें से 8 लोगों को जेल भेजा गया, बाकी लोगों को छोड़ दिया गया। इस मौके पर कोत्ताचेरुवु गांव में एक झूठी मुठभेड़ में मडकाम हडमा नामक एक सामान्य किसान की हत्या की। एक और गांव में एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया।

पुलिस दमन के खिलाफ जन प्रतिरोध की कार्रवाइयां

- 14 अप्रैल को विंजरम के निकट पीजीए छापामारों ने पुलिस के वाहन को बारूदी सुरंग से उड़ा दिया जिसमें दो सीएसएफ जवान कुत्ते की मौत मारे गए और पांच अन्य घायल हुए। इस विस्फोट के बाद अन्य वाहनों में बैठे पुलिस वालों और छापामारों के बीच भीषण गोलीबारी हुई। छापामारों को कोई नुकसान नहीं हुआ।
- ए[ज्गट्टा के निकट तीन छापामारों की टीम ने पुलिस वालों पर एम्बुश किया। किसी को कुछ नहीं हुआ।
- गगनपल्ली गांव के निकट मिलिशिया टीम ने पुलिस को हैरान करने की मंशा से एक विस्फोट किया।
- गोरखा गांव के निकट सड़क पर और स्कूल के नजदीक अलग-अलग मिलिशिया टीमों ने क्लेमोर माइन विस्फोट करके पुलिस को हैरान कर दिया।

चुनाव बहिष्कार

पूरे एरिया में कुल 20 मतदान केन्द्र हैं तो सिर्फ 8 केन्द्रों में ही पुलिस आई थी और खुद ही वोट डालकर लौट गई । बाकी 12 मतदान केन्द्रों में कोई आए ही नहीं थे। मतदान का पूरी तरह बहिष्कार हुआ।

पामेड इलाके में ...

चुनाव बहिष्कार के विषय पर डीएकेएमएस और केएएमएस के 110 सक्रिय कार्यकर्ताओं से पार्टी ने एक दिन की राजनीतिक कक्षा ली। बाद में इनसे डीएकेएमएस के 12 और केएएमएस के 11 प्रचार दल गठित किए गए जिन्होंने गांवों में प्रचार अभियान चलाया। इस प्रचार के काम में सीएनएम दलों ने भाग लिया। इलाके में कुल 9 जगहों पर बड़ी आमसभाएं आयोजित की गईं। कुल 90 गांवों में चुनाव बहिष्कार का प्रचार किया गया। इसमें 200 पोस्टर और 40 बैनर इस्तेमाल किए गए। कई जगहों पर दीवार-लेखन की गई। बुर्जुवाई पार्टियों के द्वारा चुनाव प्रचार इस पूरे इलाके में कहीं भी नहीं किया गया। कोई भी चुनावी पार्टी ने यहां कदम नहीं रखा।

दमन

मार्च के शुरू से ही पुलिस व अर्ध सैनिक बलों ने दमन का सिलसिला शुरू किया। बासागूडेम पुलिस ने 22 मार्च को पोलेमपल्ली गांव पर छापेमारी की। उसके दो दिन बाद ऊसूर पुलिस ने पूजारीकांकेर गांव पर तथा पामेड पुलिस ने कौरगट्टा गांव पर छापेमारी की। उसी दिन, यानी 24 मार्च को बासागूडेम पुलिस ने गंगनपल्ली गांव पर छापेमारी की। ग्रामवासियों

के साथ मार-पीट कर रास्ता दिखाने को कहते हुए प्रताड़ित किया। 28 मार्च को ऊसूर के पुलिस वाले पूजारीकांकेर आए और उन्होंने वहां के आसपास के पांच गांवों से 10 लोगों को गिरफ्तार कर रात भर अपने साथ स्कूल में सुला लिया। अगले दिन पूजारीकांकेर गांव की एक महिला को गिरफ्तार कर बुरी तरह यातनाएं दीं। दस्ते की मदद करने के आरोप में बाद में उस महिला को जेल भेज दिया। बुस्सापुरम गांव की पांच लोगों की पिटाई करके उनसे दो हजार रुपए की रिश्वत वसूल कर छोड़ दिया।

मोद्दिगूडा, जारापल्ली, गामापाड, रापम, जोडिपल्ली, एमपुरम, कचाल और कौरगट्टा गांवों पर पामेड पुलिस ने छापेमारियां कीं। धर्मारम गांव से 12 लोगों को गिरफ्तार किया। गल्लम, पुट्टेपाड, इत्तागूडेम और नडुमपल्ली गांवों से 14 लोगों को गिरफ्तार कर उन्हें बुरी तरह पीटकर बाद में दो लोगों को जेल भेज दिया। गलगाम गांव में 7 लोगों को गिरफ्तार किया। पूरे इलाके में इस दमनचक्र के तहत पुलिस ने कुल 44 लोगों को गिरफ्तार करके उनमें से 4 लोगों को जेल भेज दिया। 28 अप्रैल को भी कोंडापल्ली गांव में पुलिस ने दो लोगों की पिटाई की। चुनावों के मौके पर ऊसूर इलाके के कुछ परम्परागत मुखियाओं और नडिमपल्ली गांव के जमींदार ने पुलिस की मदद करके संगठन सदस्यों को गिरफ्तार करवाया। बाद में इन लोगों को जनता ने संगठन के नेतृत्व में जन अदालत में दण्डित किया। चुनावों के संचालन के लिए इस इलाके में मौजूद ऊसूर, पामेड और बासागूडेम पुलिस थानों के अतिरिक्त बीएसएफ की एक-एक कम्पनी तैनात कर दी गई। बीएसएफ जवानों ने जनता को बुरी तरह प्रताड़ित किया।

कोंटा इलाके में पीजीए द्वारा दो पुलिस वालों की गिरफ्तारी - रिहाई

दन्तेवाड़ा जिला, सुकमा तहसील, पटनमपारा निवासी वेट्टी राजू दन्तेवाड़ा आदिवासी पुलिस थाने में आरक्षक के रूप में काम कर रहा था। यह 18 मार्च को जब पोलमपल्ली गांव में अपना ससुराल आया था तो जनता और जन मिलिशिया ने मिलकर इसे गिरफ्तार किया। चूंकि इसके खिलाफ जन विरोधी कार्रवाइयों में भाग लेने का कोई आरोप नहीं था, इसलिए पीजीए छापामारों ने क्रान्ति के लक्ष्य तथा जनयुद्ध की राजनीति के बारे में समझाकर कुछ दिन बाद, 26 मार्च को छोड़ दिया।

इसी प्रकार 19 मई को जब भेज्जी थाने में काम करने वाला इसदोर खालको नामक सीएएफ जवान बस में जा रहा था तो पीजीए के आधार बल सैनिकों ने इसे गिरफ्तार किया। बाद में उसे स्थानीय दस्ते को सौम्प दिया गया। इसे भी छापामारों ने दो-तीन दिन रखकर क्रान्तिकारी राजनीति और पार्टी के लक्ष्य के बारे में समझाकर छोड़ दिया। इन घटनाओं से क्रान्तिकारियों के बारे में कई गलतफहमियों का शिकार होने वाले आम पुलिस वालों को सचाई को समझने में सहायता मिल रही है। इन मौकों पर पीजीए सैनिक आम पुलिस वालों के प्रति उसकी नीति स्पष्ट तौर पर बता रहे हैं। उन्हें यह याद दिलाते हुए कि वे भी गरीबों के बच्चे हैं, यह अपील करते हुए छोड़ रहे हैं कि गरीबों के खिलाफ वे बन्दूक न चलाएं।

जन प्रतिरोध

- पूजारीकांकेर में स्कूल में सोए बीएसएफ जवानों पर मिलिशिया दस्ते ने क्लेमोर बमों से हमला किया। बीएसएफ वाले रात भर गोलीबारी करते रहे।
- बासागूडेम से कोंडापल्ली आए बीएसएफ और स्थानीय पुलिस को निशाना बनाकर छापामारों ने नलकूप के पास एक बम फोड़ दिया जिससे दुश्मन रात भर गोलीबारी करता रहा।
- इसी दल पर जब वह बासागूडेम वापिस जा रहा था, गुण्डम गांव के निकट जन मिलिशिया टुकड़ी ने क्लेमोर माइनों से हमला किया। इसमें एक हवलदार मारा गया और दो अन्य बीएसएफ जवान घायल हैं।
- मारे गए हवलदार की लाश और घायल जवानों को ले जा रहे पुलिस वालों का छापामारों ने पीछा किया। इससे वे जान हथेली पर रखते हुए जनता को जबरन मानव ढाल के रूप में आसपास रखकर बासागूडेम पहुंचे। इस मौके पर स्थानीय पुलिस व बीएसएफ के बीच तीखी नोंकझोंक हुई। बीएसएफ वाले यह कहते हुए स्थानीय पुलिस अधिकारियों पर बरस पड़े कि उनसे बार-बार मांगे जाने के बावजूद वे मदद करने नहीं पहुंचे थे।
- पामेड के पुलिस वालों के लिए बैलगाड़ी में आ रही आपूर्तियों को पीजीए के आधार बल ने रोक दिया।
- तोंगूडेम-पामेड के बीच पैदल आ रहे पुलिस वालों पर मिलिशिया ने गोलीबारी की। दोनों ओर से गोलीबारी हुई पर कोई घायल नहीं हुए।
- 13 अप्रैल को ऊसूर से पूजारीकांकेर आ रहे बीएसएफ जावनों के दल पर पीजीए के लड़ाकुओं ने गुंजूर गांव के पास घात लगाकर हमला किया जिसमें दो अधिकारियों समेत पांच जवान घायल हुए।

मतदान प्रक्रिया

इस इलाके में कुल 15 मतदान केन्द्र हैं, पर मतदान सिर्फ ऊसूर और पामेड में ही हुआ जहां पुलिस थाने थे। पुलिस के डर से इनके आसपास के कुछ गांवों से भी चन्द लोगों ने मतदान किया। बाकी सभी गांवों के लोगों ने चुनावों का पुरी तरह से बहिष्कार किया। अत्यधिक गांवों में मतदान कर्मी आए ही नहीं थे।

पश्चिम बस्तर डिवीजन

सीआरपीएफ, बीएसएफ, पंजाब कमाण्डो, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के हजारों बलों के बर्बरतम दमन का मुकाबला करते हुए पश्चिम बस्तर की जनता ने चुनावों का बहिष्कार किया। इस डिवीजन के दायरे में स्थित 300 गांवों में से सिर्फ 32 गांवों ने ही, यानी 10.6% गांवों ने ही मतदान में भाग लिया। ये तमाम गांव या तो सड़कों पर बसे हुए हैं या फिर पुलिस थाना गांव हैं। पूरे डिवीजन में कुल 80 प्रतिशत जनता ने झुठे चुनावों का बहिष्कार किया।

जन प्रतिरोध

- भोपालपटनम से मद्देड आने वाली सड़क पर स्थित उस्कलेड गांव के पास तीन सदस्यीय पीजीए टीम ने पुलिस पर घात लगाकर हमला किया। 19 अप्रैल के दोपहर को जब पुलिस मोटार सायकिल पर आ रही थी तब यह हमला हुआ। इसमें चार पुलिस घायल हुए।

- 17 अप्रैल को फरसेगढ़ पुलिस थाने से सागुमेट्टा आ रहे पंजाब कमाण्डो बलों पर सालेपल्ली गांव के निकट पीजीए सैनिकों ने हमला किया। इस एम्बुश में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। पंजाब कमाण्डो बलों पर बस्तर में किया गया पहला हमला था यह। बाद में उनके कमाण्डेन्ट ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "पूर्व में पंजाब में दिन हमारा और रात उनका (राष्ट्रीय आन्दोलनकारियों का) हुआ करता था। पर अब ऐसा लगता है कि यहां पर दिन और रात दोनों उन्हीं (नक्सलवादियों) के हैं।" ऐसी टिप्पणियों से उनके बुरी तरह गिर चुके मनोबल को समझा जा सकता है।
- 19 अप्रैल की रात जब पंजाब कमाण्डो सागुमेट्टा गांव में कुत्ता भोंकने और पत्तों की सरसराहट से भी भय खाते हुए एक-एक पल को एक-एक युग की तरह काट रहे थे, पीजीए छापामारों ने फिर एक बार उन पर धावा बोलकर एक ग्रेनेड फेंका और कुछ गोलियां चलाईं। इसके बाद कायर कमाण्डो रात भर गोलियां चलाते हुए, मोर्टारों से गोलाबारी करते रहे।
- 19 अप्रैल को ही जगदलपुर-बीजापुर रोड पर माटवाडा-जांगला गांवों के बीच स्थित पुल के नीचे पीजीए छापामारों ने बारूदीसुरंग लगा दी। पर पिछले कुछ दिनों से पूरे बस्तर में हो रहे हमलों को देखते हुए पुलिस का काफिला पुल से थोड़ी दूर पर ही रुक गया ता। कुछ पुलिस वाले पुल की तलाशी लेने के लिए पैदल आगे बढ़ रहे थे तो छापामारों ने बारूदी सुरंग को चिनगारी दिखा दी। इसके तुरन्त बाद उन्होंने गोलीबारी भी शुरू की। इसमें एक कमाण्डेंट समेत दो पुलिस वाले घायल हुए, जबकि छापामारों की ओर से कोई नुकसान नहीं हुआ।
- मिरतुल एलजीएस के दायरे में पुल्लुम गांव में स्थित मतदान केन्द्र की सुरक्षा में आए पुलिस वालों ने जब गांव के स्कूल भवन में मुकाम किया हुआ था, तब छापामारों ने उन पर हमला किया। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई पर किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। अगले दिन जब पुलिस वाले निकलने की तैयारी में थे तब गांव की जनता ने उनका सामान ढोने से इनकार किया। इससे पुलिस को झक मारकर खुद ही अपना सामान उठाना पड़ा।

गड़चिरोली डिवीजन

गड़चिरोली जिले के टिप्रागड़ इलाके के दराची गांव में चुनाव के बन्दोबस्त में आए पुलिस दल पर पीजीए सैनिकों ने हमला बोल दिया। इस हमले का उद्देश्य पुलिस को हैरान करना था। पर हमले में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। पुलिस तो रात भर गोलीबारी करती रही और रोशनी देने वाले बम (फ्लेयर) फोड़ते रही।

उत्तर बस्तर डिवीजन

किसकोड्डो इलाके में ...

उत्तर बस्तर डिवीजन के किसकोड्डो इलाके में झूठे चुनावों का बहिष्कार करने का प्रचार बड़े पैमाने पर चलाया गया। पोस्टर, बैनर, पर्चों के अलावा जगह-जगह पर दीवार-लेखन भी की गई। कई गांवों के लोगों को इकट्ठा करके चुनाव बहिष्कार सभाएं आयोजित की गईं। ग्राम हुचाडी में आयोजित सभा में 3 गांवों से 40 महिलाओं और 60 पुरुषों ने भाग लिया। किसकोड्डो गांव में आयोजित एक और सभा में 10 गांवों के लोगों ने भाग लिया। कुल 260 लोगों की उपस्थिति में आयोजित इस सभा के पहले लोगों ने गगनभेदी नारे लगाते हुए जुलूस निकाला।

कुदुरुपारा गांव में आयोजित सभा में 6 गांवों से 120 स्त्री-पुरुषों ने भाग लिया। गांव पीपरा में आयोजित जुलूस में 60 पुरुषों और 40 महिलाओं ने बाग लिया। इलाके के लगभग सभी बड़े गांवों और हाट बाजारों में जुलूस निकाल कर चुनाव बहिष्कार का संदेश लोगों तक पहुंचाया गया।

जन प्रतिरोध - बहिष्कार

जिन-जिन गांवों में मतदान केन्द्र थे उन तमाम गांवों में मतदान के दिन पुलिस आई थी और जनता को मार-पीटकर वोट डालने पर मजबूर किया। गवाडी गांव में पुलिस ने छोटे बच्चों से भी जबरन वोट डलवाया। इसके बावजूद गवाडी में सिर्फ 6 वोट, अर्रा में 5 वोट, किसकोड्डो में 10 वोट पड़े। अर्रा गांव में मतदान के लिए आए पुलिस वालों ने लोगों के घरों में घुसकर बकरे-मुरगे उठाकर खा लिए। आसपास के गांवों से एक भी आदमी वोट डालने नहीं आया।

इस इलाके में जनता और जन मिलिशिया ने मिलकर कुल पांच वोटिंग मशीनें जब्त कर लीं। दो जगहों पर मिलिशिया ने पुलिस पर गोलीबारी की। दो अन्य जगहों पर स्थानीय छापामार दस्तों ने पुलिस पर गोलीबारी की।

बारदा एलजीएस इलाके में ...

चुनाव बहिष्कार के प्रचार के लिए इस इलाके में डीएकेएमएस के 4 और केएएमएस के 2 प्रचार दलों को गांवों में भेजा गया। प्रचार कार्य में 300 पोस्टर और 500 पर्चे बांटे गए। लगभग 30 गांवों में दीवार-लेखन की गई। पराल गांव में इस मौके पर आयोजित एक सभा में आसपास के गांवों से 200 पुरुषों और 180 महिलाओं ने भाग लिया। तुरकी गांव में आयोजित सभा में 75 महिलाओं और 110 पुरुषों ने भाग लिया। कोनगुड गांव में आयोजित सभा में 50 महिलाओं और 150 पुरुषों ने भाग लिया। आमगांव में आयोजित सभा में 100 महिलाओं और 200 पुरुषों ने भाग लिया। इन सभाओं का आयोजन डीएकेएमएस और केएएमएस उरुंदाबेड़ा रेंज कमेटियों ने संयुक्त रूप से किया। चिंगनार गांव में डीएकेएमएस की अगुवाई में जनता ने एक जुलूस निकाला। इस रैली में लगभग 500 स्त्री-पुरुषों ने भाग लिया। व्यापक प्रचार के फलस्वरूप बारदा एलजीएस इलाके में 12 गांवों की जनता ने चुनावों का सम्पूर्ण बहिष्कार किया।

जन प्रतिरोध

- 18 अप्रैल की रात धनोरा से ग्राम हाटचपाई आकर स्कूल में मुकाम करने वाले पुलिस दल पर मिलिशिया दस्ते ने भरमारों से हमला किया। पर पुलिस बिना कोई गोली चलाए ही अन्दर ही रह गई। सुबह पांच बजते ही सीधा धनोरा चल दी।

माड़ डिवीजन

कोह्कामेट्टा इलाके में ...

इस इलाके में जन संगठनों और मिलिशिया संगठनों के तमाम इकाइयों ने चुनाव बहिष्कार अभियान में भाग लिया। इस इलाके में चुनाव बहिष्कार 99% सफल हुआ। भले ही सरकार ने फर्जी मतदान करवाकर झूठे आंकड़े पेश किए हों, पर सचाई यही है कि इस इलाके के लगभग शत प्रतिशत लोगों ने चुनावों का बहिष्कार किया।

दमन

सोनपुर, मरहापदर, कुंदला और कोह्कामेट्टा में पुलिस ने 20 लोगों को बुरी तरह पीटा। इन्हीं गांवों के 27 लोगों को (इनमें 10 छोटे बच्चे शामिल थे) पकड़कर मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। बाद में इनमें से आधे लोगों को छोड़ दिया जबकि बाकी लोगों को कई दिनों तक अपनी हिरासत में रख लिया। सोनपुर गांव में स्थित दो दुकानों से पुलिस ने सामान चोरी कर लिए। कोह्कामेट्टा में 2, सोनपुर में 30, कुंदला में 2, कीहकड में 1 – कुल 35 घरों को पुलिस ने ध्वस्त कर दिया। दरवाजे तोड़ देना, सामान उठाकर बाहर फेंक देना आदि कार्रवाइयों का हिसाब ही नहीं रहा। सोनपुर गांव में सभी घरों में घुसकर सारा सामान फेंक-फांक दिया। कोह्कामेट्टा आश्रम पाठशाला का दरवाजा तोड़ दिया। छात्रों के कपड़ों, पेटियों आदि को बाहर फेंक दिया। आश्रम के भीतर ही मल-मूत्र त्यागकर उसे पाखाने से भी बदतर बना दिया। मुरगे उठाकर खा लेना, अंडे लेकर खाना आदि घटनाओं का हिसाब ही नहीं रहा। मरहापदर गांव में एक किसान पर गोली चला दी। नेलनार गांव पर छापेमारी करके वहां मौजूद भूमकाल शहीदों के स्मारक को तोड़कर वहां से तीन युवकों को गिरफ्तार किया। नारायणपुर कस्बे में 'दैनिक भास्कर' के पत्रकार शीतल प्रकाश पर सीआरपी जवानों ने हमला किया। नारायणपुर में जनता पर सीआरपी बलों के अत्याचारों के खिलाफ उन्होंने 12-13 अप्रैल को अखबार में रिपोर्ट जो लिखी थी, वहीं उनका गुनाह था। नारायणपुर में रहकर असपास के हाट-बजार घूमकर धंधा करने वाले छोटे व्यापारियों को भी सीआरपी बलों ने बुरी तरह पीटा।

जन प्रतिरोध

इस इलाके में छापामार दस्तों और मिलिशिया ने कुल सात जगहों पर पुलिस पर एम्बुश किया। छह जगहों पर पुलिस के मुकामों पर गोलीबारी की। इन तमाम घटनाओं में कुल 13 पुलिस वाले जख्मी हो गए। रातों में मिलिशिया द्वारा लगातार बारी-बारी से की गई गोलीबारी से पुलिस भयभीत हो गए। यहां तक कि टट्टी-पेशाब करने के लिए भी वे बाहर न आकर स्कूली भवन को खराब करके कायरता का प्रदर्शन किया। पुलिस व अर्ध सैनिक बलों को यह डर हर दम सताता रहा कि कहां कदम रखने से कौन सा बूबी ट्रैप फट जाए और कहां से कब गोली चल जाए। इन तमाम घटनाओं में पुलिस ने हजारों गोलियों और सौ से ज्यादा मोर्टार के गोले खर्च किए।

इंद्रावती इलाके में ...

दमन

बड़ेपल्ली गांव में डीएकेएमएस रेंज कमेटी सदस्य के घर पर पुलिस ने रात के 3 बजे धावा बोल दिया। वहां से दो महिलाओं और छह युवकों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार महिलाओं के साथ पुलिस व अर्ध सैनिक बलों ने सामूहिक बलात्कार किया। बाद में एक महिला भाग गई जबकि बुधरी नामक दूसरी महिला को नक्सली बताकर झूठी मुठभेड़ में कत्ल कर दिया। छोटेपल्ली गांव के तीन किसानों – चैतु कोपाल, मंगुडु और बुधराम को गिरफ्तार किया। इनमें से चैतू की मौत पुलिस की यातनाओं से हुई। लाश को पुलिस ने खुद रहकर गांववालों से जलवा दिया। बाकी दो लोगों को जेल में कैद कर दिया जिनकी अभी तक रिहाई नहीं हुई।

जन प्रतिरोध

- जाटलूर और आदेर इलाकों में चुनाव के पहले और बाद में तीन जगहों पर पीजीए बलों ने गोलीबारी की, पर इन घटनाओं में दोनों पक्षों को कोई नुकसान नहीं हुआ।
- 3 अप्रैल को इंद्रावती इलाके के धरमा गांव में स्कूल में डेरा लगाने वाले पुलिस वालों पर पीजीए सैनिकों ने गोलीबारी की।
- 4 अप्रैल के दोपहर जब वही दल वापिस जा रहा था तब रास्ते में ताडुम गांव के पास पीजीए की एक और टुकड़ी ने घात लगाकर हमला किया। इसमें भी कोई घायल नहीं हुआ।

चुनाव बहिष्कार

इंद्रावती इलाके में कुल 14 मतदान केन्द्र थे तो उनमें सिर्फ बाइल, ताकिलोड, पोल्लेवाया और कुडिमेर गांवों में ही सभी मतदान केन्द्रों के मत डाले गए। अत्यधिक गांवों के लोगों ने वोट ही नहीं डाला। कुडिमेर, ताकिलोड और पोल्लेवाया में जितना भी मतदान दर्शाया गया पूरी तरह से झूठा है। मतदान कर्मियों और सशस्त्र बलों ने मिलकर फर्जी मतदान किया। इन गांवों से एक भी मतदाता ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। दरअसल पुलिस दमन से भयभीत होकर मतदान केन्द्रों वाले गांवों की जनता पहले ही गांव खाली करके जंगल चली गई थी।

परालकोट इलाके में ...

इस इलाके में पोस्टर, पर्चों के जरिए चुनाव बहिष्कार का प्रचार चलाया गया। सभी जन संगठनों ने इस कार्यक्रम में उत्साह के साथ भाग लिया। कुतुल गांव में आयोजित चुनाव बहिष्कार सभा में 500 लोगों ने भाग लिया।

परालकोट इलाके में दुश्मन ने काफी दमन चलाया। चुनाव प्रक्रिया के शुरू होने से पहले ही 25 मार्च को पुलिस ने तोके गांव पर छापेमारी करके जनता के सामूहिक कृषि केन्द्र को ध्वस्त कर दिया। वहां पर एक मकान को तोड़कर सारा सामान नष्ट कर दिया। तीन किसानों को गिरफ्तार कर यातनाएं देकर एक दिन बाद छोड़ दिया। उसी दिन एक अन्य किसान को गिरफ्तार करके उससे 5 हजार रुपए रिश्वत वसूलकर छोड़ दिया। 40 पुलिस वालों के एक दल ने इरपानार गांव पर धावा बोल दिया। 12 घरों की इस बस्ती पर पुलिस बलों ने सात साल के बच्चे से लेकर बूढ़ों तक सभी पर कहर बरपाया। किसानों से कुल्हाड़ियां, चाकू, तीर-धनुष और दो भरमार बन्दूकें जब्त कर लीं। कद्देर, बेरेवेडा गांवों पर हमला करके किसानों के औजारों को भी हथियार बताकर जब्त कर लिया। एक किसान को बुरी यातनाएं दीं।

चुनाव के पहले 3 अप्रैल को गश्त पर आए सैकड़ों सशस्त्र बलों ने डोंडरीबेड़ा गांव पर छापेमारी की और वहां से एक किसान को यातनाएं देते हुए नारायणपुर तक ले जाकर छोड़ दिया। चुनाव के तीन दिन पहले ही निकले सशस्त्र बलों ने पीजीए के हमलों से डरकर जनता को जबरन अपने साथ रखकर मानव ढाल की तरह इस्तेमाल किया। जहां जनता ने इससे इनकार किया वहां पर उन्होंने लोगों को मारा। गारपा आए पुलिस वालों ने मसपूर के निवासियों को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल किया। बाद में ओरादी गांव के किसानों को मारपीट कर गारपा तक ले जाया गया। गांव सितरम में वोट डालने इनकार करने पर चार किसानों को

(शेष पृष्ठ 47 पर ....)

(.... अन्तिम पृष्ठ का शेष)

सहायता, मारे गए किसानों को एक लाख रुपए का मुआवजा, इत्यादि वायदे सत्तारूढ़ गठबन्धन कर रहा है, जबकि विपक्षी पार्टियां भी इससे बढ़कर वायदे कर रही हैं। दरअसल, आज किसान जिस बदहाली के शिकार हैं उसके लिए सरकारों द्वारा अमल साम्राज्यवाद-अनुकूल आर्थियां ही जिम्मेदार हैं। किसानों की जिन्दगियों के साथ खिलवाड़ करते हुए डब्ल्यूटीओ पर दस्तखत करने वाली सरकार ही अब किसानों की मुसीबतों पर मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। इन किसान-विरोधी नीतियों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच पूरी सहमति है। इतने सालों से केन्द्र में सत्तारूढ़ रही भाजपा-नीत राजग सरकार और प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस-राकांपा गठबन्धन सरकार दोनों भी इस अपराध में समान रूप से भागीदार हैं। इसलिए, फिलहाल वोट पाने के लिए चाहे कोई भी जो भी बोले, यह समझ लेना मुश्किल नहीं है कि ये सब किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ करने वाले ही हैं।

ज्यों ही चुनाव नजदीक आ गए, सत्तारूढ़ गठबन्धन ने आनन-फानन में यह घोषणा की कि राज्य में नौकरियों की नियुक्ति पर रही पाबन्दी को वह उठा रही है। बन्द चीनी मिलों को खुलवाने, निजी क्षेत्र में पिछड़ों और दलितों को आरक्षण लागू करने तथा अकाल-पीड़ित इलाकों में युद्ध स्तर पर राहत-पुनर्वास कार्यक्रम लागू करने की घोषणाएं भी कीं। साफ जाहिर हैं ये सब प्रदेश के नौजवानों को झांसा देने के लिए ही हैं। शिंदे सरकार ने यह भी घोषणा की कि वह सामान्य श्रेणी की डेढ़ लाख नौकरियों की नियुक्ति करेगी। यहां गौरतलब यह है कि नौकरियों की नियुक्ति पर ठीक इसी सरकार ने रोक लगाई थी। वर्तमान में प्रदेश में रोजगार के दफ्तरों में अपना नाम दर्ज करा चुके पढ़े-लिखे बेरोजगारों की संख्या 45 लाख हैं। कई बेरोजगार बदहाल जिन्दगी से तंग आकर आत्महत्या भी कर रहे हैं। सरकार इन्हें झूठे आश्वासनों से छलकर वोट बटोरने की कोशिश में है। सरकारों द्वारा अमल नई आर्थिक नीतियों के कारण ही देश में बेरोजगारी छाई हुई है। इन नीतियों पर अमल का सिलसिला कांग्रेस सरकार ने शुरू किया जिसे भाजपा ने सुचारू रूप से जारी रखा। ऐसे में इस बदहाली के लिए दोनों पार्टियां बराबर जिम्मेदार हैं। इसलिए नौजवानों को चाहिए कि वे इन दोनों को बेनकाब कर दें और चुनावों का बहिष्कार करें।

विदर्भ क्षेत्र की जनता लम्बे अरसे से यह मांग करती आ रही है कि पृथक विदर्भ राज्य का गठन किया जाए। लेकिन लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियां विदर्भ राज्य के गठन का विरोध कर रही हैं। लेकिन ज्यों ही चुनाव नजदीक आ गए, वे विदर्भवासियों पर ढेर सारा प्यार उंडेलते हुए यह घोषणा कर रही हैं कि वे विदर्भ राज्य के गठन के खिलाफ नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी यह कह रही है कि वह विदर्भ के मामले में भी वही रवैया रखती है जो वह पृथक तेलंगाना राज्य के गठन के प्रति रखती है। सच यह है कि कांग्रेस ने पृथक तेलंगाना के गठन पर अभी तक कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया और तेलंगाना के गठन पर एक शब्द बोलने मात्र से वह उसके घटक दल तेलंगाना राष्ट्र समिति के साथ ऐसा धमकियों भरा बरताव कर रही है कि वह चाहे तो गठबन्धन से जा सकती है। ऐसे में यह समझना मुश्किल नहीं होगा कि कांग्रेस के इस आश्वासन में कोई दम नहीं है और विदर्भ के गठन के प्रति वह गंभीर नहीं है। इसलिए सिर्फ वोटों पर नजर रखकर विदर्भ के गठन के सवाल पर झूठ-मूठ की बातें करने वाली तमाम अवसरवादी पार्टियों को विदर्भवासी जरूर सबक सिखा देंगे।

पिछले पांच सालों के शासन में महाराष्ट्र में जितने घोटाले उजागर हुए, उसका हिसाब ही नहीं रहा। देश में तहलका मचाने वाले स्टाम्प पेपर घोटाले में सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई नेताओं का हाथ रहा। उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल को इस घोटाले के चलते अपना पद ही खोना पड़ा। 5,000 करोड़ रुपए के चावल घोटाले में भी कई नेताओं का हाथ रहा। उधर आपराधिक पृष्ठभूमि वालों को सत्ता से बाहर करने की मांग उठाने वाली भाजपा ने खुद कई दागियों को सीटें देकर अपने दोगलेपन को साबित किया। सत्ता पक्ष और विपक्ष की सभी पार्टियां आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को सीटें दे रही हैं।

पिछले मई माह में भाजपा-नीत राजग की पराजय के कारणों की समीक्षा करते हुए संघ गिरोह ने फैसला किया कि अब उग्र हिन्दुत्ववादी नीतियों की ओर रुख किया जाए। इसके तहत ही संघ गिरोह के सारे संगठनों ने एक योजना के मुताबिक फासीवादी नीतियों पर अमल की प्रक्रिया में तेजी लाई। विहिप नेता प्रवीण तोगड़िया महाराष्ट्र में त्रिशूल बांटते हुए उसका 'गुजारातीकरण' करने की कोशिश कर रहा है। मुसलमानों की सदियों पुरानी मस्जिदों और दर्गाओं को ढहाने का आह्वान करते हुए संघ गिरोह की ताकतें जनता में उन्माद फैला रही हैं। एक ओर विकास की रट लगाते हुए ही दूसरी ओर जनता में धार्मिक उन्माद भड़काकर समाज को मध्य युगों की ओर ले जाने की कोशिश कर रही हैं। पूर्व में मुम्बई समेत कई शहरों व कस्बों में साम्प्रदायिक दंगे भड़काकर हजारों मुसलमानों का कत्लेआम करने में सेना-भाजपा का हाथ रहा। बुनियादी समस्याओं से जनता की नजर हटाने के लिए ही वे योजनाबद्ध ढंग से धार्मिक उन्माद भड़का रही हैं। पर खुद को धर्मनिरपेक्षवादी बताने वाली कांग्रेस संघ गिरोह की ताकतों के साथ तुष्टीकरण की नीति पर चलते हुए व्यवहार में हिन्दू फासीवादियों का सहयोग ही कर रही है। संशोधनवादी पार्टियों समेत अन्य सभी पार्टियों का कहना चाहे जो भी हो, पर वे वास्तव में संघ गिरोह की ताकतों से दृढ़तापूर्ण संघर्ष के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए इन झूठी राजनीतिक पार्टियों को सही सबक सिखाते हुए बढ़ते हिन्दू फासीवाद के खिलाफ व्यापक स्तर पर एकताबद्ध होने की जरूरत है।

महाराष्ट्र में दलितों के वोट बटोरे बिना ज्यादा सीटें जीतना मुश्किल है, यह समझते हुए सत्ता पक्ष और विपक्ष की पार्टियां तरह-तरह की चालबाजियां कर रही हैं। जहां कांग्रेस ने दलित (सुशील कुमार शिंदे) को मुख्यमंत्री बनाकर दलितों को रिझाने की तिकड़मबाजी की, वहीं शिवसेना ने "शिव शक्ति - भीम शक्ति" का नारा लगाते हुए दलितों को अपनी तरफ कर लेने की कोशिश शुरू की। आज महाराष्ट्र में, जहां ज्योतिबा फूले और आंबेडकर के समय से ही दलित चेतना विकसित हुई थी, तमाम दलित पार्टियां घनघोर अवसरवाद और अंदरूनी कलहों में डूब चुकी हैं। इस तर्क में अब कोई दम नहीं रह गया है कि चुनाव जीतकर सत्ता पाने से दलितों की उन्नति हो सकती है। इसके बावजूद भी आरपीआई, बीएसपी, लोक जनशक्ति इत्यादि पार्टियां दलितों को

इसी तर्क के सहारे धोखे में रख रही हैं। यह सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में दलित मुख्यमंत्री मायावती ने दलितों का कितना उत्थान किया है। दलितों को चाहिए कि वे ऐसी अवसरवादी पार्टियों से धोखा न खाते हुए नई जनवादी क्रान्ति में भागीदार हों। उन्हें इस सचाई को समझ लेना चाहिए कि दलित सवाल का हल जनवादी क्रान्ति से ही होगा जो सामंतवाद को जड़ से सफाया कर देगी।

महाराष्ट्र के दक्षिण-पूर्वी दिशा में मौजूद गड़चिरोली, गोंदिया और चन्द्रपुर जिलों में हमारी पार्टी की अगुवाई में क्रान्तिकारी आन्दोलन जारी है। मुख्य रूप से आदिवासी इलाकों में केन्द्रित यह आन्दोलन देश में सामंतवादी, दलाल नौकरशाह पूंजीवादी और साम्राज्यवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंककर मजदूर-किसान एकता की बुनियाद पर उत्पीड़ित जनता की संयुक्त राज्यसत्ता की स्थापना करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। महाराष्ट्र सरकार इन इलाकों में क्रूरतापूर्ण पुलिसिया दमन का प्रयोग करते हुए क्रान्तिकारी आन्दोलन को कुचल डालने की कोशिश कर रही है। पूर्ववर्ती सेना-भाजपा गठबन्धन सरकार और वर्तमान कांग्रेस-राकांपा गठबन्धन सरकार दोनों ने यहां की आदिवासी जनता पर टाडा, पोटा जैसे क्रूरतम कानून लागू करके भीषण दमनचक्र ही चलाया। झूठी मुठभेड़ें, गिरफ्तारियां, यातनाएं, जेल में बन्दी बनाना, गांवबन्दी के नाम पर क्रान्तिकारियों के खिलाफ जनता को उकसाने की कोशिशें, इत्यादि कई रूपों में सरकारें दमन को जारी रखे हुई हैं। सी-60 बलों के नाम से गठित कमाण्डो बलों ने जनता पर अमानवीय अत्याचार और कत्लेआम का सिलसिला जारी रखा हुआ है। भीषण पुलिस दमन के बीच ही जन आन्दोलन आगे बढ़ रहा है। गांव-गांव में क्रान्तिकारी राजसत्ता के अंगों के निर्माण का काम जारी है। दण्डकारण्य को मुक्त इलाके में बदलने के लक्ष्य के तहत गड़चिरोली जिले में क्रान्तिकारी आन्दोलन कई चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ रहा है। जनता अपने विकास का जिम्मा अपने हाथों में लेते हुए सरकार के झूठे विकास कार्यक्रमों का विरोध कर रही है। मौजूदा गैर-जनवादी व्यवस्था में होने वाले चुनावों को झूठा करार देते हुए वह उनका बहिष्कार कर रही है। महाराष्ट्र की तमाम उत्पीड़ित जनता को इसी रास्ते पर चलना होगा। चुनावों से हमारी जिन्दगी नहीं बदलेगी। चाहे जो भी जीते जनता पर जारी शोषण और उत्पीड़न का अन्त नहीं होगा। सभी चुनावी पार्टियां लुटेरे वर्गों की पार्टियां ही हैं। इसीलिए इस व्यवस्था को जड़ से बदलने वाली नई जनवादी क्रान्ति में भाग लेते हुए झूठे चुनावों का बहिष्कार करना चाहिए। शोषण, उत्पीड़न, असमानता, भेदभाव, भुखमरी, अपमान, बेरोजगारी, बीमारी इत्यादि समस्याओं से मुक्त समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए क्रान्ति ही एक मात्र रास्ता है। ★

(.... पृष्ठ 45 का शेष)

पुलिस ने बुरी तरह मारा-पीटा। बाद में जब गांव की महिलाओं ने उनका विरोध किया तब उन्हें छोड़ दिया।

जन प्रतिरोध

- 18 अप्रैल को गारपा के निकट सीआरपी और स्थानीय पुलिस का संयुक्त दल पीजीए के घात हमले में फंस गया। इसमें दो पुलिस वाले घायल हो गए। पर दुर्भाग्य से इस हमले के दौरान तीन ग्रामीण भी घायल हो गए जिन्हें पुलिस जबरन पकड़ ला रही थी। इनमें से बोरा दुरवा नामक किसान ने बाद में दम तोड़ दिया। स्थानीय पार्टी ने इस घटना पर खेद व्यक्त किया। मृतक किसान के परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की।
- 19 अप्रैल को फिर से मिलिशिया दस्ते ने गारपा में मुकाम किए हुए शत्रु बलों पर गोलीबारी की। इस घटना में किसी को कुछ नहीं हुआ। दुश्मन भयभीत होकर गोलीबारी करता रहा।

चुनाव बहिष्कार

परालकोट इलाके में पिछले साल दिसम्बर में हुए विधानसभा चुनावों और अब के लोकसभा चुनावों का भी जनता ने पूरी तरह से बहिष्कार किया। पिछली बार कुछ जगहों पर लोगों ने पुलिस से डरकर वोट डाला था पर इस बार तो पुलिस द्वारा जान से मारने की धमकियां दिए जाने पर भी वोट नहीं डाला। सिर्फ सितरम गांव में पुलिस लोगों को डरा-धमकाकर वोट डलवाने में कामयाब हो गई। इस एक गांव को छोड़कर कहीं भी मतदान नहीं हुआ। गारपा गांव के कुछ लोग, जो क्रान्तिकारी आन्दोलन के विरोधी हैं, नारायणपुर भाग गए थे। सरकार ने उन लोगों से नारायणपुर में ही वोट डलवाकर नाटकबाजी की। इस इलाके में बड़े पैमाने पर पुलिस बल भेजे ताकि बाहरी दुनिया को यह दिखलाया जा सके कि यहां पर मतदान सम्पन्न हुआ है तथा 'जनवाद' सफल रहा है।

डौला इलाके में ...

इस इलाके में चुनाव बहिष्कार प्रचार अभियान व्यापक स्तर पर किया गया। जन संगठनों और पार्टी इकाइयों ने सक्रिय रूप से भाग लेते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाया। 9 जगहों पर बड़ी आमसभाएं हुईं। इन तमाम सभाओं में कुल 1,100 लोगों ने भाग लिया। इसके अलावा वयानार, डंडावन, वेडमकोट और कडियानार – इन चार गांव में लगने वाले हाट बाजारों में भी चुनाव बहिष्कार सभाएं आयोजित की गईं। इनमें कुल 3,000 लोगों ने भाग लिया। जन संगठन कार्यकर्ताओं के लिए राजनीतिक कक्षाएं आयोजित करके उन्हें चुनावों पर पार्टी की समझदारी से अवगत करवाया गया। इसके साथ जन मिलिशिया को फौजी प्रशिक्षण भी दिया गया ताकि शत्रु बलों द्वारा अमल दमन का मुकाबला किया जा सके।

दमन

मातला में एक, इन्नर में दो, मादोडा में एक और मढोनार में दो संगठन कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पर इन गांवों में केएएमएस की अगुवाई में महिलाओं ने पुलिस का मुकाबला कर उन्हें छुड़वा लिया। इसके अलावा, मातला गांव में पुलिस ने दो छोटे बच्चों को भी गिरफ्तार किया। उन्हें खूब यातनाएं देकर बाद में छोड़ दिया।

जन प्रतिरोध

इस इलाके में पुलिस दमन के खिलाफ जनता, मुख्य रूप से महिलाओं ने बड़े पैमाने पर प्रतिरोध खड़ा किया। चार गांवों में पुलिस ने संगठन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया तो महिलाओं ने पुलिस के खिलाफ खड़ी होकर अपने लोगों को छुड़वा लिया। इसके अलावा जन मिलिशिया और स्थानीय छापामार दस्तों ने कई जगहों पर गोलीबारी करके पुलिस को हैरान-परेशान किया। ★

महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करें !

वोट मांगने आने वाले लुटेरे नेताओं को मार भगाएं !!

13 अक्टूबर को महाराष्ट्र चुनाव सम्पन्न होने वाले हैं। पिछले 5 सालों से सत्ता में रहे कांग्रेस-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) गठबन्धन, जो हाल में हुए 14वीं लोकसभा चुनावों में थोड़ी सी बढ़त मिलने से काफी खुश है, यह कोशिश में है कि किसी भी तरह फिर से सत्ता पर काबिज हो जाए। दूसरी ओर कट्टर हिन्दू फासीवादी शिवसेना और भाजपा सरकार की पिछले पांच सालों की नाकामियों को ही अपना जादुई हथियार बनाकर गद्दी छीनने के लिए आक्रामक मुकाबला कर रही हैं। बाकी पार्टियों में से कुछ तो इन दो गठबन्धनों में से किसी एक के साथ गठजोड़ करके चन्द सीटें हासिल करने की कोशिश में हैं, जबकि अन्य पार्टियां स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़कर कुछ सीटें हासिल करने की कोशिश में लगी हुई हैं ताकि वे नतीजों के निकलने के बाद बनने वाले संतुलन को प्रभावित करने की स्थिति में पहुंच सकें। गौरतलब है कि संप्रग की घटक लोक जनशक्ति पार्टी महाराष्ट्र में अलग से चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा बीएसपी, आरपीआइ, जस्टिस पार्टी आदि अलग से ही चुनावी दंगल में उतर चुकी हैं। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा को होने वाले इन चुनावों में सभी पार्टियां और गठबन्धन एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप करने में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ आम जनता को इन चुनावों मे कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि वह मान रही है कि चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में आए पर उसे कुछ नहीं मिलने वाला है।

जहां एक तरफ चुनावों पर से परदा उठ रहा था, वहीं दूसरी तरफ राज्य में, मुख्य रूप से मेलघाट इलाके में कुपोषण की मौतें और खासकर विदर्भ इलाके में किसानों की आत्महत्या की घटनाओं में आई वृद्धि दो बड़ी समस्याओं के रूप में सामने आई हैं। एक ओर ये समस्याएं सत्ता पक्ष को झकझोर रही हैं, तो दूसरी तरफ सेना-भाजपा गठबन्धन खुश है कि यही समस्याएं उसे सत्ता की कुर्सी के करीब ला देंगी। दोनों पक्ष इन दोनों समस्याओं पर आपसी आलचोना करते हुए जनता को रिझाने की जी-तोड़ कोशिश कर रहे हैं। आन्ध्र के चुनावों में जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस द्वारा किसानों को मुफ्त बिजली दिए जाने को ध्यान में रखते हुए शिवसेना ने यह सोचते हुए कि वह महाराष्ट्र में भी उसी वादे से जनता को अपनी तरफ रिझा सकती है, पहले ही मुफ्त बिजली को अपने चुनावी घोषणा-पत्र में शामिल कर सबको हैरान में डाल दिया। लोकसभा चुनावों में घोर पराजय के बाद संघ गिरोह द्वारा उग्र हिन्दुत्व की नीतियों की ओर पलटने का फैसला लिए जाने के बाद, महाराष्ट्र में सेना-भाजपा गठबन्धन हिन्दू फासीवादी नीतियों पर हिंसात्मक तरीके से अमल करते हुए दूसरी तरफ विकास के मुद्दे को भी बिना रुके उछाल रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस खुद को मुसलमानों और दलितों का बन्धु बताते हुए उनके वोट बैंक लूटने की पुरजोर कोशिश कर रही है।

महाराष्ट्र में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 9,000 बच्चे कुपोषण से मारे गए। यह मुद्दा सुर्खियों में तब आया जब पिछले जुलाई में अमरावती जिले के मेलघाट इलाके में कुपोषण से 72 बच्चों के मारे जाने की खबर मिली थी। (इस जिले के धारणी और चिखलदरा तहसीलों के इलाके को मेलघाट कहा जाता है।) विडम्बना देखिए, जहां एक तरफ देश के सरकारी गोदामों में खाने के अनाज सड़ रहे हैं और उन्हें चूहे खा जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ घने जंगलों से भरे इस इलाके में जी रहे कोरकू आदिवासी एक जून की रोटी के लिए मोहताज हैं। अमरावती के साथ-साथ चन्द्रपुर, नागपुर, भण्डारा, यवतमाल और गड़चिरोली जिलों की जनता, खासकर आदिवासी जनता सूखे और अकाल के चलते भुखमरी और कुपोषण की शिकार हो रही है। ये सभी जिले विदर्भ के तहत आते हैं। अनमोल सम्पदाओं से समृद्ध विदर्भ की धरती पर आज घोर गरीबी, बीमारी, भूख और सूखे का ताण्डव मचा हुआ है। हालांकि इस इलाके में निक्षिप्त बेशकीमती वन व खनिज संपदा से सरकार को हजारों करोड़ों रुपए का राजस्व मिल रहा है, लेकिन सरकार ने इस इलाके के विकास पर कोई खास खर्च नहीं किया।

फिलहाल विदर्भ इलाके में आए दिन किसी न किसी कोने से किसानों की आत्महत्या की खबरें आ रही हैं। अखबारों ने लिखा है कि इस साल की शुरूआत से अगस्त माह तक विदर्भ में 225 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। इनमें ज्यादातर कपास उगाने वाले किसान थे। टेर्मिनेटर व वेर्मिनेटर बीज बेचने वाली बदनाम मन्सान्टो कम्पनी द्वारा जारी किया गया 'बिनौला' किस्म का बीज किसानों के लिए अभिशाप बन गया। नकली बीज, मिलावटी कीटनाशक दवाएं, चक्रब्याजी कर्ज, बिजली की आपूर्ति में कटौती, बिजली की दरों में बढ़ोत्तरी, सिंचाई सुविधाओं का अभाव, फसलों को समर्थन मूल्यों का अभाव, नौकरशाह बैंक अधिकारियों का जुल्म – इन तमाम कारणों से किसान खुदकुशी करने पर मजबूर हो रहे हैं। महाराष्ट्र में कुल खेत-जमीन में 15 फीसदी को ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। जबकि देश का औसत 32.9 फीसदी है। विदर्भ इलाके में तो स्थिति और भी बदतर है। एक तरफ इन गंभीर मुश्किलों से तंग आकर किसान हताशा में अपनी जान लेने पर तुले हुए हैं, तो दूसरी तरफ प्रदेश के कृषि मंत्री गोविंदराव अदिक के बयान ने जैसे जले पर नमक छिड़क दिया। उनका कहना था, "किसानों की आत्महत्याओं का एक कारण यह है कि उनमें से कुछ लोग शराब के आदी हैं। कुछ धोखेबाज भी हैं जो अपने परिवार को मुआवजा मिलने के लालच में खुद की जान ले रहे हैं।" इस टिप्पणी से इस समस्या के प्रति सरकार का असंवेदनशील रवैया स्पष्ट हो जाता है। दूसरी ओर समस्या की तीव्रता को पहचानते हुए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों भी इस होड़ में है कि किसानों को रिझा लिया जाए। कई वायदे करते हुए उन्हें सब्ज बाग दिखा रहे हैं। किसानों के कर्जों की माफी, मुफ्त बिजली, धान उगाने वाले किसानों को 20 करोड़ रुपए की

(शेष पृष्ठ 46 पर ....)